चैत्र-वैशाख २०५८ अप्रैल २००१

स्वदेशी

राष्ट्रीय स्वाभिमान, आर्थिक स्वावलंबन, राष्ट्रीय पुनर्रचना तथा स्वदेशी संदेश की संवाहिका पत्रिका

अमीरों को साथ और गरीबों को लात

• मुकुन्द गोरे

क्या हश्र होगा इस सुधारवादी बजट का

• अवधेश कुमार

Scanned with OKEN Scanner

श्रीधर की स्वदेशी कुण्डलियाँ

एक

बजट-खटाई

धर लेगा मधुमेह देश को, क्यों बाटेंगे मिठाई ।
जनता बने अचार इसलिए, बना बजट खटाई ।।
बना बजट खटाई कि सेठों की भूख बढ़े ।
पचे उन्हें पूँजी प्रचूर चर्बी और चढ़े ।।
खरचा देंगे सेठ, राज है नेता जी को करना ।
रोएँ श्रमिक-किसान, करें रैली अनशन धरना ।।

दो

मात्रात्मक प्रतिबंध हटाओ

विदेशी मुद्रा से फटा जा रहा जब स्टॉक तुम्हारा ।
बोला अमेरिका भारत से तू सहलो भार हमारा ।।
तू सह लो भार हमारा मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाओ ।
होकर सुलभ बाजार हमें लाभ की शहद चटाओ ।।
इस फिक्सिंग को देख रो उठे उत्पादक सब देशी ।
भारत अब चारागाह बनेगा चरेंगे चतुर मवेशी ।।

तीन

मानव का अंग बिकेगा

बन्द करो सार्वजनिक उपक्रम होता घाटा भारी ।
बता रहा है विश्व बैंक तो है सहमति सरकारी ।।
है सहमति सरकारी देश में उपजे खूब बेकारी ।
भीख माँगते मरें देश के अब लाखों नर-नारी ।।
होगी जनसंख्या कंट्रोल मानव का अंग बिकेगा ।
फिर क्यों ना यह देश भूमंडल पर श्रेष्ठ दिखेगा ।।

चार

आपस में हाथ मिलाओ

हतो न अपनी जान किसानो, समय संगठन का आया
हुआ संगठित जन-जन जब-जब, शत्रु का बल थर्राया है
शत्रु का बल थर्राया है, गौरव-गाथा याद करो
ओ अमृत की संतानो, तू ही विजयी हो धैर्य धरो
बाँटों सुख-दुःख आपस में, मिल-जुल संग-साथ निभा
कट जाएगी रात अँधेरी, आपस में हाथ मिलाओ

☹☹☹

Scanned with OKEN Scanner

अपनी वार्ता

प्रिय पाठक बन्धु,

बजट की प्रशंसा या आलोचना शब्दों में की जाए, इस कार्य की समय सीमा समाप्त हो गई है। अब तो बजट की सही समीक्षा परिणामों में प्रकट होने लगी है। देश के हित को सर्वोपरि मानने वाले संगठन सरकारी नीतियों का खुलकर विरोध करने लगे है। भारतीय मजदूर संघ अपनी ९६वीं बैठक में घोषणा कर चुका है कि १६ अप्रैल, २००१ को संसद के समक्ष एक लाख से अधिक मजदूरों का प्रदर्शन करेगा। जहाँ-तहाँ किसानों की आत्महत्या और उनका विद्रोह एक साथ सामने आ रहा है – यह लक्षण जन-आंदोलन का है।

आपके लिए स्वदेशी पत्रिका इस अंक में बजट के अतिरिक्त अन्य स्पर्शी विषयों को अपने ढंग से प्रस्तुत कर रही है। आशा है आप इनसे प्रेरित होंगे।

नमस्कार।

आपका
प्रमोदकुमार दुबे

अनुक्रम

अग्रलेख
अमीरों को साथ और गरीबों को लात
मुकुन्द गोरे........................../७

क्या हश्र होगा इस सुधारवादी बजट का
अवधेश कुमार......................../१३

वैश्वीकरण का हितैषी बजट
विद्यानंद आचार्य......................../१७

दृष्टिकोण
स्वदेशी की कसौटी पर खरा नहीं है बजट २००१-२००२
डॉ. अश्विनी महाजन................../२२

लेख
गरीबी का नियंत्रण नहीं, निवारण चाहिए
डॉ. भरत झुनझुनवाला................/२६

संस्कृति
आज सम्राट अशोक जीवित होते तो . . . .
डॉ. प्रमोदकुमार दुबे................../२९

माध्यम
हॉलीवुड निगलना चाहता है सांस्कृतिक विविधता
भोगेन्द्र पाठक......................../३३

कोयला में है तेल संकट का समाधान
धीप्रज्ञ द्विवेदी........................../३५

स्तंभ
खेत की मेंड़ से/६, हलचल/४३, समाचार परिक्रमा/४७

संपादकीय कार्यालय : ६०, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-११० ००१ ● दूरभाष : ३०१८१७५
ई-मेल : swadeshisampark@rediffmail.com

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष-६, अंक-७

चैत्र-वैशाख २०५८, अप्रैल, २००१

:: अमर वाणी ::

येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः।
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥

जिस मन द्वारा कर्म के जानने वाले धीर पुरुष यज्ञ अर्थात् धर्म-व्यवहार में कामों को करते हैं और जो प्राणियों के भीतर और पूजनीय है, वह मेरा मन शुभ विचार वाला हो।

• • •

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु

जो मन ज्ञान का उत्पादक, स्मरणशक्ति और साधारण शक्ति का आधार है, जो जीती-जागती ज्योति प्राणियों के भीतर है, जिसके बिना कुछ भी काम नहीं किया जाता, वह मेरा मन शुभ विचार वाला हो।

(भक्ति दर्पण)

मुख्य संपादक :
डॉ. महेश चंद्र शर्मा
कार्यकारी संपादक :
डॉ. प्रमोदकुमार दुबे

मूल्य : एक अंक – ६ रुपए
वार्षिक सदस्यता शुल्क – ६० रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क – १०००/-

विशेष सूचना : अपनी सदस्यता सूची एवं सदस्यता फार्म कृपया अपना नाम व पता, पिनकोड सहित साफ-साफ शब्दों में लिखकर भेजें।

Scanned with OKEN Scanner

पाठकनामा

खेती और लघु उद्योगों पर आधारित है भारत की अर्थव्यवस्था

संपादक जी,

पत्रिका का अंक काफी अच्छा लगा। यह सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि भारत की आर्थिक स्थिति खेती और लघु उद्योगों पर आधारित है। सरकार समझकर भी नासमझ बन बैठी है।

प्रदूषण के नाम पर हम बेरोजगारी को बढ़ावा नहीं दे सकते न ही अर्थव्यवस्था को नष्ट कर सकते आवश्यकता है ऐसी नीति की जो पर्यावरण एवं जनता दोनों के हितों की सुरक्षा कर सकें। केन्द्र और राज्य सरकारों की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

डा. एस. के. शर्मा
शालीमार बाग, नयी दिल्ली

'वेलेंटाइन डे' के बदले कौमुदी महोत्सव

संपादक महोदय,

स्वदेशी की कसौटी पर बजट पूर्व समीक्षा करते हुए लेखक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऋषि वचनों को एक बार फिर याद दिलाकर देश की आर्थिक नीतियों को उचित दिशा देने में सहायता की। इसके लिए स्वदेशी पत्रिका को धन्यवाद। पत्रिका में 'वेलेंटाइन डे' के बदले कौमुदी महोत्सव का विकल्प पढ़कर प्राचीन भारत का गौरवशाली इतिहास हमारी विकसित संस्कृति की याद दिलाती है। निश्चय ही भारत अपने मूलस्वरूप में पश्चिमी देशों का गुरु रहा है।

सुहासिनी भट्टाचार्य
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

पश्चिम की गिद्ध दृष्टि

संपादक जी,

स्वदेशी पत्रिका का मैं नित्य पाठक हूँ। मार्च अंक में भारत के प्राचीन ग्रंथों में भूकंप के बारे में गहरी जानकारी दी गई थी। इस विषय में डॉ. प्रकाश पाण्डेय का लेख संग्रहणीय और विद्वतापूर्ण लगा। इस तरह के लेख जो प्राचीन भारतीय विज्ञान की जानकारी दें, उसे अवश्य प्रकाशित करें। आज प्राचीन भारतीय विद्याओं – आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष आदि पर पश्चिमी देशों की ललचायी नजर लगी हुई है। हमें ज्ञान की अपनी थाती को फिर से सहजकर उसे विकास का आधार बनाना जरूरी है। दूसरे देशों की खोजों पर हम अपने विकास की नींव नहीं रख सकते। अगर रखने का प्रयास करते है तो हमारा विकास दूसरे दर्जे का होगा और हम उनके ऋण से दबे रहेंगे।

चौधरी मौजीराम
हिसार, हरियाणा।

उन्होंने कहा

बाजारवाद ने देश को भंवर जाल [illegible]
उलझाया।

गोविंदाचा[illegible]

बजट ने कर घटाकर मैं उपभोक्ता मां[illegible]
में वृद्धि का प्रयास कर रहा हूँ क[illegible]
ब्याज दरे और ऊपर ढाँचे को प्रोत्साह[illegible]
देने जैसे कदमों के जरिए मुझे ज्याद[illegible]
निवेश की उम्मीद है।

यशवंत सिन्[illegible]

आरक्षण (मात्रात्मक प्रतिबंध) खत[illegible]
करने से तालाबंदी एवं बेरोजगारी होगी

आल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्[illegible]
विजय कालंत[illegible]

भूकंप के बाद आर.एस.एस. एवं विहि[illegible]
ने हमारी खुलकर मदद की।

कांग्रेस ने[illegible]
छगनभाई खोल[illegible]

अपने राष्ट्र में स्वीकार्यता दुनिया के[illegible]
किसी भी सम्मान से बढ़कर है।

डॉ. चितरंजन एस. रानाव[illegible]

भारत का एक प्रमुख आर्थिक ताकत के
रूप में उभर रहा है।

पूर्व अमरीकी राजदूत एवं वर्तमान [illegible]
यूएस-इंडिया बिजनेस कांउसिल के चेयर[illegible]
फ्रैंक वाइजन[illegible]

ज्यादातर महत्वपूर्ण बहुत कम कीमत प[illegible]
भी उपलब्ध हो सकती है।

मैनेजिंग डायरेक्टर सिप्ला का[illegible]
यूसुफ के. हमीं[illegible]

संपादकीय

अपनी अस्मिता की पहचान ही हमें बचा सकेगी

भारत सरकार ने मई, १९९७ में जब इन्द्रकुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे और पी. चिदम्बरम वित्तमंत्री– घोषणा की थी कि वह नौ वर्षों में मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाएगी। लेकिन यह समय सीमा घटती चली गई, पंहले यह ७ वर्ष की हुई, इसके बाद ६ वर्ष पर आई, फिर यह और कम होती गई, ऐसा क्यों? अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में यह सवाल उठाया कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। इसे दी जानेवाली समय-सीमा घटायी जानी चाहिए और भारत ने भी स्वीकारा कि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं है, वह समय सीमा घटा सकता है। क्या यही आत्मरक्षा की रणनीति है? आक्रमण करनेवाले तो हमेशा विजयी होने के लिए आरोप गढ़ेंगे। विदेशी दवा कम्पनियों ने भारत, ब्राजिल और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के न्यायालय में कभी इसकी गुहार भी लगाई थी कि इन देशों के नियम दवाओं की बिक्री के लिए लाभकारी नहीं हैं। यह उचित नहीं है– जहाँ दूसरे देशों में एचआईवी एड्स चिकित्सा व्यय एक वर्ष में १५००० डॉलर है, भारत और ब्राजिल में यही चिकित्सा व्यय केवल २५० से ३०० डॉलर तक है। क्या इस शिकायत से दवा कम्पनियों को लाभ पहुँचाने के प्रयास में देशवासियों का अहित किया जाना उचित होगा? इस प्रकार के अनेक सवाल जिसका भारत जैसे धर्माश्रित संरचना के देश से दूर-दूर तक सम्बन्ध नहीं है, अब टकराएँगे और सबल रणनीति के अभाव में भारत पीछे हटता जाएगा जिसके दुष्परिणामों की कल्पना भी अत्यन्त दुखद है।

एक अप्रैल २००१ से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने का दूसरा चरण लागू हो रहा है। इसमें केवल ४५ वस्तुओं को छोड़कर अन्य ७१५ वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। इस प्रकार अब प्रथम चरण के ७१४ वस्तुओं को मिलाकर १४२९ वस्तुएँ मात्रात्मक प्रतिबंध से मुक्त हो रही हैं। देश में इसका प्रत्यक्ष दृश्य सामने आएगा। इसके साथ ही दूसरे संकट भी छाएँगे। इनके मनोवैज्ञानिक दबाव सामाजिक विकृतियों के कारण बनेंगे। सबल अर्थव्यवस्था का आरोप भारत पर कैसे लगा? बजट का रुख जनतांत्रिक चरित्र से विचलित होकर पूँजीवादी अर्थाश्रित व्यवस्था की ओर है। आर्थिक लोकतंत्र का स्वप्न देखना कठिन हो रहा है।

मजदूर और किसान राष्ट्रव्यापी आन्दोलन पर उतर रहे हैं, इस माँग के साथ कि भारत विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकले। केन्द्र सरकार राज्यों के वाणिज्य सचिवों की बैठक बुलाकर मात्रात्मक प्रतिबन्ध के हटने के बाद की कठिनाइयों पर विचार कर चुकी है। विदेशी उत्पादों का बाजार बनने के खतरों को आयात शुल्क बढ़ाकर, घरेलू उत्पादों पर लगनेवाले करों को कम से कम करके प्रतियोगी मूल्यों के निर्धारण से– कम किया जा सकता है। इस दिशा में भी आवाजें उठ रही हैं; सरकार भी जागरूकता दिखा रही है। लेकिन यह युद्ध सिर्फ उद्योग, सरकारी नियम और कामगार लोगों तक ही लड़ा जाना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए हमें भारत की संस्कृति, परंपरा, प्रचलन, विश्वास और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी चारों ओर से मोर्चे खोलने होंगे। यह भी मुद्दा हो सकता है कि उन्हीं कारों को आयात किया जाए जो सिर्फ दायीं ओर चलती हों, ऐसे भोज्य पदार्थ बाजार में न बिकें जो हमारी मान्यताओं के विपरीत हों। जब झटके और हलाल का फर्क भी माँस की बिक्री को प्रभावित करता है तो सालों पुरानी फ्रीज की हुई मुर्गों की टाँग अमेरिका से आकर भारत में क्यों बिकेगी? इसी प्रकार खाद्य तेल, अनाज और प्रसाधन के सामान भी हैं जिनकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। जीन सम्वर्द्धित अन्न, सब्जी, फल के दुष्प्रभाव विकसित देशों के उपभोक्ताओं के जीवन पर पड़ रहा है। उनके यहाँ हर तरह के असमय में हो रहे विकासों की विकृतियाँ समाज को नष्ट करने पर तुली हुई हैं। ये विकृतियाँ हम क्यों मोल लें। हमारे वैज्ञानिकों को उत्साह में आकर विदेशियों का पिछलग्गु बनना अनुचित होगा।

आज भारत को अपनी अस्मिता को पहचानने का समय आ चुका है। यही एक पहचान हमें बचा पाएगी। इसी समर में हमारा वास्तविक अर्थशास्त्र विकसित हो सकता है, सच्चे विकास का मार्ग बन सकता है, धर्म द्वारा निर्धारित जीवन मूल्यों की प्रासंगिकता समझ में आ सकती है। जिन्हें जीवन की निरंतरता चाहिए उन्हें संयम की राह उचित लगेगा ही; पर जिन्हें तत्कालिक लोभ-लाभ से भोगवादी जीवन का अन्त रूचिकर है उनकी आपत्तियाँ संयम के विरुद्ध हो सकती है। आनेवाले घमासान समर में चरित्र खुलेंगे तो वर्गीकरण भी आसान हो जाएगा। डूबनेवाले बड़े चरित्र का तमगा नहीं पहन लें, उन्हें पुरस्कार देकर कीर्ति-पुरुष न घोषित किया जाए, इसके लिए समाज का विवेक सजग रहे और चरित्र को ध्वस्त बनानेवाली गरीबी-मजबूरी के षड्यन्त्र रचने वाले हाथ मजबूत न हों तो सादगी का अमृत समाज को इस धुँध से निकाल सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

आन्दोलन के लिए विवश कर दिए गए राजस्थान के किसान

आज किसानों की सबल पक्षधरता देश में आवश्यक हो गई है। देश का अधिकतम जनसंख्या इन्हीं किसानों की है इसीलिए भारत का नैतिक चरित्र अभी भी बना हुआ है। आज सरकारी नीति भूमंडलीकरण के भ्रम में पड़कर भारत का अस्तित्व डुबा देने पर तुली है सौंदर्यीकरण के आगे श्रम और उत्पादन का क्षेत्र उपेक्षित होता जा रहा है

कितनी बेखबर है राजस्थान की वर्तमान सरकार कि उसे अपने प्रान्त के गाँवों की बदहाली की जानकारी तक नहीं और उसने उद्योग जगत को राहत पहुँचाने के साथ अभी कृषि और घरेलू उपयोग की बिजली की दरों में वृद्धि की है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर के विद्युत निगमों के प्रस्तावों पर सुनवाई करने के बाद दरों में १६.७६ प्रतिशत तक वृद्धि की स्वीकृति दी है। एक अप्रैल से लागू होनेवाली ये दरें औद्योगिक क्षेत्रों पर नहीं; बल्कि किसानों पर भारी पड़ेंगी। अब किसानों को ७० पैसे प्रति यूनिट के बदले ९० पैसे प्रति यूनिट बिजली का मूल्य देना होगा।

भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रांत के महामंत्री रामपाल सिंह चौधरी ने घोषणा की थी कि यदि बिजली की दरें बढ़ाई गई तो ग्राम बन्द आन्दोलन शुरू होगा जो वास्तव में राजस्थान-बन्द शब्द को सार्थक करेगा। सरकार विद्युत नियामक आयोग द्वारा अब वह कार्य करा चुकी है जिसकी आशंका भारतीय किसान संघ, राजस्थान को थी। इसका मतलब हुआ कि बाध्य होकर राजस्थान के किसानों को आन्दोलन के लिए आगे आना ही होगा।

राजस्थान के ग्रामीणों की बड़ी समस्या यह है कि प्रांत के सभी गाँवों को अकालग्रस्त घोषित ही नहीं किया है। कुल ४१५२८ गाँवों में से सिर्फ ३०५८५ गाँवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया, जब कि सभी गाँवों की परिस्थिति समान है। यहाँ पीने तक के पानी का भारी संकट है। एक लाख से अधिक कुँओं में से ७५ प्रतिशत कुँए सूख गए हैं। हैंडपम्पों के सूख जाने की प्रतिशत भी यही है। यहाँ की बारहमासी नदियाँ– बनास, चम्बल की स्थिति सर्दी में भी जेठ मास के दिनों जैसी रही। भरतपुर के डाँग और कुम्हेर तहसील में एक मटके पानी का मूल्य ८ रुपये है। स्वयं राज्य सरकार की जानकारी में भी २४१०५ कुँए सूखे पड़े हैं।

खेती की दशा भी चिन्ताजनक है। इस वर्ष सिंचाई के अभाव में ६५ प्रतिशत फसलें नष्ट हो गई हैं इसके लिए बिजली की आपूर्ति व नहरों से पानी नहीं मिलना- जिम्मेदार दुर्व्यवस्थाएँ हैं। कृषि क्षेत्र में इस वर्ष १०० अरब रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। दूसरी ओर समर्थन मूल्य नहीं मिलने से बाजरा, सरसों, सोयाबीन, चावल को किसान कम मूल्य में बेचने पर मजबूर हुए, जिससे ३६३ करोड़ की हानि का अनुमान लगाया गया है। अब चारों ओर से समस्याओं से घिरे किसानों पर बिजली की मूल्य वृद्धि का भार भी डाल दिया गया है।

भारतीय मजदूर संघ राजस्थान ने मुख्यमंत्री को विधानसभा पर प्रदर्शन करने के पहले दी गई लिखित चेतावनी में कहा है कि आपके शासन में जयपुर के सौंदर्यीकरण पर ८० करोड़ रुपये, नयी विधानसभा भवन के निर्माण में १३३ करोड़ और राजस्थानी सम्मेलन में करोड़ रुपये खर्च करने के लिए पैसे हैं किन्तु किसानों की फसल के लिए बिजली, सिंचाई व गाँवों में पीने

के पानी और पशुओं के लिए चारे के
हैं। शहरी क्षेत्रों में बिजली आवश्यकता से
व्यय हो रही है। फसल उत्पादन के लिए
की निर्धारित आठ घंटे की अवधि पूरी
पाती, इसके लिए बिजली की कमी का
जाता है। सौंदर्यीकरण हो या उत्पादन?
संघ का यह निर्णय है कि राजस्थान के
एवं २२९ तहसीलों के किसान आग
अप्रैल २००१ को विधान सभा पर प्रदर्श
प्रदेश के किसान राजनैतिक दलों की
भाँति बिना किराया दिए नहीं, वरन्
अपने खून-पसीने की गाढ़ी कमाई में से
पेट काटकर किराया चुका, जयपुर पहुँ
इस भयंकर अकाल में १ रुपए का खर्च
रुपए के बराबर अखरेगा। आशा है
नैतिकता आधारित जीवनचर्या वाले किस
प्रदर्शन के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
किसान संघ ने विश्व व्यापार संगठन के
हटाये जा रहे मात्रात्मक प्रतिबन्ध के दोनों
को उल्लखे किया है और उससे पैदा होने
संकटों की चर्चा करते हुए माँग की है कि
व्यापार संगठन के पूँजीवाद आधारित
व्यवस्था के जहर के फैलने से पहले इस
संगठन से भारत को बाहर आ जाना चाहि
ज्ञापन में बिजली, ऊर्जा संकट, पानी,
राजस्व कानून, सहकारी समिति और पशु
संवर्द्धन के साथ कृषक साथी योजना को
सुविधाजनक बनाने के मुद्दे उठाए गए हैं

आज किसानों की सबल पक्षधरता
आवश्यक हो गई है। देश का अधि
जनसंख्या इन्हीं किसानों की है इसीलिए
का नैतिक चरित्र अभी भी बना हुआ है।
सरकारी नीति भूमंडलीकरण के भ्रम में
भारत का अस्तित्व डुबा देने पर तुली
सौंदर्यीकरण के आगे श्रम और उत्पादन का
उपेक्षित होता जा रहा है यह रास्ता सम
पतन की ओर ले जानेवाला है। इसके
ये नीतियाँ भारत को पहचान निगल लें
धरती की शक्ति संगठित होकर रण में
लगी हैं।

Scanned with OKEN Scanner

अमीरों को साथ और गरीबों को लात

■मुकुन्द गोरे*

कोई भी एकाध निर्णय उचित है या अनुचित, योग्य है या अयोग्य, बराबर है या गलत, ऐसे भ्रम की स्थिति हो तब क्या करना चाहिए? महात्मा गाँधी कहते हैं, 'ऐसे समय आँखों के सामने एक अति दरिद्र शोषित, पीड़ित दूर के देहात का गिरा एवं कन्दराओं में रहने वाला गरीब वनवासी लाइये और देखिए कि लिए हुए निर्णय के कारण उस दरिद्र मानव का कितने प्रमाण में लाभ होगा; इसके बारे में सोचिए। यदि उसका लाभ होने वाला हो तो आपका निर्णय योग्य है, और यदि उसे कोई भी लाभ न होने वाला हो तो आपका निर्णय गलत है। महात्मा जी के इस निष्कर्ष पर यदि वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा लाए गए बजट का परीक्षण करेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि इस अर्थसंकल्प द्वारा वित्तमंत्री ने अमीरों का साथ दिया है और गरीबों को लात मारी है। यह बजट सीधे-सीधे उच्च अमीर वर्ग के लिए केवल राहत ही नहीं अपितु उनके लिए हर्षदायक है। इसके विपरीत देहाती दरिद्रनारायण का जीवन असहाय होने वाला है। एक तरफ गरीबों के ऊपर अन्याय तो होगा ही दूसरी तरफ यह बजट गैर कानूनी और असंवैधानिक भी है। गत ५० वर्ष में इस प्रकार का अयोग्य बजट भारत की प्रजा सत्ता के इतिहास में प्रथम बार जनता के सामने आया है।

गरीब विरोधी

बजट में कितनी मात्रा में गरीब आदमी के लिए राशि रखी गई है और कितनी मात्रा में अति उच्च वर्ग के ऐश के लिए राशि दी गई है इसके आधार पर यह अर्थसंकल्प गरीबों के पक्ष में है या उनके विरोध में है

*लेखक भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री है

Scanned with OKEN Scanner

वार्षिक वित्तीय विवरण : कुछ प्रमुख शब्दावली

संविधान के अनुच्छेद ११२ के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, जो १ अप्रैल से ३१ मार्च तक होता है, भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। 'वार्षिक वित्तीय विवरण' नामक यह विवरण मुख्य बजट दस्तावेज होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार की प्राप्तियों और अदायगियों को तीन भागों में, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, दिखाया जाता हैं।

समेकित निधि

सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋणों से और उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों से प्राप्त धनराशियाँ 'समेकित निधि' में दिखाई जाती है। सरकार का पूरा खर्च समेकित निधि से किया जाता है और संसद की स्वीकृति के बिना इस निधि में से कोई भी रकम नहीं निकाली जा सकती।

आकस्मिक निधि

कभी-कभी ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब सरकार को संसद की स्वीकृति मिलने के पहले ही अत्यावश्यक अप्रत्याशित खर्च करना पड़ता है। इस तरह का खर्च करने के लिए आकस्मिकता निधि अग्रदाय के रूप में राष्ट्रपति के पास रहती हैं। इस तरह के खर्च और समेकित निधि से उतनी ही रकम की निकासी के लिए बाद में संसद की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है और आकस्मिकता निधि से खर्च की गई धनराशि निधि में वापस डाल दी जाती है। इस समय इस निधि के लिए संसद द्वारा प्राधिकृत कुल राशि ५० करोड़ रुपए हैं।

लोक लेखा

सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अतिरिक्त जिनका संबंध समेकित निधि से होता है सरकारी लेखों में कुछ अन्य लेन-देनो जैसे भविष्य निधियों के संबंध में लेन-देन अल्प बचत संग्रह, अन्य जमा आदि का हिसाब भी रखा जाता है जिनके संबंध में सरकार लगभग

यह तय होता है। इस दृष्टि से २००१ से २००२ के कालखंड के लिए दिनांक २८ फरवरी २००१ को श्री यशवंत सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट का हम विश्लेषण करेंगे।

स्पष्टीकरण

एक महत्वपूर्ण बिन्दु ख्याल में यह रखना है कि आने वाले वर्ष के लिए कितनी राशि रखी गई है, उसकी तुलना गत वर्ष की कीमत बढ़ोत्तरी (मूल्यवृद्धि) को ध्यान में रखकर करना आवश्यक है। गत वर्ष औसत मूल्य वृद्धि ६.६० प्रतिशत थी। (आर्थिक सर्वेक्षण २००१-२००१-पृष्ठ-८५), यानि यदि गत वर्ष किसी मद में एक रुपया खर्च किया गया और आगामी वर्ष के लिए १.०६ रुपये की राशि रखी गई हो तो बजट में रुपयों में बढ़ोत्तरी दिखाई देती है तो भी वह वृद्धि नहीं है, उल्टे कमी ही है। यह बात ध्यान में रखकर ही अर्थ-बजट का विश्लेषण करना आवश्यक है।

भारत की जनसंख्या १०० करोड़ पहुँच चुकी है। १९९९ में भारत में विमान से जिन्होंने प्रवास किए, ऐसे ५७ लाख यात्रियों में १० बार से भी अधिक केवल १० लाख लोगों ने हवाई जहाज से यात्रा की होगी। अर्थात् हवाई जहाज की सेवा प्राप्त कुल जनसंख्या की तुलना में ०.१ प्रतिशत लोगों के ऊपर वित्तमंत्री कितनी राशि खर्च करने के लिए तैयार है, और इसकी तुलना में ७० प्रतिशत जनता जो देहातों में रहती है उनके लिए कितनी राशि खर्च करने के लिए दी गई है? इसे देखना जरूरी है। सारिणी १ में देखें।

सारिणी क्रमांक १ यदि अच्छी तरह से देखेंगे तो ख्याल में आता है कि विमान सेवा पर १९९९-२००० में जो प्रत्यक्ष खर्च हुआ उसकी तुलना में गत वर्ष बहुत अधिक वृद्धि नहीं थी। लेकिन संशोधित अनुमान अनुसार अधिक खर्चा हुआ है और गत व की तुलना में २२ प्रतिशत से अधिक खर्च लिए राशि रखी गई है। इस वर्ष जैसी प्रवृ दिख रही है और इसके लिए जितनी राशि गई है उससे अधिक राशि खर्च होने संभावना है। इसके विपरीत ग्रामीण विका पर १९९९-२००० में जो प्रत्यक्ष खर्च हु उससे भी बहुत कम राशि चालू वित्त वर्ष दी गई और संशोधित अनुमान के अनुस १९९९ की तुलना में यह राशि २० प्रतिश से भी कम है। इसका अर्थ है कि यदि य प्रवृत्ति रही तो जो राशि दी गई है इससे कम खर्च होने की संभावना है।

दूसरे शब्दों में १००० में एक अमी आदमी की जरुरत पूर्ण करने के लि वित्तमंत्री जो राशि बढ़ाते हैं, व्यवहार में उस भी अधिक खर्च होता है। इसके विरोध १०० में से ७० प्रतिशत लोगों के लिए रा बढ़ाने की बात तो दूर उल्टे कम की जा है, और वास्तविक खर्च उससे भी कम हो है। आंकड़ों में यदि कहना हो तो बजट में ए गरीब के लिए वर्ष में ६३ रुपये की व्यवस है और एक अमीर को सुविधाजनक प्रवा के लिए २२१० रुपये की राशि की व्यवस है।

शहर और गाँव में भेदभाव

निम्न सारिणी-२ को देखिये।

सारिणी - २

(आंकड़े करोड़ रुपये मे

मद	प्रत्यक्ष खर्च १९९९-२०००	आगामी रा २००१-२००
शहरी विकास	११.७२	२४.२३
ग्रामीण रोजगार	३७२७.३०	२१२१.६४

सारिणी क्रमांक १

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

मद का नाम	प्रत्यग बजट १९९९-२०००	संशोधित २०००=२००१	आगामी वर्ष के लिए २०००-२००१	२००१-२००२
नागर विमानन सेवा	१७०.३०	१७८.९९	२०२.७७	२२०.१३
ग्रामीण विकास	५१२३.६५	४५४७.१४	४१०५.८०	४३७९.४४

सारिणी क्रमांक ३

(आंकड़े करोड़ रु. में)

मद का नाम	प्रत्यक्ष बजट १९९९-२०००	संशोधित २०००-२००१	आगामी वर्ष के लिए २०००-२००१	२००१-२००२
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति	८.८९	१०.१४	९.८७	१०.२९
सांसद	१३०.७०	१६३.०९	१८२.६७	१९४.८९
मंत्रीगण	४१.२१	६७.१७	७८.८८	९१.५२

उपर्युक्त सारिणी-२ से यह स्पष्ट होता है कि शहरी विकास पर प्रत्यक्ष खर्च की तुलना में दुगुनी से भी अधिक राशि की व्यवस्था आनेवाले वर्षों के लिए की गई है। इसके विरोध में ग्रामीण रोजगार पर गत वर्ष जितना खर्चा हुआ उससे २० प्रतिशत कम राशि रखी गई है। यदि मूल्य वृद्धि की दर ध्यान में रखेंगे तो ग्रामीण विकास पर ३० प्रतिशत से भी कम राशि रखी गई है। महात्मा गाँधी जी का कहना था कि ग्राम विकास एवं ग्रामीण रोजगार को प्रधानता देनी चाहिए लेकिन वित्तमंत्री पाश्चिमात्यों का मार्ग अपनाते हुए भारत का विकास करना चाहते हैं।

रोजगार निर्माण में अवरोध

जिसके कारण रोजगार बढ़ता है और रोजगार बढ़ने की गति भी बढ़ती है, ऐसा विषय यानि आवास निर्माण करना। इस दृष्टि से आवास निर्माण पर अधिक राशि रखना जरूरी है। लेकिन वित्तमंत्री क्या चाहते हैं इसके लिए तुलनात्मक विश्लेषण करना होगा। १९९९-२००० में प्रत्यक्ष खर्च रु. १७७८.४१ करोड़ हुआ। लेकिन संशोधित रुपये १५२७.४० करोड़ की दिखाई गई है और आने वाले वर्ष के लिए दिखाई हुई राशि १७०६.३४ करोड़ है।

यानि जहाँ रोजगार निर्माण की संभावना है ऐसे आवास निर्माण क्षेत्र पर १२ प्रतिशत कम राशि देना और जहाँ रोजगार निर्माण कतिपय संभव नहीं ऐसे वैदेशिक कार्य कार्य पर ४० प्रतिशत से ज्यादा राशि की व्यवस्था करना यह क्या दिखाता है?

गरीबों के लिए कटौती एवं स्वयं पर बढ़ोत्तरी

केन्द्र सरकार को अपने खर्च में बड़ी मात्रा में कटौती करनी चाहिए और घाटा वित्त कम करना चाहिए। इसलिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सरकार पर दबाव ला रही है। ऐसा होना भी आवश्यक है। लेकिन दुर्दैव से सरकार ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार, आवास निर्माण आदि विषय पर होने वाले खर्चों में कटौती कर रही है जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है। लेकिन सरकार स्वयं पर यानि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद तथा मंत्रीगण आदि विषयों पर बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा बढ़ा रही है। सारिणी क्रमांक-३ देखिए।

सारिणी क्रमांक ३ से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सांसद लोग स्वयं के खर्चे में कटौती के लिए तैयार नहीं है किन्तु इस वर्ष जितनी राशि की व्यवस्था की थी उससे भी संशोधित खर्च ज्यादा दिखाई देता हैं और आनेवाले वर्ष में उसमें भी वृद्धि की गई है। केवल मंत्रीगणों ने अपने खर्चे में २२० प्रतिशत की वृद्धि की है। जिस देश में गरीबी रेखा के नीचे करोड़ों लोग गुजर-बसर करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पर २५ रुपये भी खर्च नहीं कर सकते हैं। ऐसे देश के सांसद स्वयं पर हर रोज २५०० रुपये खर्च कर रहे है। मंत्री स्वयं पर प्रतिदिन २५००० रुपये खर्च करने को तैयार हैं। लेकिन सरकार का खर्चा कम हो इसलिए स्वयं के खर्चे में कटौती न करके सरकारी नौकरी में १० प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया है। यह साजिश है रोजगार निर्माण के नाम पर रोजगार कटौती का।

ब्याज दर में कमी : निम्न मध्यम वर्ग पर आघात

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समानता लाने की दृष्टि से बैंकों के ब्याज दरों में वित्तमंत्री ने

वार्षिक वित्तीय विवरण ....

एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। इस तरह जो रकमें प्राप्त होती है उन्हें लोक लेखे में दिखाया जाता है। और संबंधित संवितरण भी इसी में से किया जाता है। आमतौर से लोक लेखो विधियाँ सरकार की नहीं होती। क्योंकि इस धनराशि को किसी न किसी समय उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों को जो इसे जमा कराते हैं वापस देना होता है। इसलिए लोक लेखे से अदायगी करने के लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता। कुछ मामलों में सरकार की आय का कुछ भाग, खास-खास कार्यों के लिए, जैसे – चीनी विकास के लिए या वाणिज्यिक उपक्रमों में जो मशीनरी आदि पुरानी पड़ गई हो उसके स्थान पर नई मशीनरी लाने आदि के लिए अलग-अलग निधियों में अलग निकाल कर रख लिया जाता है। यह रकम संसद की स्वीकृति लेकर समेकित निधि से निकाली जाती है और विशेष कार्यों पर खर्च किए जाने के लिए लोक लेखा में जमा रखी जाती है। फिर भी कार्य विशेष पर जो खर्च किया जाता है उसे संसद के सम्मुख उसकी स्वीकृति के लिए फिर प्रस्तुत किया जाता है हालाँकि यह रकम निधियों को अंतरित किए जाने के लिए पहले ही संसद द्वारा निर्धारित की हुई होती है।

राजस्व बजट

राजस्व बजट में सरकार को राजस्व (कर-स्वराज और अन्य राजस्व) से होने वाली आय तथा इन राजस्वों से किया जाने वाला व्यय शामिल होता है। कर-राजस्व में संघ द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियाँ शामिल होती हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में वित्त विधेयक में किए गए कराधान संबंधी प्रस्तावों का प्रभाव शामिल होता है। सरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्यत: उसके द्वारा निवेशित पूँजी ब्याज और लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियाँ शामिल होती हैं। राजस्व व्यय सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज प्रकारों आर्थिक सहायता आदि पर होता है। मोटे तौर पर ऐसा

Scanned with OKEN Scanner

वार्षिक वित्तीय विवरण ....

व्यय जिसमें किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय माना जाता है। राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए जाने वाले सभी अनुदान भी राजस्व व्यय माने जाते है। यद्यपि ऐसे कुछ अनुदान परिसंपत्ति के सृजन के लिए हो सकते हैं।

पूँजी बजट

पूँजी बजट में पूँजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान शामिल है। पूँजीगत प्राप्त्यों की मुख्य मदें ये हैं – सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है, राजकोषीय हुंडियों की बिक्री के जरिए सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और अन्य पक्षों से लिए जाने वाले ऋण विदेशी सरकारों और संस्थाओं से प्राप्त ऋण और केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और अन्य पक्षों को दिए ऋणों की वसूलियाँ। पूँजीगत भुगतान में ये मदें शामिल होती हैं – जमीन, इमारतों, मशीनों, उपकरणों जैसी परिसम्पतियों के अधिग्रहण पर किया जाने वाला पूँजी व्यय और शेयरों आदि में लगाई जाने वाली पूँजी तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य पार्टियों आदि को केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम। पूँजी बजट में लोक लेखे के लेन-देन भी शामिल होते हैं।

वित्त विधेयक

संसद द्वारा अनुमोदित अवधि के आगे नए कर लगाने विद्यमान कर ढाँचे के संशोधन अथवा विद्यमान कर ढाँचे को जारी रखने से संबंधित सरकार के प्रस्तावों को वित्त विधेयक के जरिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

संविधान की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेजों के संबंध में कुछ विशेष कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ पूरी करनी होती है और इसलिए केवल उनके द्वारा बजट की प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट संकेत नहीं दिया जा सकता। बजट के सरल बोध को सुविधाजनक बनाने के लिए बजट के साथ कतिपय व्याख्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। ■

प्रोविडेंट फंड सहित सभी लघु बचतों पर से सूद की दर १.५ फीसदी कम कर दी गई है। आम आदमी या नौकरी पेशा व्यक्ति शायद ही इस फंड या बचत के अलावा कुछ बचा पाता है इस तरह के बचतों पर उसकी उम्मीद टिकी रहती है। पिछले साल भी सूद की दर एक फीसदी घटाई गई थी और इस बार भी १.५ फीसदी की कमी की गई है। कुल मिलाकर दो वर्षों २.५ फीसदी की कमी की गई एवं उस अवधि में मुद्रा स्फीति में लगभग ६.६० प्रतिशत की वृद्धि हो गई। परिणामस्वरूप नौकरी पेशा एवं आम आदमी इस दोहरे मार के लिए अभिशप्त है।

इस बजट में कटौती की है। जो लोग निम्न मध्यवर्गीय हैं विशेषकर सेवानिवृत एवं ज्येष्ठ नागरिक उन्होंने अपने बुढ़ापे की व्यवसाा की दृष्टि से जो आर्थिक व्यवस्था की थी उसके ऊपर आघात हुआ है।

प्रोविडेंट फंड सहित सभी लघु बचतों पर से सूद की दर १.५ फीसदी कम कर दी गई है। आम आदमी या नौकरी पेशा व्यक्ति शायद ही इस फंड या बचत के अलावा कुछ बचा पाता है इस तरह के बचतों पर उसकी उम्मीद टिकी रहती है। पिछले साल भी सूद की दर एक फीसदी घटाई गई थी और इस बार भी १.५ फीसदी की कमी की गई है। कुल मिलाकर दो वर्षों २.५ फीसदी की कमी की गई एवं उस अवधि में मुद्रा स्फीति में लगभग ६.६० प्रतिशत की वृद्धि हो गई। परिणामस्वरूप नौकरी पेशा एवं आम आदमी इस दोहरे मार के लिए अभिशप्त है। इसके अलावे बार-बार बचत पर सूद में कमी एक प्रकार का धोखा एवं विश्वासघात है क्योंकि जिस समय लोगों ने बचत किया था उस समय सूद की दर एवं पूर्णावधि की सीमा की अलग शर्त सरकार ने रखी थी। दूसरी ओर पहले बैंक में सावधि जमा पूँजी पर सूद से प्राप्ति १०००० रुपए की राशि पर आयकर लगता था लेकिन सरकार ने अब इसकी सीमा अत्यधिक कम करके २५०० कर दिया है। एक तो जमा राशि पर ब्याज दर में कमी और दूसरा जमा पर प्राप्ति कर योग्य राशि की सीमा कम करना उन गरीब लोगों को भी प्रभावित करेगा। जिन्होंने न्यूनतम २०-२५ हजार रुपए की राशि भी जमा की होगी। यह लोभ दिखाकर जीभ काटने जैसा है।

अमीर मालिकों पर कृपा की वर्षा

इस साल सरकार ने कंपनी का प्र अपेक्षित राशि इकट्ठी नहीं कर पायी। प देखा जाए तो कंपनी कर बड़ी कंपनियों प्राप्त होता है जो वसूल करना आसान र है। लेकिन इसमें भी सरकार को हानि पहुँ है। तो भी भिन्न-२ प्रकार के सहुलियत दे हुए भी वित्तमंत्री निगम कर ज्यादा मिले ऐसा सोच रहे हैं। २०००-२००१ में ४००४ करोड़ रुपये कंपनी कर से आना अपेक्षित था लेकिन संशोधित अनुमान रु. ३८७२१ करोड़ दिखाया गया है। और आनेवाले वर्ष में भिन्न-भिन्न सहुलियतें देते हुए भी यह निगम कर ४४२०० करोड़ रुपये मिलेगा ऐसा वित्तमत्री को लगता है। अमीर, मालिक, धनिक आदि लोगों पर वित्तमंत्री ने किस इसके लिए कृपा की है। निम्न आश्वास देखिए।

१. इसके बाद संपदा शुल्क (इस्टेट ड्यूटी) नहीं रहेगी।
२. दान कर (गिफ्ट टैक्स) नहीं लगेगा।
३. गत वर्ष देश के अन्तर्गत कंपनियों के लाभ वितरण पर और म्यूचुअल एवं यूटीआई की आय पर २० प्रतिशत कर था वह १० प्रतिशत किया जाएगा।
४. दीर्घकालीन पूँजी लाभ देने वाले प्रतिभूति प्रमाणपत्र आदि बेचकर यदि सार्वजनिक उद्योग के समभाग (शेयर) लिए तो कर पर पूरी छूट।
५. अवसंरचना यानि वित्तमंत्री की दृष्टि से निजी हवाई अड्डा, बंदरगाह, अन्तर्देशीय बन्दरगाह, जलमार्ग, औद्योगिक उद्यान आदि में जो पूँजी निवेश करेंगे उन लोगों

Scanned with OKEN Scanner

केंद्रीय आयोजना २००१-२००२ की विशेषताएं

ग्रामीण विकास

I. ग्रामीण रोजगार (६८६४ करोड़ रुपए)

(*a*) रोजगार आश्वासन योजना (१६०० करोड़ रुपए) – गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निर्धनों के लिए रोजगार के अवसर बनाने हेतु निधियों का ७०% राशि प्रखंडो को आबंटित किया जाएगा एवं ३०% आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए रखा जाएगा।

(*b*) स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (५०० करोड़ रुपए) – ५०० करोड़ रुपए की व्यवस्था स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य सहित एक संपूर्ण स्व-रोजगार कार्यक्रम है, के लिए की गई है। इसका उद्देश्य प्रत्येक सहायता-प्राप्त परिवार को तीन वर्षों में गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। कम से कम ५०% स्वरोजगार प्राप्तकर्ता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ४०% महिलाएं और ३% अपंग व्यक्ति होंगे।

(*c*) ग्रामीण आवास (१५२७ करोड़ रुपए) – १५२७ करोड़ रुपए की व्यवस्था ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वयं निर्मित किए जाने वाले ९.८४ लाख आवासों के निर्माण के वास्तविक लक्ष्य सहित ग्रामीण आवास के लिए की गई है।

(*d*) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (८३५ करोड़ रुपए) – ८३५ करोड़ रुपए की व्यवस्था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अधीन ६२ लाख निर्धनों को पेंशन देने और राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम के अधीन २.४० लाख परिवारों को क्षतिपूर्ति देने के लिए की गई है।

(e) अन्नपूर्णा (३०० करोड़ रुपए) – ३०० करोड़ रुपए की व्यवस्था 'अन्नपूर्णा' स्कीम जिसका उद्देश्य उन सभी लोगों जो यद्यपि वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के आधीन शामिल नहीं किए गए है, को प्रतिमाह १० किलोग्राम की दर से खाद्यान्न की खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है के लिए की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत लगभग ४० लाख लाभ भोगी पात्र होंगे।

II. पेय जल पूर्ति

(f) त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम (२०१० करोड़ रुपए) – २०२० करोड़ रुपए की व्यवस्था सभी ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेय जल प्रदान करने के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु राज्यों के लिए की गई है।

(g) ग्रामीण स्वच्छता (१५० करोड़ रुपए) – १५० करोड़ रुपए की ग्रामीण स्वच्छता के लिए व्यवस्था की गई जो ७०% आंवटनों सहित राज्यों द्वारा निर्णय किए जाने वाले चयनित जिलों में संपूर्ण सफाई अभियान के लिए है।

III. भू-संसाधन (९०० करोड़ रुपए)

(h) एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (४३० करोड़ रुपए) – ४३० करोड़ रुपए की व्यवस्था लोगों की भागीदारी से जलसंभरण आधार पर विकास के लिए प्रारंभ किए जाने हेतु की गई है। यह अतिरिक्त ५ लाख हेक्टेयर भूमि के लिए है।

(i) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (२१० करोड़ रुपए) – २१० करोड़ रुपए की व्यवस्था ६ लाख हेक्टेयर नए क्षेत्रों को शामिल करते हुए की गई है।

(j) मरुभूमि विकास कार्यक्रम (१६० करोड़ रुपए) – १६० करोड़ रुपए की व्यवस्था ४ लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करते हुए की गई है।

कृषि और सहकारिता (३०२४ करोड़ रुपए)

- ३०० करोड़ रुपए की व्यवस्था फसल बीमा स्कीम के लिए की गई है।
- ५० करोड़ रुपए की व्यवस्था फार्म जल प्रबंधन स्कीम के लिए की गई है।
- ८५ करोड़ रुपए की व्यवस्था शीत भाडांगारों के लिए पूँजी निवेश सब्सिडी सहित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के लिए की गई है।

उर्वरक

- ११६.५९ लाख टन नाइट्रोजनी उर्वरक के उत्पादन का लक्ष्य।
- ४९.३० लाख टन फॉस्फेटी उर्वरक के उत्पादन का लक्ष्य।

प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता (४००० करोड़ रुपए)

- ५०० करोड़ रुपए की व्यवस्था सर्वशिक्षा अभियान के लिए की गई है। यह अनुसूचित जाति/अनुसूचि जनजाति समुदायों शहरी गंदी बस्तियों के निवासियों और निम्न महिला साक्षरता प्रखंडों के बच्चों के लिए बालिकाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ६-१४ वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अच्छी किस्म की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जिला केंद्रित लक्ष्य के साथ प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को कार्यान्वित करने के लिए है।
- ९३० करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा को पौषणिक सहायता प्रदान करने हेतु उपलब्ध कराए गए है।
- ११०० करोड़ रुपए जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।
- ४०० करोड़ रुपए शिक्षा गारंटी स्कीम तथा वैकल्पिक अभिनव शिक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए है।
- ५२० करोड़ रुपए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हेतु उपलब्ध कराए गए।
- ३६४ करोड़ रुपए अनौपचारिक शिक्षा हेतु उपलब्ध कराए गए।
- २२० करोड़ रुपए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराए गए।
- २०० करोड़ रुपए की व्यवस्था वयस्क साक्षरता के लिए की गयी।

सड़के (६०७८ करोड़ रुपए)

- स्वर्णिम चतुर्भुज (Golden quadrilateral) के निर्माण हेतु, २१०० करोड़ रुपए का प्रावधान।
- १४९२ करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु।

विद्युत (१२३७५)

- ५२७ बिलयन यूनिट उत्पादन का लक्ष्य
- २००० गाँवों का विद्युतीकरण
- २ लाख पम्पसेट लगाए जाएंगे।

लघु उद्योग

- १९४ करोड़ रुपए प्रधानमंत्री रोजगार योजना में २.२ लाख नवयुवकों को नौकरी देने हेतु।
- १२० करोड़ ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए।
- ६० करोड़ लघु क्षेत्र को ऋणमुक्त कराने हेतु।

Scanned with OKEN Scanner

को पूँजी निवेश के कारण होनेवाले लाभ पर आगामी १५ वर्ष के लिए करों से पूरी छूट्टी (टैक्स होलीडेज)।

६. दूरसंचार उद्योग में पूँजी निवेश करने वाले लोगों को जो सहूलियत ३१ मार्च २००० तक थी वह पूर्वगामी प्रभाव से ३१ मार्च २००३ तक बढ़ायी गई है। यह सहुलियत यानि ५ वर्ष की कर-छूट्टी इसके अलावा ३० प्रतिशत आय-कटौती।

७. केवल सहुलियत नहीं अधिक प्रोत्साहन मिले इसलिए आधारभूत संरचना में अमीर लोगों को समभाग लाभांश, पूँजी लाभ, ब्याज आदि सभी प्रकार के आय पर कर से पूरी छूट मिलेगी।

८. शोध और विकास पर जो खर्च होगा उस पर १५० प्रतिशत की छूट होगी।

९. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में निर्यात वृद्धि के लिए जो पूँजी निवेश होगा उसके लिए आने वाले १० वर्षों के लिए शत प्रतिशत कर छूट मिलेगी और ऐसे क्षेत्र विकसित करने वालों को पूरी कर छूट्टी मिलेगी।

१०. एकत्रित प्रकार से अनाज का वहन, भंडारण एवं रख-रखाव ऐसे सभी काम साथ में करने वाले ५ वर्ष के लिए कर छूट तो मिलेगी ही इसके अलावा ३० प्रतिशत कर कटौती का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

उपर्युक्त सहुलियतें छोड़कर शिपिंग उद्योग के लिए २५ प्रतिशत अवक्षयण और कपड़ा उद्योग के नवीनीकरण के लिए ५० प्रतिशत अवक्षयण सहुलियत मिलेगी। संपत्ति का हस्तांतरण करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं रहेगी।

देश का दिवाला

एक तरफ अमीर लोगों को कृपा की वर्षा दूसरी तरफ गरीबों पर होने वाले खर्चों में कटौती, जनता को कम उपभोग की सलाह तो मंत्री लोगों को भर-भर कर भोजन देने वाले वित्तमंत्री को देश की चिंता नहीं है। पैतृक वहुमूल्य संपत्तियों को बेचकर यह सरकार उत्सव मनाने को तैयार है। बालको जैसे देश की शान समझे जाने वाले उद्योग को कूड़े-कचड़े के भाव में बेच रही है और इसी मार्ग से १२,००० करोड़ रुपये जमा करने की योजना है।

आने वाले वर्ष में पूँजी रुपए १४३४७८ करोड़ अपेक्षित है इसमें से केवल १५१६४ करोड़ रुपए पीछे दिए गए कर्जों की वसूली है। शेष सब रकम यानि १२८३१४ करोड़ रुपए भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्ज है। उसमें भी बाजार ऋण ७७३५३ करोड़ रुपए है।

पूँजी खाता प्राप्ति में भिन्न-भिन्न प्रकार से रुपए १२८३१४ करोड़ आने वाले हैं। इसमें से गत कर्जे के ऊपर ब्याज के रूप में ११२३०० करोड़ रुपए देने होंगे। यानि केवल ब्याज देने के लिए ही सरकार नया कर्जा ले रही है।

कुल मिलाकर बजट ३,७५,२२३ करोड़

एक मंत्री द्वारा दूसरे मंत्री के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए इस प्रकार का नैतिक एवं कानूनी बंधन भी होता है। लेकिन वित्तमंत्री को विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हरी झंडी दिखाने की जल्दी पड़ी थी। इसलिए श्रम कानूनों में आमूलाग्र बदलाव करने का आश्वासन वित्तमंत्री ने बजट में दिया है। गत पचास वर्ष में इस प्रकार का दुःसाहस किसी भी वित्तमंत्री ने नहीं किया था।

रुपए का है। इसमें से कुल पूंजी खाते पर आयोजना व्यय ४८७५ करोड़ रुपए हो रहा है। पूंजी निवेश के कारण भविष्य में आय बढ़ती है लेकिन सरकार पूंजी निवेश पर १० प्रतिशत से भी कम पूंजी लगा रही है। इसका अर्थ भविष्य अंधकारमय है।

इसके विरोध में कुल राजस्व खाते में जो जमा राशि अपेक्षित है यह है २,३१,७४५ करोड़ रुपए। लेकिन पीछे लिए हुए कर्ज का आने वाले २००१-२००२ वित्तीय वर्ष में ऋण की वापसी अदायगी १२५९७२ करोड़ रुपए होगी और कुल ब्याज अदायगियाँ ११२३०० करोड़ रुपए होगी। यानि कुल २३८२७२ करोड़ रुपए लिए गए ऋण की वापसी का हिस्सा और ब्याज इस पर खर्च होगा। य[...] राजस्व प्राप्तियों से यह रकम ज्याद[...] समझिए कि एक कर्मचारी को पांच ह[...] रुपए वेतन मिलता है और उसको कर्ज [...] वापसी हिस्सा और ब्याज के रूप में ६०[...] रुपए प्रति माह देने होंगे तो ऐसे व्यक्ति [...] हम क्या कहेंगे। देश का दिवाला निकला हु[...] है और मंत्री लोग अपना वेतन भत्ता, विदे[...] प्रवास आदि सुख-सुविधा बढ़ा रहे है। य[...] बहुत संतोषजनक नहीं है।

गैर-कानूनी और अनैतिक

कुल मिलाकर यह बजट गरीबों प[...] अन्याय करने वाला एवं अमीरों पर कृप[...] बरसाने वाला तक ही सीमित नहीं है ब[...] इससे ऊपर गैरकानूनी एवं अनैतिक भी है।

एक मंत्री द्वारा दूसरे मंत्री के कार्यक्षे[...] में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए इस प्रका[...] का नैतिक एवं कानूनी बंधन भी होता है। लेकिन वित्तमंत्री को विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हरी झंडी दिखाने की जल्दी पड़ी थी। इसलिए श्रम कानूनों में आमूलाग्र बदलाव करने का आश्वासन वित्तमंत्री ने बजट में दिया है। गत पचास वर्ष में इस प्रकार का दुःसाहस किसी भी वित्तमंत्री ने नहीं किया था। सुझाव किए हुए बदलाव कामगारों की दृष्टि से कितनी अन्यायपूर्ण है यह एक स्वतंत्र लेख का विषय है। किंतु यहाँ केवल एक बात स्पष्ट करना उचित होगा। भारत में कारखानों में काम करने वाले कामगारों की संख्या ९८ लाख है। इसमें से १००० से अधिक कामगार वाले कारखानों में जो काम करते है ऐसे कामगारों की संख्या १३ लाख है। केवल इनको ही वित्तमंत्री ने संरक्षित किया है और बाकी कारखानों में मजदूरों की कटौती हेतु अब सरकार की अनुमति नहीं चाहिए। यानि ८५ लाख कामगारों का भविष्य वित्तमंत्री ने संरक्षणहीन बना दिया।

ऐसा बजट जो देश की गरीब शोषित जनता, की उपेक्षा करके उसे अमीरों, उद्योगपतियों के हित में बनाया गया हो उसे जला देना चाहिए और ऐसे संवेदनहीन वित्तमंत्री को भी त्यागपत्र दे देना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

सच कहा जाए तो यह बजट कई क्षेत्रों में या तो आमूल परिवर्तन की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करता है या कम से कम ऐसे परिवर्तनों की प्रक्रिया की शुरुआत अवश्य कर देता है।

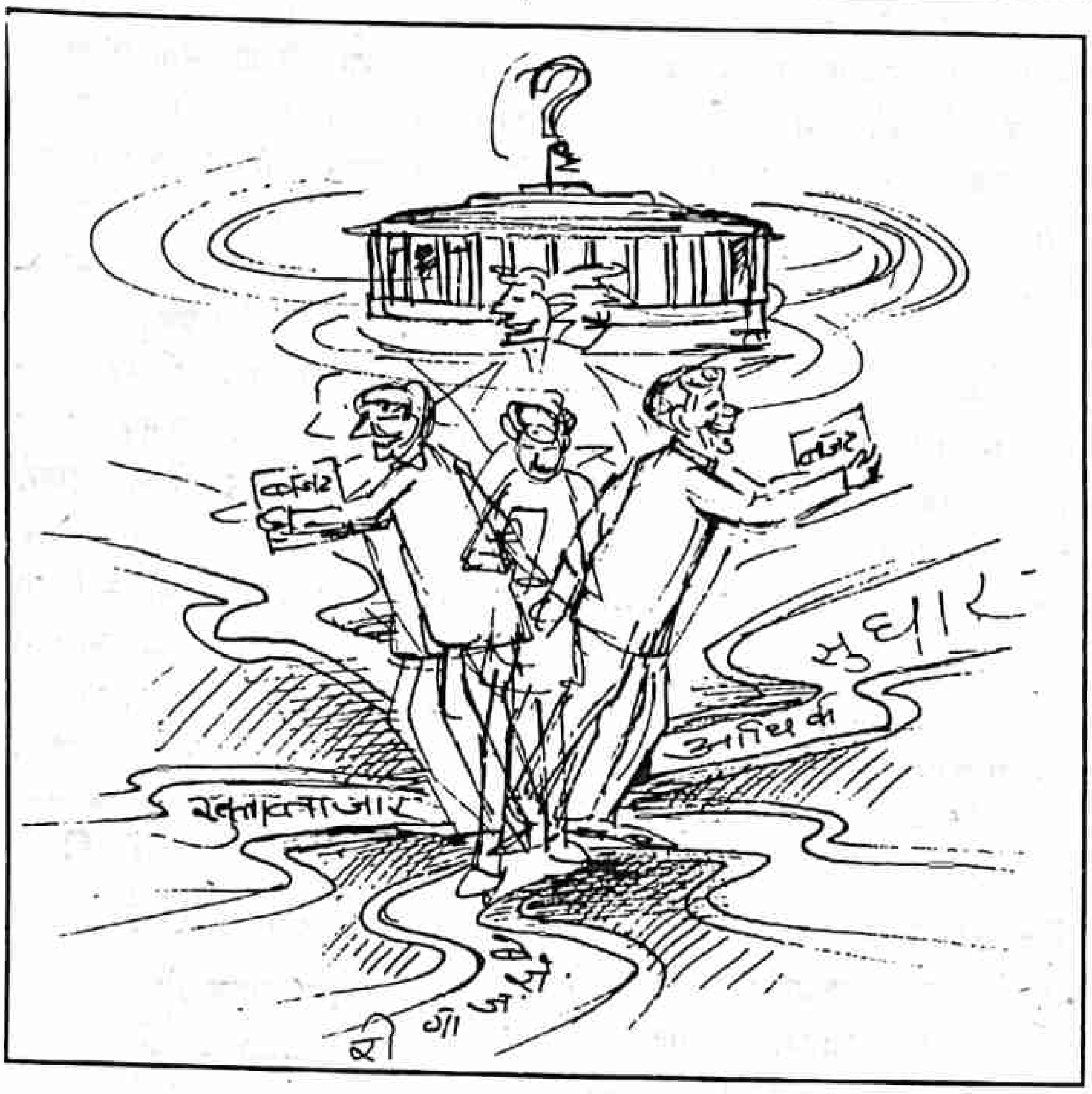

क्या हश्र होगा इस सुधारवादी बजट का?

■ अवधेश कुमार*

सामान्यतः बजट का अर्थ है आय एवं व्यय का ब्यौरा। बजट के माध्यम से मूलतः यह दर्शाया जाता है कि पिछले वर्ष कर सहित विभिन्न मदों से आमदनी का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिनमें से कितनी की प्राप्ति हुई एवं इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में व्यय का जो लक्ष्य घोषित हुआ था वह हासिल हुआ या नहीं। वास्तव में एक परिपक्व अर्थव्यवस्था वाले देश में वार्षिक बजटों की मूल भूमिका यहीं तक सीमित होती है। लेकिन, भारत में बजट का आयाम कई बार आर्थिक नीतियों की व्यापक दिशा तक विस्तारित हुआ है। विशेषकर उदारवादी अर्थनीति की दृष्टि से देखें तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सन् १९८६ में, श्री मनमोहन सिंह ने सन् १९९१ में तथा श्री पी. चिदम्बरम ने सन् १९९७ में अपने बजटों के द्वारा ही आर्थिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बजट भारत की अर्थनीति में व्यापक बदलाव के वाहक बने। बजट का यह स्वरूप इन तीन बजटों तक ही सीमित हो– ऐसा नहीं है। बल्कि जबसे आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ हुई प्रत्येक बजट में कुछ न कुछ नीतिगत बदलाव संबंधी कदम आवश्य उठाए गए हैं और अर्थव्यवस्था की अभी जो स्थिति है उसके आलोक में यह अपने आप स्पष्ट है कि बजट का यह स्वरूप अभी कुछ समय तक बना रहेगा। वित्तमंत्री श्री यशवंत सिन्हा के वर्तमान बजट को आर्थिक सुधारों की दिशा में सन् १९९१-९२ के मनमोहन सिंह के बजट के बारे में सबसे अधिक परिवर्तनकारी बजट की संज्ञा दी जा सकती है।

सच कहा जाए तो यह बजट कई क्षेत्रों में या तो आमूल परिवर्तन की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करता है या कम से कम ऐसे परिवर्तनों की प्रक्रिया की शुरुआत अवश्य कर देता है। अगर यह बजट अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा तो फिर अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। यह बात अलग है कि इन परिवर्तनों के वास्तविक परिणामों को लेकर सशंकित होने की काफी गुँजाईश तो है ही, अनेक कदमों की सफलता की संभावनायें भी क्षीण दीख रही हैं। बहरहाल, बजट के इन प्रावधानों पर नजर डालने के पूर्व यह याद दिलाना आवश्यक है कि देश के अधिकतर आर्थिक विश्लेषक, उद्योग जगत एवं शेयर बाजार से जुड़े लोग इस बजट की ठीक उसी तरह प्रशंसा कर रहे हैं, जिस तरह पूर्व वित्तमंत्री चिदम्बरम के सन् १९९७ के बजट की कर रहे थे। उस बजट को भी "ड्रीम बजट" की संज्ञा दी गई थी। किन्तु उसका वास्तविक हस्र क्या हुआ – यह हम सबको

*लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक-आर्थिक विश्लेषक हैं

ज्ञात है। उस पृष्ठभूमि में इस आशंका का बलवती होना स्वाभाविक है कि कहीं इतिहास अपने को दुहरा न दे।

आईये, पहले हम बजट में घोषित उन मुख्य कदमों पर विचार करें जिन्हें बाजार आधारित उदारवादी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आमूल परिवर्तन की संभावनाओं वाला कहा जा सकता है। ये प्रावधान हैं– व्यापक पैमाने पर निजीकरण, श्रम कानूनों में भारी बदलाव, उपभोग शुल्क की पूर्ण वसूली व प्रशासनिक मूल्य व्यवस्था का अन्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम का पुनरीक्षण व भारतीय खाद्य निगम की भूमिका में कमी, लघु उद्योग के अनेक मदों को आरक्षित सूची से अलग करना तथा सरकार के आकार का लघुकरण। वित्तमंत्री ने इन सुधार कदमों को तीव्र आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य घोषित किया है। वास्तव में अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढाँचे व शब्दावली की सीमा में विचार करें तो वित्तमंत्री के सामने जो तात्कालिक आर्थिक समस्याएँ हैं जिनमें मंदीग्रस्त समग्र आर्थिक हालात, अवसादग्रस्त व्यापारिक मनोविज्ञान, संकटग्रस्त कृषि, औद्योगिक विकास में गिरावट आदि प्रमुख हैं। स्वाभाविक ही वैसी निराशाजनक स्थिति से उबारकर विकास की दिशा में आर्थिक तानावाना को धकेलना ही किसी भी वित्तमंत्री का तात्कालिक उद्देश्य हो सकता है। ऐसा तभी संभव है जब मंदी से मुक्ति मिले एवं अर्थव्यवस्था को प्रभावित करनेवाले मुख्य कारकों की मनःस्थिति को अवसाद के गर्त से निकालकर उनके अन्दर आशा का संचार किया जा सके। कहना न होगा कि वित्तमंत्री ने उपरोक्त परिवर्तनकारी कदमों के अलावा ब्याज की दर में कमी, विभिन्न करों की दरों में कटौती एवं आधारभूत संरचना में भारी निवेश की संभावना दिखाकर, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की है। लेकिन, क्या बजट इन उद्देश्यों को पाने में संभव हो सकेगा?

यदि बजट के प्रशंसकों पर विश्वास किया जाए तो हाँ। हालांकि बजट के समर्थक अपने आकलन में एकदम गलत हों ऐसा नहीं है। उदारवादी अर्थव्यवस्था का सामान्य सिद्धांत है कि आर्थिक ताने-बाने में जहाँ-जहाँ अवरोध हों, जो-जो प्रश्न कुछ बंधनों में बंधे हों - उनमें से अधिकतर को अवरोधमुक्त - बंधनमुक्त कर दिया जाए, ताकि वे बाजार की प्रतिस्पर्धा में खुलकर स्वाभाविक गति से स्वतंत्र अवस्था में विकास कर सकें। निश्चित रूप से वित्तमंत्री ने इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए अपने बजट द्वारा जितना संभव था - अर्थव्यवस्था को बंधन मुक्त करने का प्रयास किया है। इसे अंध-अनुसरण इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जन-दबाव के मद्देनजर उन्होंने आयात कर आदि के क्षेत्र में कुछ अवरोध भी खड़े किए हैं। हालांकि ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि वित्तवर्ष २००१-०२ की शुरुआत के साथ ही विभिन्न वस्तुओं के आयात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों का लगभग अंत हो रहा

उदारवादी अर्थव्यवस्था का सामान्य सिद्धांत है कि आर्थिक ताने-बाने में जहाँ-जहाँ अवरोध हों, जो-जो प्रश्न कुछ बंधनों में बंधे हों - उनमें से अधिकतर को अवरोधमुक्त - बंधनमुक्त कर दिया जाए, ताकि वे बाजार की प्रतिस्पर्धा में खुलकर स्वाभाविक गति से स्वतंत्र अवस्था में विकास कर सकें।

है, जिनके आवाहन के भार से देशी उत्पादों की रक्षा करने का तात्कालिक उपाय यही है कि उनपर सीमा शुल्कों में भारी बोझ लाद दिया जाए। वैसे यह ऐसा विषय है जिस पर अलग विस्तार से विचार करना जरूरी है।

ब्याज दर में कटौती की घोषणा कर वित्तमंत्री ने एक प्रकार से उसे धीरे-धीरे बाजार के हवाले छोड़ने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। यानि अब ब्याज का दर क्या होगा– यह बाजार की प्रतिस्पर्धा तय करेगा। इसके पीछे सोच यह है कि बैंकों आदि का ब्याज दर कम होने से निवेशक पूँजी बाजार की स्थिति मजबूत होगी तथा उद्योग एवं आधारभूत संरचना के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध हो सकेगा। वैसे इन अपेक्षाओं की पूर्ति कहाँ तक हो पाती है– इसे देखना होगा। पर इतना तय है कि इससे छोटे बचतकर्ता बुरी तरह प्रभावित होंगे। बैंक से लेकर डाकघर की विभिन्न योजनाओं में थोड़ी-थोड़ी राशि जमा करनेवाले आम आदमी को प्राप्त होने वाले ब्याज लाभ में तत्काल कमी आ जाएगी।

बजट के दो महत्वपूर्ण प्रावधनों - श्रम कानून में परिवर्तन तथा सरकार के आकार में कमी पर जब हम विचार करते हैं तो बहुत आशाजनक तस्वीर नहीं उभरती है। यह सिद्धांत एक हद तक सही है कि जो उद्योग एकदम बीमार हो गए हैं, जिनका पुनर्संचालन संभव नहीं, उन्हें बन्द किया ही जाना चाहिए। लेकिन यदि श्रमिकों को निकाला नहीं जा सकते तो फिर उद्योग भी बन्द नहीं हो सके। और जब तक बीमार मृतप्राय उद्योग बन्द नहीं होंगे नये उद्योगों के खड़े होने की संभावनाएं क्षीण रहेंगी। वैसी हालत में नये रोजगार के अवसर भी अपेक्षित मात्रा में पैदा नहीं होंगे। इस दृष्टि से देखें तो श्रम कानूनों को इतना लचीला बनाना आवश्यक दिखेगा ताकि प्रबंधन अपनी आवश्यकतानुसार श्रमिकों की छँटनी एवं भर्ती कर सकें। बजट में श्रम कानूनों में सुधार संबंधी जो प्रावधान हैं उनमें पांच बिन्दु प्रमुख हैं:-

एक, १०,००० से ज्यादा श्रमिक वाले कम्पनी अतिरिक्त श्रमिकों की छँटनी अब आसानी से कर सकेंगे; दो, अनुबँध पर काम करनेवाले या ठेका मजदूर (कॉन्ट्रैक्ट लेबर) प्रथा को एक प्रकार से प्रतिबंधित करने वाले जो सख्त कानून हैं- उनको समाप्त किया जाएगा; तीन, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं अनुबंध श्रमिक कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा शेष दो प्रावधान श्रमिकों की हितरक्षा की दृष्टि से प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें पहला तो मुआवजा की राशि प्रत्येक कार्यवर्ष के १५ दिन के पारिश्रमिक को बढ़ाकर ४५ दिन तथा; दूसरे, नौकरी से बाहर जानेवालों के लिए अंतिम प्राप्त वेतन के ३० प्रतिशत की नयी इन्श्योरेंस योजना का प्रावधान है। बैंकों के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम यह उठाया गया है कि अब आगामी जुलाई माह से बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड इतिहास के विषय हो जाएंगे एवं बैंक प्रबंधन अपनी आवश्यकतानुसार श्रमिकों

Scanned with OKEN Scanner

की भर्ती के लिए स्वतंत्र होगा। श्रमिक क्षेत्र का ही एक अन्य पहलू सरकार के आकार में कटौती भी है। बजट के अनुसार केन्द्र अपने कर्मचारियों की संख्या में अगले पाँच वर्ष के भीतर कम से कम दस प्रतिशत की कमी लाएगा। वैसे पिछले कई बजटों से केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या में कटौती की बात होती रही है, पर व्यावहारिक धरातल पर हुआ कुछ भी नहीं। किन्तु, इस बार एक तो सरकार के हाथ में व्यय सुधार आयोग (एस्कपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन) की विस्तृत रिपोर्ट है तथा दूसरे, योजना आयोग के द्वारा छँटनी के लिए एक पुल बनाने की बात कही गई है जिसमें सक्षम छँटनीग्रस्त कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षित (रिट्रेनिंग) कर नये काम में लगाने की बात है।

स्पष्टतः यदि श्रमिक क्षेत्र में सारे प्रावधान क्रियान्वित हो गए तो यह निश्चय ही युगान्तकारी परिवर्तन होगा। इतिहास में एकबारगी इतने व्यापक परिवर्तनों के उदाहरण शायद ही मिले। लेकिन सवाल है कि क्या इनसे प्रबंधन को मनमानी की खुली छूट नहीं मिल जाएगी? लम्बे संघर्षों के बाद श्रमिकों के लिए जिन अधिकारों को वैधता का जामा पहनाया गया – वह सब एक साथ तार-तार नहीं हो जाएगा? खासकर ठेके पर काम करनेवाले श्रमिकों के भविष्य की चिंता से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बजट में श्रमिक भी सुरक्षा संबंधी प्रावधान शेष सुधारों के समानान्तर ठोस सकारात्मक आश्वासन प्रदान नहीं करते। ऐसे उदाहरण विरले ही हैं जबकि लम्बे समय काम करने के पश्चात् छाँटे गए श्रमिकों को उपयुक्त रोजगार मिला हो। यह मान भी लिया जाए कि सुधार अंततः रोजगार को बढ़ावा देगा तब भी सुधारों की वेदी पर बलि चढ़नेवाले मजदूरों के भविष्य की चिंता बनी रहती है। थोड़े शब्दों में कहें तो छँटे श्रमिकों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। वित्तमंत्री का सुझाव मुआवजा राशि को तीन गुना बढ़ाने की है। लेकिन, इतनी राशि देगा कौन? क्या बीमार और मृतप्राय उद्योग जो कि बन्द होने जा रहे हैं! स्पष्ट है कि प्रबँधन की संभावित मनमानी पर अंकुश लगाने एवं श्रमिकों की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ ठोस उपाय करने ही पड़ेंगे।

अब आइये संक्षेप में शेष सुधारवादी कदमों पर विचार करें। सबसे पहले उपभोक्ता शुल्क। बजट प्रावधान के अनुसार सन् २००१ के अन्त तक बिजली की पूरी खपत को मीटर रीडिंग के भीतर ले आया जाएगा। वास्तव में यह ऐसा कदम है जिससे हर कोई सहमत होगा। आखिर आज कुछ उत्पादित बिजली का लगभग ४० प्रतिशत खपत बिना मीटर रीडिंग के है, बल्कि राजस्व की भी भारी हानि होती है। आज कुल उत्पादित बिजली में से केवल ३० प्रतिशत का ही भुगतान हो पा रहा है। स्पष्ट है कि इस स्थिति को लम्बे समय तक वहन करना किसी के भी हित में नहीं है। बिजली किसी भी अथव्यवस्था की रीढ़ है। इस रीढ़ को मजबूत करने के लिए इसे सशक्त एवं स्वालम्बी बनाना ही होगा। इसी दिशा में बजट की दूसरी घोषणा सन् २००२ तक प्रशासनिक मूल्य व्यवस्था का अन्त करने की है। यानि सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को बाजार के हवाले करने जा रही है। प्रशासनिक मूल्य व्यवस्था की समाप्ति के साथ ही जटिल तेल पूल व्यवस्था का अंत हो जाएगा एवं सारे पेट्रोलियम उत्पाद जैसे किरासन, डीजल, रसोई गैस (एल.पी.जी.) आदि का भुगतान बजट की सीमा से निकल जाएगा। इसी तरह खाद्यान्न के क्षेत्र में भी सरकार आवश्यक वस्तु

इतिहास में एकबारगी इतने व्यापक परिवर्तनों के उदाहरण शायद ही मिले। लेकिन सवाल है कि क्या इनसे प्रबंधन को मनमानी की खुली छूट नहीं मिल जाएगी? लम्बे संघर्षों के बाद श्रमिकों के लिए जिन अधिकारों को वैधता का जामा पहनाया गया – वह सब एक साथ तार-तार नहीं हो जाएगा? खासकर ठेके पर काम करनेवाले श्रमिकों के भविष्य की चिंता से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

अधिनियम को नयी रूपरेखा देना चाहती है। यह बात सही है कि खाद्यान्न सब्सिडी घटने की बजाय १३,६७५ करोड़ की असहाय सीमा को लाँघ चुका है। इसके बड़े कारण खाद्यान्नों की खरीद में भारतीय खाद्य निगम की आवश्यकता से अधिक विस्तृत भूमिका एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम भी हैं। इसके माध्यम में जारी सरकार के सख्त नियंत्रण के कारण कृषि में निवेश नहीं हो सका एवं कृषि क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए, नहीं हो पाया है।

इन परिप्रेक्ष्यों में विचार करें तो ये सारे कदम अनिवार्य, उपयोगी एवं आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेक ऊर्जा साबित होंगे। बड़ी सीमा तक ऐसा है भी। पर शेर और बकरी के एक ही घाट पर पानी पीने के खतरे को नहीं भूलना चाहिए। बिजली एवं पेट्रोलियम उत्पाद की कीमत लागत मूल्यों के आधार पर तय हों– यह बात तो समझ में आती है; किन्तु निर्धन एवं सधन के लिए एक ही मूल्य-व्यवस्था को वह भी एक जनकल्याणकारी राज्य में, उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक बड़ा उद्योगपति, बड़े ट्रांसपोर्ट मालिक बिजली एवं पेट्रोलियम उत्पाद के वही मूल्य चुकायें जो कि एक गरीब एवं सीमान्त किसान– यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण होगा। दुर्भाग्यवश, वित्तमंत्री ने सिंचाई एवं जन यातायात के लिए बिजली एवं डीजल आदि के लिए रियायती मूल्य व्यवस्था की बात तक नहीं की हैं। निश्चय ही सुधार कार्यक्रमों का यह एक खतरनाक पक्ष है। हालांकि खाद्यान्न के मामले में वित्तमंत्री ने गरीबी की रेखा से नीचे जीनेवालों के लिए व्यवस्थायँ की हैं। परन्तु ऐसा लगता है कि खाद्यान्न सब्सिडी को घटाने के प्रयास में वे खाद्यान्नों की खरीद एवं उसके वितरण की सारी जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर डालने जा रहे हैं। राज्य सरकार को इसमें भारतीय खाद्य निगम का सहयोग मिल भी सकता है और नहीं भी। इसलिए संभव है कि भारतीय खाद्य निगम की उपयोगिता ही समाप्त हो जाए एवं उसे बन्द कर देना पड़े। साथ ही पूरी खाद्य वितरण प्रणाली के चरमरा जाने का भी खतरा है।

जहाँ तक ग्रामीण विकास एवं कृषि का सवाल है – वित्तमंत्री ने निस्संदेह इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन

Scanned with OKEN Scanner

कदमों के ठोस सकारात्मक परिणाम आने की आशा की जा सकती है। लेकिन, यहाँ भी कृषि क्षेत्र में निवेश की सर्वाधिक जिम्मेवारी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सिर डाली गई है। स्पष्ट है कि नाबार्ड को अपनी इस वृहत्तर भूमिका के निर्वहन के लिए न केवल भारी मात्रा में संसाधन चाहिए, बल्कि उसकी सक्रियता एवं जोखिम लेने की उसकी क्षमता भी बढ़नी चाहिए। नाबार्ड को अपने लिए बाजार में कर मुक्त बॉण्ड द्वारा राशि उगाहने की छूट है। अब इस छूट द्वारा वह कितनी राशि एकत्र कर पाता है, उसमें से कितना निवेश कर पाता है एवं निवेश-राशि में से कितने की वापसी संभव हो पाती है- इन्हीं तीन बिन्दुओं पर इसकी पूरी सफलता निर्भर हैं। स्पष्ट है कि नाबार्ड की संरचना में आवश्यक बदलाव के बगैर वह अपनी इस विस्तारित भूमिका को पूरी तरह अंजाम दे सकेगा - इसमें संदेह हैं।

इस तरह देखा जाए तो बजट में सुधार संबंधी लगभग सारे कदम एक ही साथ संभावनाओं व आशंकाओं से भरे हुए हैं। लघु उद्योगों के प्रावधानों को ही ले लीजिए। वित्तमंत्री ने चमड़ा एवं खिलौना सहित १४ मदों को आरक्षण की श्रेणी से अलग कर दिया है। क्यों ये क्षेत्र तकनीक एवं गुणवत्ता की दृष्टि से सक्षम हुए बिना आयातित मालों के मुकाबले बाजार में टिक पाएंगे? थोड़े शब्दों में कहें तो सुधार प्रावधानों से दूरगामी लाभ की संभावनाएं भले दर्शायी गयी हैं, किन्तु तत्काल इतने व्यापक कार्यक्रमों से समाज का बड़ा वर्ग दुष्प्रभावित होनेवाला है। इनमें छोटे बचतकर्त्ता व निवेशकों से लेकर, सरकारी सेवक, अन्य श्रमिक, पेन्शन भोगी, लघु उद्योग, छोटे किसान आदि सभी शामिल हैं। साफ है कि इन सबकों संतुष्ट करने के लिए सरकार को राहतकारी कदम उठाने होंगे। इसके लिए भारी मात्रा में संसाधन चाहिए। समस्या यह है कि सरकार के खजाने में इतना धन है ही नहीं। सरकारी कर्ज व ब्याज अदायगी, सब्सिडी पेंशन तथा रक्षा खर्च को पूरा करने के बाद सरकार के पास २,८१,००० की कुल प्राप्ति में से केवल १२,००० करोड़ रुपया शेष बचता है। कहना न होगा कि आज की हालत में १,२३,००० करोड़ सरकारी खर्च को पूरा करने के लिए ही १,१०,००० करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा।

वित्तमंत्री ने एक रास्ता विनिवेश का पकड़ा है। बजट में २७ सार्वजनिक निगमों के विनिवेश की घोषणा की गई है। हालांकि सार्वजनिक निगमों के बिक्री का तत्काल इतना परिणाम तो होगा ही कि धन प्राप्ति के साथ-साथ सरकार के सिर से जिम्मेवारी का अतिरिक्त बोझ भी कम होता है। लेकिन, विनिवेश का अभी तक का अनुभव निराशाजनक ही रहा है। सन् १९९९-२००० एवं २०००-२००१ में १० हजार करोड़ के समान विनिवेश लक्ष्य में से केवल ८२९ करोड़ एवं ५०० करोड़ की ही प्राप्ति हो सकी। इसलिए इस वर्ष सरकार १२,००० करोड़ रुपया का लक्ष्य पा ही लेगी इसमें संदेह की काफी गुंजाईश है।

> ***यह कैसी विडम्बना है कि उस अर्थनीति को राष्ट्रविरोधी करार देकर तूफान खड़ा करने वाली भाजपा का वित्तमंत्री आज उनसे आगे बढ़कर इतिहास का सबसे बड़ा उदारवादी बजट पेश कर रहा है। इस बजट के द्वारा अब इन्होंने यह साफ कर दिया है कि इनका विरोध महज एक पाखण्ड था।***

इन सबके बावजूद वित्तमंत्री ने राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के ४.७ प्रतिशत तक सीमित कर देने का जो वायदा किया है उसमें कईयों को आश्चर्य हो सकता है। आश्चर्य तो तब भी हुआ था जब वित्तमंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण में यह दावा किया कि उन्होंने राजकोषीय घाटा को ५.१ प्रतिशत तक सीमित कर देने का लक्ष्य पा लिया है। प्रश्न उठाता है कि सब्सिडी सहित सरकारी खर्चों में कमी न होने के बावजूद ऐसा संभव कैसे हो सका? इसका एक उत्तर तो यह है कि सब्सिडी सहित सरकारी खर्चों में कमी न होने के बावजूद ऐसा संभव कैसे हो सका? इसका एक उत्तर तो यह है कि पिछले बजट में श्री सिन्हा ने कुल योजनागत व्यय ११ प्रतिशत की तथा पूंजी आवंटन में १४ प्रतिशत बढ़ोत्तरी की घोषणा की थी। इसके ठीक विपरीत इसमें कमी आ गई। स्पष्ट है कि इन्हें राजकोषीय घाटा कम करने के मद में डाल दिया गया। ध्यान रखने की बात है कि योजनागत खाता से पूंजीगत व्यय में २,६३६ करोड़ की जो कमी आई उसका असर आधारभूत संरचना पर पड़ा। इस वर्ष भी इसकी पुनरावृत्ति की संभावना बनी हुई है। यदि ऐसा हुआ तो फिर आधारभूत संरचना तथा कृषि सहित सामाजिक क्षेत्र के विकास का लक्ष्य अपेक्षित है- वह पूरा नहीं हो सकेगा एवं स्वाभाविक ही इसका विपरीत प्रभाव हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बजट ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि वर्तमान सरकार बाजार आधारित उदारवादी अर्थव्यवस्था के रास्ते दृढ़ता से आगे बढ़ने का निश्चय कर चुकी है। यहाँ पूर्व वित्तमंत्री मनमोहन सिंह का यह कथन एकदम सही है कि कांग्रेस ने इस वर्ष पूर्व अर्थनीति के जिन प्रतिमानों (पाराडिग्म) की शुरुआत की थी- उसे अब उन सबने स्वीकार कर लिया है, जो कि विपक्ष में रहते समय इसकी आलोचना करते थे। यह कैसी विडम्बना है कि उस अर्थनीति को राष्ट्रविरोधी करार देकर तूफान खड़ा करने वाली भाजपा का वित्तमंत्री आज उनसे आगे बढ़कर इतिहास का सबसे बड़ा उदारवादी बजट पेश कर रहा है। इस बजट के द्वारा अब इन्होंने यह साफ कर दिया है कि इनका विरोध महज एक पाखण्ड था। ये जिस तथाकथित वैकल्पिक अर्थनीति की बात करते थे, या तो उसके प्रति ये स्पष्ट नहीं थे या फिर उसमें इनकी निष्ठा नहीं थी। सिद्धांत रूप में शायद इस बजट द्वारा उजागर नीति संबंधी सबसे कारूणिक पक्ष यही है। ■

Scanned with OKEN Scanner

भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ करोड़ों लोग किसी न किसी काम धंधे की तलाश में है वहाँ प्रगति का कोई विदेशी अन्य मापदंड की कल्पना करना घातक है।

■ विद्यानंद आचार्य

श्रम कानून में प्रस्तावित संशोधन

- १,००० या इससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को हटाने की राह सुगम बनाई जाएगी।
- निकाले जाने के बाद कुल सेवित वर्ष का ४५ दिन के बराबर का वेतन मुआवजे के तौर पर। पहले १५ दिन का मिलता था।
- बाहर से कर्मचारी लेने की इजाजत होगी और पूर्व में नियुक्ति से जुड़े प्रतिबंध हटाए जाएंगे।
- औद्योगिक विवाद कानून १९४७ एवं ठेका मजदूर कानून में संशोधन होगा।

वैश्वीकरण का हितैषी बजट

प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उन्होंने प्रशासन से यह जानकारी माँगी है कि उन्हें रुपयों नहीं अपितु काम-धंधे के हिसाब से आवंटनों के बारे में अवगत कराया जाए लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री इसमें सफल नहीं हो पाए। नौकरशाह उन्हें यह ब्यौरा उपलब्ध कराने में अक्षम रहा।

तात्पर्य यह कि रुपयों-डॉलरों से भरा आँकड़ों का यह विशाल दस्तावेज क्या पिछले ५० वर्षों से देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे लोगों को न्यूनतम मानवीय सुविधा भी उपलब्ध करा पाया है। वर्ष दर वर्ष संसद में बजट प्रस्तुत करने की रस्म अदा की जाती है। आम आदमी जो बहुमत में है, को छोड़कर व्यापारी, बनिये, राजनेता आदि लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं इस तर्क के साथ कि इससे देश का विकास होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा लोगों को रोजगार मिलेंगे। इस बजट में आँकड़ों में रुपए तो इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि उससे आर्थिक विशेषज्ञों के अलावा आम लोगों के लिए याद करना भी मुश्किल होता है। लेकिन पैसों में होने वाला यह बजट प्रावधान लोगों को कितना रोजगार मुहैया करवा पाएगा यह बता पाने में असमर्थ होता है।

भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ करोड़ों लोग किसी न किसी काम धंधे की तलाश में है वहाँ प्रगति का कोई अन्य मापदंड की कल्पना करना घातक है। हालात तो ऐसे है कि आम आदमी सरकार से अपेक्षा करता है कि इस बार के बजट में वह रोजगार निर्माण का अवसर जुटाएगा लेकिन बजट में अलग से रुपयों का प्रावधान इसलिए किया जाता है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से (स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना) हटाया जा सके।

वृद्धि दर का अप्राप्य लक्ष्य

इस वित्तमंत्री द्वारा इस सरकार में प्रस्तुत देश का यह लगातार चौथा बजट है। लेकिन हर वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय जिस उत्साह से बजट की विशेषताओं की चर्चाएँ होती है और कहा जाता है कि इससे आर्थिक विकास की वृद्धि दर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। यह तथ्य कितना सत्य है इसका ज्ञान सरकार द्वार ही बजट से पूर्व प्रस्तुत इस वर्ष के आर्थिक समीक्षा को पढ़ने से ज्ञात हो जाता है। आर्थिक समीक्षा २०००-२००१ के सामान्य समीक्षा खंड में भूमिका में ही जिस आँकड़े को लिखा गया है वह पिछले बजट में निर्धारित लक्ष्यों को न प्राप्त कर पाने की पुष्टि करता है। ज्ञातव्य हो वर्ष १९९८-१९९९ में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद ६.६ प्रतिशत से कम होकर वर्ष १९९९-२००० में ६.४ प्रतिशत पर एवं वर्ष २०००-२००१ में और घटकर केवल ६.० प्रतिशत हो गया। यह गिरावट इस बात का प्रतीक है कि हर बजट में जिन उद्योगपतियों, पूँजीपतियों के हित के लिए सरकार बढ़-चढ़कर घोषणाए करती है, वही वर्ग वित्तमंत्री के प्रसंशा में अच्छी बजट का ढोल पीटता है और वही वही वर्ग राष्ट्र के विकास की दर को पीछे धकेलता है। आम आदमी बजट से न कभी जुड़ा था न सरकार उसके हित के लिए कुछ करती है। यह बजट भी ऐसा ही है और इतने दावों के बावजूद भी विकास लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा कि नहीं यह प्रश्न चिन्ह है। पूर्वानुभव कहता है – नहीं।

ज्ञातव्य हो भारत आर्थिक सम्मेलन २००० के उद्घाटन करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत इस बार ८ प्रतिशत का विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखेगा। ठीक उसी सम्मेलन में अगले दिन विश्व आर्थिक मंच के प्रबंध निदेशक क्लाऊड स्माजदा ने इस लक्ष्य पर ही प्रश्न

Scanned with OKEN Scanner

चिन्ह लगा दिया। अवसंरचना, राजस्व घाटा, विनिवेश आदि में अब तक के अनुभवों के आधार पर उन्होंने कहा कि "चमत्कार से ही ८.१%. वृद्धि दर हासिल की जा सकती है।

(स्रोत : द इकोनॉमिक टाइम्स २८ नव. २०००)

श्रमिक विरोधी बजट

१९९१ में नई आर्थिक नीति का कार्यान्वयन किए जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हुआ जिसके परिणामस्वरूप घरेलू औद्योगिक वातावरण तथा श्रम बाजार में भी काफी परिवर्तन आया है। उद्योग क्षेत्र में कार्यस्थल, रोजगार की प्रकृति, कार्य घंटे तथा औद्योगिक संबंधों में परिवर्तन आए हैं। उदारीकरण, वैश्वीकारण एवं निजीकरण के कारण श्रम बाजार में नई-नई शक्तियों का उदय हुआ है। उपर्युक्त पृष्ठ भूमि में श्रम एवं उससे जुड़े प्रमुख मुद्दों को प्रासंगिक एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया जिसे श्रम कानूनों में परिवर्तन हेतु सुझाव देने का आग्रह किया गया है। यह आयोग इस वर्ष के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा फिर भी वित्तमंत्री ने श्रम कानूनों में सुधार करने की घोषणा क्यों की। यह एक ओर श्रम मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप तो है ही दूसरी ओर विदेशी निवेशकों को आकर्षिक करने हेतु सस्ता एवं घटिया जुमला है। मजदूर की छँटनी हेतु जिस विधेयक लाने की बात वित्तमंत्री ने की है क्या वह विधेयक वित्तमंत्री ला सकते हैं? यदि नहीं तो सरकार वैश्वीकरण के दबाव में इस विधेयक को लाने की बात कह रही है। क्योंकि वित्तमंत्री ने छँटनी के बाद जिस तरह की सुविधाएँ छँटनीग्रस्त कर्मचारियों के लिए घोषित की है उसे कई गुणा अधिक छूट, सुविधाएँ एवं सहुलियत उद्योगपतियों के लिए किया है। यह तय है कि भारत के सभी प्रमुख राष्ट्रीय श्रमिक संगठन इस विषय पर चुप नहीं बैठेंगे।

'सुधार' आज के पाश्चात्य प्रभाव से ग्रस्त बुद्धिजीवियों के लिए एक आकर्षक मंत्र बन गया है। उन्हें व्याप्त हर व्यवस्था में, या भारतीय दृष्टिकोण में खामियाँ ही नजर आता

वस्तु	कस्टम ड्यूटी	
	वर्तमान दर	नयी दर
चाय, कॉफी, नारियल एवं नारियल उत्पाद	३५%	७०%
कच्चा तेल (वनस्पति) रुग्ण उद्योग हेतु	२५%	५५%
पाम तेल (सामान्य)	५५%	७५%
सोयाबीन तेल	३५%	४५%
सूर्यमुखी तेल	३५%	७५%
नारियल तेल	४५%	७५%
मूंगफली तेल	३५%	७५%
सरसो तेल	३५%	७५%
अन्य तेल	३५%	७५%
पाम तेल रिफाइन्ड	६५%	८५%
नारियल तेल रिफाइंड	४५%	८५%
मूंगफली तेल रिफाइंड	४५%	८५%
अन्य तेल	४५%	८५%
पुरानी कार	—	१८०%

है। वर्तमान आर्थिक सुधार की प्रक्रिया से पहले पूंजीवाद था। आज यह शब्द पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया है। एक देश जहाँ बेरोजगारों की संख्या लाखों में हो, वहाँ सभी को रोजगार देने के अलावा, चाहे वह कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, नहीं हो सकता। इतना ही नहीं हर क्षेत्र में बिना किसी निमंत्रण के सरकार द्वारा विदेशी 'इक्वीटी' की भी इजाजत देना उचित नहीं है। यह बात वैश्वीकरण के विरुद्ध है तो अपना क्या जाता है। कौन वैश्वीकरण की चिंता करता है। क्या उत्तरी देश ऐसा करते हैं?

विनिवेश की मरीचिका

सुधार के बाद से सरकार देश के प्रमुख सार्वजनिक कंपनियों को बेचकर उसका उपयोग वित्तीय घाटा कम करने में करती है। १९९६ से अबतक जितनी बार भी विनिवेश के लक्ष्य तय किए गए थे उसमें केवल दो बार ही लक्ष्य हासिल किया जा सका है। वैश्वीकरण के शक्तियों को आर्थिक सुधार के पुरोधा के रूप में अपने को प्रदर्शित करने का मुगालता पाए वित्तमंत्री ने पिछले आँकड़ों को देखना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष २००१-२००२ के लिए विनिवेश से प्राप्त धन राशि का लक्ष्य १२००० करोड़ रुपए रखा है। कुल २७ सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से यह राशि आने वाली है।

विनिवेश का लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ रु०)	प्राप्ति (करोड़ रु०)
१९९९-२०००	१०,०००	१८२१
२०००-२००१	१०,०००	२५००
२००१-२००२	१२,०००	—

सरकार जिस प्रकार विनिवेश की प्रक्रिया अपना रही है एवं उसके विरोध में मजदूर आंदोलन तेज हो रहे हैं उसको देखकर तो स्पष्ट है कि सरकार इस बार भी वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएगी। परिणाम उधारी फिर से बढ़ेगी, विकास दर नीचे आएगी और मुद्रा स्फीति बेकाबू हो जाएगा।

कार बनाम उपभोक्ता सामग्री

देश में स्वदेशी कार उद्योग को वैश्वीकरण के बाद विदेशी कार कंपनियों के आने के बाद काफी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। देश में माँग एवं मूल्य को नियंत्रित रखने में ही इन कंपनियों की क्षमता खत्म हो जाती है। तुलनात्मक रूप से स्वदेशी गाड़ियों का मूल्य विदेशी कारों के मामले में कम है। अत: प्रयुक्त हो चुकी कारों पर १८०% तक कस्टम ड्यूटी निश्चित रूप से भारत में जो विदेशी कार निर्माता कंपनियाँ हैं उनको फायदा पहुँचाने के लिए किया गया है क्योंकि पुरानी विदेशी कारें जब यहाँ आएंगी तो उनका मूल्य काफी कम होगा, वे अच्छी हालत में भी होगी। अब अगर अच्छी हालत में पुरानी विदेशी गाड़ी कम कीमत पर यहाँ मिलती है तो यहाँ बनने वाली महँगी विदेशी कारें कौन खरीदेगा? लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।

दूसरी तरफ ३१ मार्च, २००१ को ७१ वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंध की अवधि खत्म हो रही है। हालाँकि सरकार ने उनपर कस्टम ड्यूटी तो बढ़ाई है लेकिन वे अपेक्षित मात्रा में नहीं है। किसी भी उपभोक्ता सामग्री

एवं कृषि उत्पाद वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी ७५% से ऊपर नहीं किया गया है, जबकि विदेशों में मात्रात्मक प्रतिबंध से निपटने के लिए कस्टम ड्यूटी की सीमा २०० प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। (सारणी सलंग्न)

दवा उद्योगों पर मूल्य नियंत्रण हटाने की घोषणा से केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा होगा। शोध एवं अनुसंधान पर लागत राशि पर १५०% की छूट के प्रावधान से बड़े-बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ लाभान्वित होगी। पेटेंट कानून के तहत शोध से प्राप्त नई औषधियों के स्वामित्व का लाभ होने का फायदा जहाँ उन कंपनियों को होगा वहीं सरकार द्वारा प्राप्त छूट का भी फायदा उन्हें मिलेगा।

कृषि क्षेत्र : कहने भर को राहत

लघु एवं सीमांत किसानों को अपने कृषि उत्पादन एवं इसके भंडारण के लिए सरकार बाजार एवं एफ.सी.आई. का गोदाम उपलब्ध कराता था। लेकिन वर्तमान में सरकार ने कृषि राज्य सरकारों का मुधा है कहकर अपना पल्ल झाड़ लिया है। पहले

कृषि उत्पादन

मद	१९८०-८१ १९९१-९२	१९९१-९२ १९९९-२०००
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	३.९	३.६
पशुपालन एवं डेयरी	४.२	३.७
वानिकी	-०.१	०.८
मत्स्य पालन	५.४	५.५

अच्छी फसल होने की स्थिति में किसानों की अच्छी कीमत तो मिल जाती थी लेकिन फसल खराब या बर्बाद होने की स्थिति में सरकार द्वारा कम से कम समर्थित मूल्य प्राप्त होने की उम्मीद तो जरूर रहती थी। लेकिन वित्तमंत्री ने निगम को संग्रह एवं वसूली के काम से अलग रहने को कहा है। परिणामस्वरूप किसान अब कम कीमत पर अपने अनाज को बेचने को या तो बाध्य होगा या फिर अनाज को सड़ने देगा या फिर आत्महत्या करेगा।

ज्ञातव्य हो कि कृषि कार्य अब बढ़ते पूँजी निवेश, तकनीकी बातों पर आधारित हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में बैंकों से प्राप्त ऋण एवं फसलों के बर्बाद से जाने के बाद ऋण चुका न सकने के कारण कई किसान आत्महत्या कर चुके है। इस वर्ष पिछले वर्षों की अपेक्षा लगभग १२००० करोड़ रुपए का इजाफा वित्तमंत्री ने इस क्षेत्र के लिए किया है जो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

आर्थिक सुधारों के बाद भी कृषि की विकास दर में कमी आयी है। सरकार सुधार के नाम पर कृषि और बिजली के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में कमी करती आयी है। नहरों, जलाशयों आदि के रखरखाव पर प्रतिकूल असर पड़ा एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के अभाव के कारण उत्पादन घटा। धन के अभाव में तकनीकी उन्नयन का भी अभाव रहा।

समय पर संसाधन उपलब्ध न होना किसान की मुख्य समस्या है। उसे संस्थागत ऋण न मिल पाने के कारण बाजार से ऋण लेना पड़ता है। १९८७ में बैंक जहाँ कुल ऋण का १९.१ प्रतिशत कृषि क्षेत्र को देते थे वही मार्च १९९९ में घटकर यह ११.८ प्रतिशत रह गया। ■

पंजाब में फिर एक किसान ने आत्महत्या की

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अगली कतार के प्रान्त पंजाब में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी है। कपास की खेती करनेवाले किसानों द्वारा कर्ज में डूब जाने के कारण आत्महत्या करने की कई घटनाएँ सामने आई थी। अब गन्ने की खेती भी आत्महत्या का कारण बन रही है।

पंजाब की सरकारी नीतियों ने गुर्नेकलन, बुद्धलाड़ा के तीस वर्षीय किसान चमकौर सिंह की जान ले ली। चमकौर सिंह के पास १९८८ के पहले अच्छी जमीन-जायजाद थी। लेकिन बुद्धलाड़ा में जब किसानों की उपजाऊ जमीन सरकार ने चीनी मील खोलने के लिए अधिग्रहण किया तो किसानों को मुआवजा और नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। अधिकांश खेतिहर किसानों के पास कोई डिग्री तो होती नहीं है कि उन्हें कुर्सी मेज पर बैठकर काम करने वाली नौकरी मिल सके।

उनकी सबसे बड़ी योग्यता अपनी खेत से अधिक से अधिक उत्पादन की होती है हालाँकि यह कोई छोटी योग्यता नहीं है। फिर चीनी मील के लिए जमीन ले ली जाने के बाद चमकौर सिंह की योग्यता बेकार हो गई। उन्हें खेती के बदले चीनी मिल में ट्रैक्टर चालक के सहायक की नौकरी मिली। किसान तो अपनी सम्पत्ति का छोटा ही सही एक बादशाह होता है। क्या गुजरा होगा इस नौकरी को करते हुए चमकौर सिंह के स्वाभिमानी मन पर? इसे सोचा जा सकता है। पंजाब की सरकार ने तो गन्ना मील खोलकर चमकौर सिंह जैसे किसानों को नीचे गिरा दिया। लेकिन यह किस्सा आगे चलकर और दर्दनाक तब हुआ जब चीनी मील भी बन्द हो गई। सरकार ने १९९९ में कर्मचारियों को फालतू मान हटा दिया। जमीन गई अब वेतन भी बन्द हो गया। पाँच वर्ष तक किसी तरह परिवार का भरण पोषण करने के बाद जब चमकौर सिंह पूरी तरह टूट गया आखिर मजबूर होकर उसे आत्महत्या कर लेनी पड़ी।

कौन है इस या उन तमाम किसानों की आत्महत्या का जिम्मेदार सरकारी नीति? या सरकारी नीति को प्रभावित करनेवाली ताकतें? या विकास की हत्यारी मानसिकता? ■

Scanned with OKEN Scanner

चिंताजनक है देश की अर्थव्यवस्था

बातचीत

२७ फरवरी, २००१ को पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर ने वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, उपभोक्ता सामानों एवं कृषि उत्पादों के अबाध आयात के विरोध में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया। स्वदेशी पत्रिका की ओर से **भोगेन्द्र पाठक** ने उक्त ज्ञापन का संदर्भ लेते हुए श्री चंद्रशेखर से कुछ प्रश्नों के साथ बातचीत की। लगभग उसी प्रकार के प्रश्नों पर आर्गेनाइज़र के पूर्व संपादक, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ विचारक श्री के.आर. मलकानी के भी विचार लिए, जिनके संपादित अंश हम अपने पाठकों के लिए दे रहें हैं।

श्री चंद्रशेखर से

स्वदेशी : *पैसे को केंद्र मानकर अर्थनीति बनाने पर किस प्रकार के विकास की संभावना दीखती है?*

चंद्रशेखर : कोई भी विकास एक ही आधार पर बनता है प्रकृति के जो साधन हैं और जो मानव श्रम हैं – इनके संयोग से नई संपदा पैदा होती है, पैसे से पैसा पैदा नहीं होता। पैसे के साथ अगर प्राकृतिक साधन न हों और मनुष्य की श्रम शक्ति न हो तो विकास का क्रम ठप्प हो जाएगा। हर देश के लिए अलग-अलग विधाएँ हैं जिनके जरिए विकास हो सकता है। हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति जनशक्ति है और प्रकृति ने हमें पर्याप्त साधन दिए हैं। हमें ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे श्रमशक्ति का उपयोग हमारे साधनों पर हो सके। ये काम नहीं हो रहा है इस देश में। केवल पैसे-पैसे से विकृतियाँ पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इससे अमीरी-गरीबी का अंतर बढ़ेगा . . . व्यक्ति-व्यक्ति के बीच बढ़ेगा . . . . अंचल-अंचल के बीच बढ़ेगा . . . हमारे गरीब इलाकों में नए अंचलों के बीच बढ़ेगा . . . . हमारे गरीब इलाकों में नए साधन नहीं जाना चाहेंगे . . . वहाँ विकास नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि दूसरे जो पैसा लगाएँगे वो पैसा हमको देकर धनी नहीं बनाएँगे . . . . पैसा आता है हरदम देशों का या लोगों का शोषण करने के लिए और उस शोषण से विकास नहीं होता। उससे एक तो विषमता बढ़ती है, दूसरे गरीबी बढ़ती है।

स्वदेशी : *दीनदयालजी ने जिस आर्थिक लोकतंत्र की बात की थी उसमें पंचायती स्तर तक आर्थिक लोकतंत्र लाने की बात कही गई है। क्या ऐसी कोई संभावना बनती है?*

चंद्रशेखर : पुराने समय में था कि हम खाना भरपेट खाते थे और पड़ोस को भी खाना देने की बात सोचते थे। संवेदनशीलता, एक-दूसरे से सहयोग, एक-दूसरे के सुख-दुख के भागी होना – यह हमारी परंपरा थी। . . . . तो दीनदयाल जी को जितना मैंने सरसरी तौर पर समझा है . . . . वो यही कहते थे कि वही परंपरा

श्री के. आर. मलकानी से

स्वदेशी : *नई अर्थनीति के संदर्भ में आपकी आपत्तियाँ क्या हैं?*

मलकानी : ये सारे जो संकट शुरु हुए हैं – राजीव गाँधी के जमाने से। उस समय गैट की बात चल रही थी, अमरीका का बहुत ज्यादा दवाब था और राजीव गाँधी एकदम झुक गए। राजीव गाँधी के आखिरी दो साल थे। उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार आ गई, उस समय सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे आदमी वाणिज्य मंत्री हो गए। उसके बाद नरसिम्हाराव की सरकार आ गई – ये सारे समझौते होते गए।

बाहरी दवाब था कि इसमें पेटेंट भी ले आइये, कृषि ले आइये, बीज ले आइये। . . . . तो राजीव गाँधी को अगर सूझबूझ होती, तो विरोध करते, न हिम्मत थी, न दम था, न ज्ञान था; कोरा कागज थे। तो इस तरह हमारे राष्ट्रीय हित के साथ समझौता हुआ और वो चलता रहा चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव के काल में भी।

स्वदेशी : *आपका पं. दीनदयाल जी से सम्पर्क रहा है। वे वैकल्पिक अर्थनीति की बात करते थे। उन दिनों नेहरू जी के खिलाफ बड़ा भारी मुहिम चलता था। दीनदयाल जी की अर्थनीति को आज के संदर्भ में आप कैसे जोड़ेंगे?*

मलकनी : दीनदयाल जी रोजगारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को ही स्वीकार करते। अभी तो बेरोजगारी बढ़ रही हैं, क्योंकि छोटे-छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं। दीनदयाल जी इसे बर्दास्त नहीं करते। राजीव जी ने गलतियाँ की तो सरकार को सबकुछ करना पड़ा। लेकिन उसके दुष्प्रभावों को कई तरीकों से कम किया ही जा सकता है।

स्वदेशी : *ग्राम-पंचायत स्तर तक आर्थिक लोकतंत्र लाने की दीनदयाल जी की जो इच्छा थी – ये कैसे संभव हो सकती है?*

मलकानी : हमारी व्यवस्था बड़ी कमजोर है। कोई योजना होती है तो पहले यह देखा जाता है कि उसमें अधिकारी कौन होंगे, कर्मचारी कितने होंगे, कार्यालय का खर्च क्या होगा – इसकी चिंता

Scanned with OKEN Scanner

इस देश को शाश्वत शक्ति देने की परंपरा है। जब नयी नीति बन रही थी तो मैंने संसद में कहा था कि अबाध प्रतियोगिता और संवेदनशीलता – दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं हो सकते। . . . आज हमारे देश में वही हो रहा है। उसका नतीजा यह है कि समाज में दुराव बढ़ रहा है – चाहे वह जाति के नाम पर बढ़े, अमीरी-गरीबी के नाम पर बढ़े या अंचलों के नाम पर बढ़े। इसलिए संकट पैदा हो रहा है। . . . पंचायती स्तर तक आर्थिक लोकतंत्र लाने में सरकार का कोई योगदान नहीं हो सकता, समाज में जबतक लोगों का मन नहीं बदलेगा – तब तक अंतर आने वाला नहीं है।

स्वदेशी : *आनेवाली पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में राजनीति की स्वतंत्र भूमिका कहाँ तक बनी रहेगी?*

चंद्रशेखर : हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें तो उन्होंने साफ कहा है कि अब श्रम कानून में बदलाव लाएँगे। एक हजार लोगों तक की मजदूरी करनेवाली जो कंपनी होगी उसे बंद करने के लिए किसी से परमीशन लेने की जरूरत नहीं होगी।

हमलोगों को अपनी बात समझने के लिए बुनियादी तौर पर देखना होगा . . . .जो लोग चुनकर आते हैं उन लोगों का आचरण अगर ठीक नहीं होगा तो ये संस्थाएँ जो हैं . . . .आप लोग जो कह रहे हैं वो कह रहा हूँ कि तुलसीदास ने कहा –

"मुखिया मुख सो चाहिए खानपान में एक।
पालहिं पोसहिं सबहि अंग तुलसी सहित विवेक।।"

लेकिन, हमारे मुखिया आज चंद लोगों के पालन-पोषण में लगे हुए हैं। जो समाज बना रहे हैं वह पाँच-दस फीसदी के लिए है। पंचायती राज का जो ढाँचा खड़ा कर रहे हैं उससे लोगों को भरमाया नहीं जा सकता है। वे समाज को नई दिशा नहीं दे सकते हैं।

. . . .श्रम की प्रतिष्ठा आवश्यक है। . . . यहाँ तो जो बड़ा आदमी हो जाता है, चाहे वह हमारे जैसा नेता हो या उद्योगपति हो, चाहे कोई लेखक हो – वह काम नहीं करता; श्रम करना उसके लिए सबसे बड़ा अपराध हो जाता है।

स्वदेशी : *नई आर्थिक नीति के संभावित दुष्प्रभावों के प्रति लगभग सभी दलों और संगठनों के लोग बहुत-सी समान राय रखते हैं। ऐसे लोग एक साथ खड़े हो सकेंगे?*

चंद्रशेखर : प्रयास होना चाहिए; हो सकता है कि नहीं – इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई संगठन नहीं है जिस संगठन को मैं इस्तेमाल करके सब लोगों को एकजुट कर सकूँ। . . . . मैंने पहले कहा था कि एक संस्था फौज की है जिसमें आज भी अनुशासन है, और दूसरी आर.एस.एस. की है जो देश को टूटने से बचाएगा और इसलिए जब बाला साहब देवरस ने कहा था कि हम स्वदेशी के लिए संघर्ष करेंगे तो हमने उनका समर्थन किया था। ■

खूब रहती है – लेकिन इसकी चिंता कम रहती है कि काम कितना होगा। उल्टा पिरामिड वाली स्थिति हो जाती। काम नीचे तक जाता है, नहीं जाता है – किसी को चिंता नहीं। काम सीधे पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर होना चाहिए, लेकिन काम की शुरुआत होती है योजना आयोग से। जो लोग ऊपर बैठे हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक महीना भी गाँव में गुजारा है। गाँव के लोगों को क्या परेशानी है – इसका लोगों को पता नहीं है।

स्वदेशी : *देश की समुचित अर्थव्यवस्था के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे।*

मलकानी : जो बाहरी दवाब आज है – उसे कम करना होगा। अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन पर हस्ताक्षर हो गया – छुट्टी हो गई। अंतरराष्ट्रीय समझौता के पहले उसका खुला मूल्यांकन होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन अगर सबके सामने आता तो उसे स्वीकृति नहीं मिलती और अगर मिलती भी तो शर्तों के साथ। उल्टे हम विश्व व्यापार संगठन से बाहर की चीजों को भी स्वीकृति दे देते हैं। ■

एनरॉन परियोजन रद्द हो

२८ फरवरी २००१ को स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय ऊर्जा कार्य दल की ओर से श्री अनिल गचके ने एनरॉन पर गठित पुनर्विचार समिति, मुम्बई के अध्यक्ष श्री माधवराव गोडबोले को डी.पी.सी. पावर प्रोजेक्ट के संदर्भ में ज्ञापन दिया जिसके मूल मुद्दे थे–

१. स्वदेशी जागरण मंच कपटपूर्ण एवं अनावश्यक एनरॉन पावर प्रोजेक्ट का घोर विरोधी रहा है।
२. डाभोल पावर प्रोजेक्ट में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता नहीं दिखती।
३. उत्पादित बिजली देश में सबसे मंहगी होगी।
४. एनरॉन को स्वीकृति देने वाली समिति के सदस्य कीर्ति पारीख को पुनर्विचार समिति में नहीं रखा जाए।
५. एनरॉन परियोजना का सही व्यय भारतीय और विदेशी निर्माताओं द्वारा आंका जाए।
६. एनरॉन पी.पी.ए. के लाभांश नियम के अनुसार ३९ प्रतिशत लाभ पा सकता है।
७. पी.पी.ए. के अनुसार अगले २० वर्ष के लिए ऊर्जा का मूल्य निर्धारित किया जाए।
८. ग्राहक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और महाराष्ट्र सरकार के हित में इस परियोजना को रद्द करने का प्रस्ताव दिया जाए।
९. हमें बहस के लिए बुलाया जाए ताकि हम अपनी सभी बातों का सप्रमाण खुलासा कर सकें।

Scanned with OKEN Scanner

दृष्टिकोण

स्वदेशी की कसौटी पर खरा नहीं है बजट २००१-२००२

■ डॉ. अश्विनी महाजन

अपने पूर्व के वित्त मंत्रियों की तरह यशवंत सिन्हा भी आँकड़ों के जाल में वास्तविकता को छुपाने का प्रयास करते दिखाई दिए। कृषि क्षेत्र जिससे ७० प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता हो और सरकारी नीतियों में अवहेलना के कारण जो लगातार कमजोर होता जा रहा हो उसे इस बजट में पहले से भी बुरा व्यवहार मिला।

किसी ने कहा कि यह ड्रीम बजट है, तो किसी ने कहा कि यह बोल्ड बजट है। किसका ड्रीम (सपना) यह पूरा करता है या किसके लिए यह बोल्ड है, कम-से-कम मुझे समझ नहीं आया। अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि किसी सरकार का वार्षिक बजट उस सरकार की वर्ष भर की आर्थिक नीतियों का दर्पण होता है। देश के समक्ष खड़ी समस्याओं को दूर करने हेतु उपाय बजट द्वारा जुटाए जाते है। लेकिन बजट का सूक्ष्म अध्ययन हमें यह बताता है कि ऐसा कोई प्रयास बजट में हुआ नहीं। हालाँकि वित्त मंत्री ने यह कहकर अपनी पीठ थपथापाई कि आर्थिक विकास की दर भूमंडलीकरण के बाद औसत रूप से ६.४ प्रतिशत रही। जबकि यह १९८० के दशक में यह मात्र ५.८ प्रतिशत थी। लेकिन साथ में यह भी स्वीकारा गया कि इस वर्ष यह दर ६ प्रतिशत के आसपास रहने वाली है। गरीबी को तथाकथित रूप से कम करने का श्रेय भी वित्त मंत्री ने लिया। लेकिन देश के समक्ष मुँहवायी समस्याओं की तरफ वित्त मंत्री विमुख दिखाए दिए। क्या हैं वह समस्याएँ –

१. लगातार घटती कृषि उत्पादन की दर और किसानों की भारी समस्याएँ।
२. विदेशियों का अर्थव्यवस्था पर बढ़ता प्रभाव।
३. ढाँचागत क्षेत्र, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ती सरकारी भूमिका और उसकी शिकार आम जनता।
४. विश्व व्यापार समझौते से उत्पन्न स्थितियों जैसे – समाप्त होते मात्रात्मक नियंत्रण, विदेशी माल की अंधाधुंध डम्पिंग, नई पेटेंट व्यवस्था इत्यादि।

कृषि और बजट

अपने पूर्व के वित्त मंत्रियों की तरह यशवंत सिन्हा भी आँकड़ों के जाल में वास्तविकता को छुपाने का प्रयास करते दिखाई दिए। कृषि क्षेत्र जिससे ७० प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता हो और सरकारी नीतियों में अवहेलना के कारण जो लगातार कमजोर होता जा रहा हो उसे इस बजट में पहले से भी बुरा व्यवहार मिला। अपने बजट अभिभाषण में वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण से लेकर प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना तक कई विषयों की चर्चा की, और कुछ ऐसा लगा कि शायद इस बजट में कृषि पर कोई बहुत ध्यान दिया गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जहाँ पिछले बजट में योजना व्यय का ८.७६ प्रतिशत कृषि एवं ग्रामीण विकास पर खर्च का प्रावधान था। इस बार वो घटकर मात्र ७.८५ प्रतिशत रह गया है। वित्त मंत्री जी को सलाह है कि भविष्य में जनता के समक्ष सच्चाई को आँकड़ों के मकड़जाल में छुपाने का प्रयास न करें। वैसे वित्त मंत्री द्वारा फूड प्रोसेसिंग उद्योग को उत्पाद शुल्क से मुक्त किया जाना स्वागत योग्य कदम माना जा सकता है।

विदेशी निवेश और बजट

पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि जिस उद्देश्य से विदेशी निवेश को अनुमति देने की बात की जा रही थी कि विदेशी निवेश के द्वारा देश में ढाँचागत क्षेत्र में प्रगति होगी उत्पादन के नए आयाम खुलेंगे, पिछले दस वर्षों के घटनाक्रम ने उसे झूठ सिद्ध कर दिया है। ढाँचागत क्षेत्र में जो विदेशी निवेश हुआ है वह एनरॉन जैसी परियोजनाओं में हुआ है। पिछले कुछ समय से एनरॉन द्वारा बिजली के भारी बिलों और अन्य प्रकार के प्रकरणों से ढाँचागत क्षेत्र में विदेशी निवेश की सरकारी नीति की कलई खुल चुकी है। इसलिए कोई सरकार खुद को ढाँचागत क्षेत्र से अलग रखने की नीति द्वारा जनता को भरमा नहीं सकती।

उद्योगों में निवेश केवल अधिग्रहण के रूप में हुआ है और पहले से स्थापित भारतीय उद्योग विदेशी आधिपत्य में चले गए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक अब पहले से कही ज्यादा भारतीय शेयर बाजार पर हावी होते जा रहे हैं और आम निवेशक शेयर बाजार से बाहर होता जा रहा है। इस बजट में वित्त मंत्री ने फिर से विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किसी एक कंपनी में पोर्टफोलियो निवेश की सीमा को ४० प्रतिशत से बढ़ाकर ४९ प्रतिशत कर दिया है। गैर-बैंकीय वित्त कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा १०० प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। बजट के इन दोनों प्रावधानों से देश के संसाधनों पर विदेशी आधिपत्य बढ़ेगा। गैर-बैंकीय कंपनियों में विदेशी

Scanned with OKEN Scanner

निवेश की १०० प्रतिशत की छूट हमारे छोटे बचतकर्ताओं के जोखिम को और बढ़ाने वाली होगी।

सामाजिक सेवाओं में सरकार की भूमिका

चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य या हों नागरिक सुविधाएँ, निजी क्षेत्र की भूमिका इनमें अधिक नहीं हो सकती और अगर होती भी है तो यह आम नागरिक विशेषतौर पर गरीब लोगों के लिए अहितकारी होती है। खेद का विषय है कि यह जान लेने के बाद भी कि ऊर्जा के क्षेत्र में निजी/विदेशी भागीदारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही और न ही भविष्य में रहने वाली है, वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र के लिए विशेष प्रयास इस बजट में नहीं किया।

ऊर्जा के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता को भी तथाकथित ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों के साथ जोड़ दिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से हल करने का प्रयास करना होगा। सामाजिक सेवाएँ जिसमें शिक्षा और जन-स्वास्थ्य प्रमुख है, पिछले बजट में मात्र १८.६ प्रतिशत प्राप्त कर पाए। इस बार भी सामाजिक सेवाओं पर मात्र १८.८ प्रतिशत खर्च का ही प्रावधान रखा गया है। इसमें भी इन क्षेत्रों में कोई सुधार की अपेक्षा नहीं है क्योंकि बजट में बढ़ा हुआ प्रावधान पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन वृद्धि में जाने वाला है।

विश्व व्यापार संगठन और बजट

जबकि देश का हर क्षेत्र चाहे कृषि हो या लघु उद्योग विश्व व्यापार संगठन से उपजी समस्याओं से त्राहि-त्राहि कर रहा है। वित्त मंत्री द्वारा इस संबंध में बजट में अपेक्षित प्रयासों का अभाव रहा। हालाँकि तिलहनों और खाद्य तेलो पर आयात शुल्क तो बढ़ाया गया है लेकिन सबसे अधिक आयात होने वाले सोया तेल पर आयात शुल्क पूर्व की भाँति ४५ प्रतिशत ही रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि समझौते के अनुसार यह अधिकतम आयात शुल्क है। लेकिन याद रखना होगा कि १९९९-२००० के वर्ष में सोयाबीन तेल का आयात ४२,००० करोड़ रुपए मूल्य का रहा। जिससे तिलहन की खेती पर अत्याधिक बुरा प्रभाव पड़ा और भारत अब तिलहन और खाद्य तेलों के लिए विदेशों पर आश्रित देश बन कर रह गया है। सरकार की यह मजबूरी सरकारी अधिकारियों के दावों को सर्वथा झूठ सिद्ध करती है कि विश्व व्यापार संगठन से देश के किसानों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उधर जब १ अप्रैल, २००१ से सभी आयातित वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंध उठा लिए जाएंगे, वित्त मंत्री द्वारा देश के मुर्गीपालन, डेरी और अन्य क्षेत्रों में पड़ने वाले दुष्प्रभावों के संबंध में उदासीनता दिखायी गई है। मुर्गीपालन उद्योग का कहना है कि अमरीका से मुर्गे की टाँगों के आयात के कारण श्रीलंका का मुर्गीपालन उद्योग लगभग समाप्त हो चुका है, मात्रात्मक नियंत्रण हटाने से भारतीय मुर्गीपालन उद्योग की भी वही दुर्दशा होगी। हालाँकि वित्त मंत्री द्वारा १०० प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की बात कही गई है लेकिन मुर्गीपालन उद्योग इसको पर्याप्त नहीं मानता। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में अधिकतम आयात शुल्क ३०० प्रतिशत हो सकता है। जबकि एक ओर किसान दूसरी ओर लघु उद्योग विनाश के कगार पर खड़े है। वित्त मंत्री आर्थिक सुधारों के दूसरे दौर की बात करना शुरू हो गए हैं और यही नहीं पहले से ही विदेशी माल की मार से ग्रस्त लघु उद्योगों को अब अनारक्षण की मार भी सहनी होगी। उल्लेखनीय है कि भूमंडलीकरण से पहले ८३७ वस्तुएँ लघु उद्योगों के उत्पादन के लिए आरक्षित थी जिसमें से २४ वस्तुओं को पहले से ही अनारक्षित किया जा चुका है और इस बजट में वित्त मंत्री ने दस और वस्तुओं को अनारक्षित करने का संकल्प लिया है। गौरतलब है कि लघु उद्योगों के आरक्षण का विषय वित्त मंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ■

मुर्गीपालन उद्योग का कहना है कि अमरीका से मुर्गे की टाँगों के आयात के कारण श्रीलंका का मुर्गीपालन उद्योग लगभग समाप्त हो चुका है, मात्रात्मक नियंत्रण हटाने से भारतीय मुर्गीपालन उद्योग की भी वही दुर्दशा होगी।

विश्व बैंक का बढ़ता हस्तक्षेप

भारत में जिस प्रकार आर्थिक सुधार की प्रकिया तेज हो रही है विश्व बैंक उसी तीव्रता से भारत में हस्तक्षेप कर रहा है। यह बैंक भारत के कुछ राज्यों में आर्थिक सहायता देने के बदले वहाँ के शासन, कानून एवं प्रशासनिक ढाँचे में मनचाही तब्दीलियाँ कराने पर दबाव डाल रहा है। देश के संप्रभुता को सीधे चुनौती देकर उसने कितने राज्यों को जो पैसा के लिए लालायित हैं बजट घाटा पूरा करने का प्रस्ताव रखा है। आजादी के बाद के इतिहास की यह पहली घटना है कि विश्व बैंक केन्द्र सरकार की अवहेलना कर सीधे राज्य सरकार से बातचीत की है। यह सहायता लेने में आंध्रप्रदेश, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश की सरकारे आगे है।

ज्ञातव्य हो यह सहायता केन्द्र के जरिए मिलती है एवं इसका उपयोग विकास कार्यों, धार्मिक उद्देश्यों एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए दी जाती है। लेकिन विश्व बैंक केन्द्र सरकार के द्वारा न आकर सीधे राज्य सरकारों पर दबाव डाल रही है। उड़ीसा सरकार पर विश्व बैंक ने आर्थिक मदद के बदले स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तीव्रता से लागू करने की शर्त रखी है। यह खुशी की बात है कि उड़ीसा के आकस्मिक निधि आयुक्त ने इस शर्त पर मदद को रोक दिया है।

विश्व बैंक का मदद राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से भी खतरनाक है। आर्थिक मदद के नाम पर यह बैंक ऐसी परियोजना को लागू करवाने का दबाव बनाते हैं जो किसी भी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय हित में नहीं है। आर्थिक मदद पाने के लिए श्री चन्द्रबाबू नायडू विवादास्पद सांख्यवाहिनी परियोजना को लागू करने की प्रतिबद्धता विश्व बैंक को दे रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि संघ परिवार की आपत्ति के कारण इस परियोजना को केन्द्र ने नामंजूर कर दिया था। राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा आर्थिक मदद पाने को लालायित ये लोग राष्ट्र के सामने मुश्किल पैदा कर रहे हैं। विश्व बैंक के लोगों का अन्तरराष्ट्रीय खुफिया ताकतों, विघटनकारी शक्तियों से संबंध होता है। वे लोग आर्थिक मदद के नाम पर देश को परेशानी में डालने का षडयंत्र करते रहते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

शेयर बाजार : फिर आया तूफान

■ संजय तिवारी

शेयर बाजार के कारण आत्महत्या करने वाले संजय अग्रवाल पहले व्यक्ति नहीं है और शायद आखिरी व्यक्ति भी नहीं हैं। मुंबई के दलाल स्ट्रीट में २८ मंजिली जी जी वाई टॉवर नामक बिल्डिंग को पिछले कुछ सालों में एक तीर्थ की तरह पूरे देश में प्रचारित किया गया है। यह आधुनिक जुआघर अब तक सैंकड़ों जाने ले चुका है, हजारों को बरबाद कर चुका है और लाखों, करोड़ रुपए बरबाद कर चुका है, फिर भी यह स्थान आधुनिक व्यापार का केंद्र बना हुआ है।

दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित एम.आई. फ्लैट में रहने वाले संजय अग्रवाल ने २० मार्च को अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। आत्महत्या स्थल से एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने आत्महत्या के कारणों में लिखा था कि शेयर बाजार में हुए जबरदस्त घाटे ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, अब आत्महत्या के सिवा उनके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था।

शेयर बाजार के कारण आत्महत्या करने वाले संजय अग्रवाल पहले व्यक्ति नहीं है और शायद आखिरी व्यक्ति भी नहीं है। मुंबई के दलाल स्ट्रीट में २८ मंजिली जी जी वाई टॉवर नामक बिल्डिंग को पिछले कुछ सालों में एक तीर्थ की तरह पूरे देश में प्रचारित किया गया है। यह आधुनिक जुआघर अब तक सैंकड़ों जानें ले चुका है, हजारों को बरबाद कर चुका है और लाखों-करोड़ों रुपए बरबाद कर चुका है फिर भी यह स्थान आधुनिक व्यापार का केंद्र बना हुआ है। संजय अग्रवाल भले ही इसके नवीन उदाहरण हों, लेकिन इसकी कड़ी बहुत लंबी है।

यूँ तो शेयर बाजार के केंद्र पूरे देश में फैले हैं, लेकिन इन सबका मुख्यालय मुंबई शेयर बाजार के नाम से विख्यात यही भवन है। इसलिए मार्च के पहले हफ्ते में जब इस भवन में भूचाल आया तो और किसी को चोट लगी हो या न लगी हो मुंशेबा के अध्यक्ष आनन्द राठी जरूर घायल हुए और उन्हें अपने पद से जाना पड़ा। कौन जानता था कि सालभर पहले जब मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक ६००० अंक को पार कर गया था तो उसी जीजीबाई टॉवर की छत से गैस के गुब्बारे हवा में छोड़कर खुशी जाहिर करने वाले श्री राठी की हवा इतनी खराब हो जाएगी कि उनके रिटायरमेंट का समय करीब होने पर भी उन्हें पद से इस तरह हटाया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही; और आजकल वे तथा मुंबई शेयर बाजार के १३ दलाल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की जांच का सामना कर रहे हैं। परिणाम क्या आएगा यह तो समय बताएगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि श्री राठी को हटाना पड़ा – इस मामले पर एक नजर डालना ठीक होगा।

२८ फरवरी को वित्तमंत्री के बजट भाषण का शेयर बाजार पर इतना सकारात्मक असर हुआ कि उनके बजट भाषण के समाप्त होते-होते मुंबई शेयर बाजार १७५ अंकों की छलांग लगा गया। लेकिन पांच दिनों के अंदर ही शेयर बाजार सूचकांक ४००० के भी नीचे चला गया। वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) हैरान हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेयर बाजार औंधे मुँह गिर पड़ा। वित्त मंत्रालय ने सेबी को छानबीन का आदेश दिया। छानबीन के शुरुआती दौर में ही यह पता चला कि अचानक हु

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) आम बजट पेश होने के बाद शेयर मूल्यों में आयी तीव्र गिरावट में दलालों पर गड़बड़ी के आरोपों के संबंध में की जा रही जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट मध्य अप्रैल तक पूरा कर लेगा।

प्रारंभिक रिपोर्ट के काम को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसे अप्रैल के दूसरे सप्ताह में सरकार को सौंपना है। लेकिन पूरी जांच पड़ताल के लिए काफी समय लग सकता है, क्योंकि अन्य उभरते तथ्यों पर एक-एक बिंदु पर विचार किया जाना है। 'केवल एक घटना पर अधिक समय तक काम नहीं किया जा सकता। जांच के दायरे में हमें सभी कारणों तक जाना है। जांच-पड़ताल और उसे क्रियान्वित करने में इतना समय लग जाता है कि कार्रवाई का कोई अर्थ नहीं रह जाता। देरी मुख्यत: उच्च अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई के निश्चित निर्देशों के अभाव के कारण होती है। बीपीएल, स्टरलाईट के शेयरों में कृत्रिम तेजी की नियामक संस्था ने जांच की और चार माह के भीतर जांच रिपोर्ट दे दी। जांच पड़ताल का काम जुलाई-अक्टूबर १९९८ के दौरान किया गया और बिग बुल हर्षद मेहता और कंपनी अधिकारियों समेत १८ दलालों को इसमें इंगित किया।

इसके बावजूद हम १८ दलालों को बर्खास्त और कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों को हटा नहीं पाए। अब तक भी कंपनी के प्रवर्तक और हर्षद मेहता के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पायी है। जांच-पड़ताल अंतरराष्ट्रीय स्तर की थी और जांच-पड़ताल के तथ्यों से शेयर कारोबारियों पर कठोर प्रभाव पड़ सकता था, लेकिन अभी तक यह मामला अधिकारियों के समक्ष आगे की कार्रवाई के लिए लंबित है।

Scanned with OKEN Scanner

यह मंदी वास्तविक नहीं बल्कि कृत्रिम थी जिसके पीछे शेयर बाजार के ही कुछ लोगों का हाथ था। इन कुछ लोगों में मुंशेबा के अध्यक्ष आनंद राठी की ओर भी उंगुलियाँ उठने लगीं। इस समस्या में आनंद राठी की भूमिका इसलिए भी संदिग्ध लगने लगी क्योंकि मुंशेबा की सतत चौकसी व्यवस्था (सर्वेलियंस सिस्टम) इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहरायी जाने लगी। पूर्वतया कम्प्यूटरीकृत इस विभाग में सभी शेयर दलालों की वित्तीय सीमा वर्ग होती है। सीमा पार होने की स्थिति में दलालों का ट्रेडिंग टर्मिनल स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा ताकि उक्त दलाल अपनी जमा राशि से संलग्न निर्धारित सीमा से अधिक कारोबार न कर सके। इस व्यवस्था के अंतर्गत शेयरों के भाव में असामान्य उतार चढ़ाव की जानकारी भी मिलती रहती है। ताकि सावधानी बरती जा सके। नियमः शेयर बाजार का अध्यक्ष भी नियमित तौर पर इस विभाग के संपर्क में रहते हैं ताकि किसी संभावित समस्या के आने के पूर्व ही उस पर अंकुश लगाया जा सके। श्री राठी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने इसी अधिकार का दुरुपयोग करते हुए बजट के तीसरे दिन बाजार बंद होने के ठीक एक घंटे पहले श्री राठी ने चौकसी व्यवस्था में फोन करके बाजार की ताजा स्थिति की जानकारी मांगी। मिली जानकारी में उन्हें पता चला कि कुछ बड़े दलालों के कामकाज में असामान्यता नजर आ रही है, तो नियमानुसार उन्हे यह जानकारी गुप्त रखते हुए आगे कदम उठाना चाहिए था, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने मिली जानकारी को दलालों में लीक कर दिया। परिणामस्वरूप धड़ाधड़ ऊपर चढ़ रहा शेयर बाजार में अचानक बिकवाली की ओर मुड़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि पाँच दिनों के अंदर ही १ मार्च को सूचना तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों के शेयर में ३६७७० करोड़, मनोरंजन क्षेत्र में ३१२४.२१ करोड़, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में २१७१.८७ करोड़, ऊर्जा क्षेत्र में ९५२.०२ करोड़ एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में ६८१.२८ करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गयी। यह बिकवाली इस कदर बढ़ी कि कुछ ही दिनों में कोलकाता शेयर बाजार में भुगतान संकट

बहरहाल यह पूरा खेल एक नाटक सरीखा चला। कहा जा रहा है कि शेयर बाजार में आयी इस अचानक मंदी के पीछे शेयर बाजार के दूसरे हर्षद मेहता केतन पारीख का भी हाथ है। केपी के नाम से मशहूर केतन पारीख जिस शेयर पर हाथ रख देता है उसके भाव आसमान छूने लगते हैं और इस मंदी के पीछे उसकी यही मंशा एक कारण बनी। इन दिनों उसकी रुचि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में बढ़ गयी तो उसके दाम आसमान छूने लगे।

पैदा हो जाने की खबरें आने लगीं। और सेबी के कुछ अधिकारियों को वहाँ जाकर स्थिति का सामना करना पड़ा।

बहरहाल यह पूरा खेल एक नाटक सरीखा चला। कहा जा रहा है कि शेयर बाजार में आयी इस अचानक मंदी के पीछे शेयर बाजार के दूसरे हर्षद मेहता केतन पारीख का भी हाथ है। केपी के नाम से मशहूर केतन पारीख जिस शेयर पर हाथ रख देता है उसके भाव आसमान छूने लगते हैं और इस मंदी के पीछे उसकी यही मंशा एक कारण बनी। इन दिनों उसकी रुचि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में बढ़ गयी तो उसके दाम आसमान छूने लगे। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में उसकी रुचि के कारण हैं – कीर्ति पारीख की दर्जन भर से अधिक कंपनियों के खाते ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में ही हैं और दूसरी ओर उसने बैंक से ३०० करोड़ रुपए उधार ले रखे हैं। इसी तरह जी टेलीफिल्म्स के शेयर भाव गिरे तो उसके पीछे भी के०पी० की ही अरुचि थी।

बहरहाल शेयर बाजार रूपी जुएघर को व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित करने का खामियाजा देर-सवेर देश को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसे में सेबी जैसी नियामक को और दुरुस्त करने की जरूरत है जो शेयर बाजार के दलालों पर लगाम कस सके। इससे शेयर बाजार के नियमन में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही सामान्य निवेशकों को भी सुरक्षा मिलेगी। इस हेतु लंबे समय के पूँजी बाजारों के कंपनीकरण व डीम्यूचुअलाइज़ेशन की व्यवस्था की जा सकती है जैसा कि राष्ट्रीय शेयर बाजार ने किया है। ■

सेबी को और अधिक शीघ्र

केंद्र सरकार ने शेयर बाजारों में इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रभावी रोक लगाने और छोटे शेयर निवेशकों को ज्यादा सुरक्षा देने के लिए भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) को शीघ्र ही और ज्यादा अधिकार देने जा रही है। इसकी पूर्व तैयारी के रूप में केंद्र सरकार द्वारा दो अधिसूचनाएँ जारी की गयी हैं। ये हैं छोटे शेयरधारकों के निदेशक की नियुक्ति और दूसरी इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल विद डिफरेन्शिएल वोटिंग राइट्स। इन दोनों अधिसूचनाओं के कारण अब शेयर बाजार में कोई भी सूचीबद्ध कंपनी छोटे शेयरधारकों की तरफ से नियुक्त निदेशक की सलाह के बिना निर्णय नहीं ले सकती और दूसरा अब उन सभी कंपनियों को शेयर जारी करने का अधिकार मिलेगा जो किसी तरह की दोषी नहीं है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार १९९२ में गठित भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) को और कौन-कौन से अधिकार दिए जाएँ, इस पर अभी अध्ययन चल रहा है। इसके लिए अमरीकी संस्था फेडरल सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के सारे अधिकारों का अध्ययन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसर अमरीकी संस्था को वहां के शेयर बाजार को नियंत्रित करने हेतु असीमित न्यायायिक अधिकार प्राप्त हैं और किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल को यह मनमाफिक निर्देश दे सकती है। भारत में सेबी को यह अधिकार अभी नहीं है। हर्षद मेहता प्रतिभूति कांड के बाद सेबी की स्थापना की गयी थी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 'सेबी' के नए अधिकारों को एक पखवाड़े के भीतर नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। फिलहाल इस कड़ी में केंद्रीय कंपनी मामलों के विभाग के कंपनी कानून १९५६ की धारा ६४२ के तहत यह उपबंध जोड़ दिया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

यदि पूँजी की भाँति श्रम का मूल्य घटा दिया जाएगा तो श्रमिक मर जाएँगे। जहाँ पूँजी का मूल्य घटता जाता है वहीं श्रम का मूल्य पूर्ववत् बना रहता है। इसलिए उद्यमियों के लिए यह लाभकारी होता जाता है कि वे पूँजी का अधिक प्रयोग करें तथा श्रम का कम। नतीजा यह होता है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ बेरोजगारी बढ़ती है। हिन्दुस्तान लीवर द्वारा भारी मात्रा में पूँजी लगाकर सस्ती लाइफबॉय साबुन बनाई जा सकती है।

गरीबी का नियंत्रण नहीं, निवारण चाहिए

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

विश्व बैंक गरीबी को लेकर बहुत चिंतित है। बैंक मुक्त बाजार से गरीबी अवश्य ही उत्पन्न होती है। बैंक स्वयं गरीबी का जनक है। परंतु यह गरीबी विस्फोट न हो जाए इसलिए बैंक गरीबी नियंत्रण पर खर्च बढ़ाने का सुझाव देता है। अन्न वितरण, पेंशन, स्वास्थ्य एवं बेरोजगारी बीमा जैसी योजनाओं के लिए भारी मात्रा में ऋण भी देने को तैयार है। परंतु बैंक उस मुक्त बाजार को छोड़ने को तैयार नहीं है जो गरीबी उत्पन्न करता है। बैंक चाहता है कि एक तरफ मुक्त बाजार गरीबी उत्पन्न करता रहे और दूसरी तरफ हम अपने धन को उसके नियंत्रण में बर्बाद करते रहें। हमें यह समझना होगा कि बाजार पर नियंत्रण करके गरीबी की समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सकता है। हमें बाजार के मोहपाश से निकलना होगा और गरीबी नियंत्रण पर खर्च करने के स्थान पर गरीबी के उत्पादन को ही बंद करना होगा।

पहले मुक्त बाजार से गरीबी का उत्पादन अनिवार्य क्यों है – इसे समझें। बाजार में सस्ती वस्तु की मांग बढ़ती है और महंगी वस्तु की मांग घटती है। आर्थिक विकास का अर्थ होता है पूँजी का संचय। पूँजी के अधिक होने से पूँजी का मूल्य घट जाता है और उस पर ब्याज दर गिरती जाती है। विकसित देशों में ब्याज दर ६-७ प्रतिशत है; चूँकि वहाँ पूँजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विकासशील देशों में ब्याज दर १०-१५ प्रतिशत है क्योंकि वहाँ पूँजी की कमी है। स्पष्ट है, अधिक पूँजी होने पर ब्याज दर गिरती है। पूँजी की तरह श्रम का मूल्य घटता नहीं रह सकता है। श्रमिक को दिन में २४०० कैलोरी भोजन, कपड़ा, मकान सब चाहिए ही। यदि पूँजी की भाँति श्रम का मूल्य घटा दिया जाएगा तो श्रमिक मर जाएगा। जहाँ पूँजी का मूल्य घटता जाता है वहीं श्रम का मूल्य पूर्ववत् बना रहता है। इसलिए उद्यमियों के लिए यह लाभकारी होता जाता है कि वे पूँजी का अधिक प्रयोग करें तथा श्रम का कम। नतीजा यह होता है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ बेरोजगारी बढ़ती है। हिन्दुस्तान लीवर द्वारा भारी मात्रा में पूँजी लगाकर सस्ती लाइफबॉय साबुन बनाई जा सकती है। सस्ती लाइफबॉय के सामने अनेक छोटे साबुन के कारखाने बंद [illegible] गए। यदि वे श्रमिकों का वेतन कम [illegible] सकते तो वे भी अपनी साबुन का दाम [illegible] देते। परंतु चूँकि वेतन कम होने पर श्रमि[illegible] मर जाएगा; इसलिए छोटे कारखानों ने साबु[illegible] बनाना ही बंद कर दिया। श्रमिक बेरोज[illegible] हो गया। ऐसी स्थिति में श्रमिक के साम[illegible] केवल दो विकल्प हैं : या तो वह अप[illegible] वेतन में कटौती स्वीकार करे अथवा व[illegible] बेरोजगार हो जाए। इसलिए उसकी गरी[illegible] बढ़ना अनिवार्य है। हाँ मुट्ठी भर श्रमिक [illegible] लाइफबॉय बनाते हैं उन्हें अवश्य कुछ ला[illegible] हो सकता है।

हमारे सामने दो विकल्प हैं। एक य[illegible] कि बाजार के उपरोक्त चरित्र पर नियंत्र[illegible] स्थापित किया जाए। पूँजी के उपयोग प[illegible] प्रतिबंध लगाकर यह सुनिश्चित किया जा[illegible] कि पर्याप्त मात्रा में श्रम की मांग बाजार मे[illegible]

पलब्ध हो। दूसरा रास्ता यह है कि लोगों को रोजगार होने दें तथा उन्हें अन्न वितरण आदि ीबी नियंत्रण कार्यक्रमों से राहत पहुँचाएं।

विश्व बैंक का कहना है कि रोजगार वश्य उत्पन्न करना चाहिए, परंतु बाजार पर तिबंध लगाकर नहीं। हिन्दुस्तान लीवर पर तिबंध लगाने को बैंक तैयार नहीं है। बैंक ा कहना है कि बाजार के अंतर्गत रहते हुए ीबों को ऋण, सड़क, बिजली आदि लब्ध कराकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हिए। बैंक यह भी कहता है कि रोजगार न को प्राथमिकता देने की आवश्यकता ीं है। अन्न वितरण जैसे गरीबी उन्मूलन र्यक्रम को बराबर की प्राथमिकता देनी हिए।

बैंक की इस सोच में दो कमियाँ हैं। ; यह कि ऋण, सड़क और बिजली लब्ध होने पर गरीबो को रोजगार उपलब्ध जाएगा यह निश्चित नहीं है। संभव है कि सब सुविधाओं के बावजूद पूँजी-आधारित उद्योग ही सफल हों। शहरों में छोटे ुन के कारखाने बंद हो गए, यद्यपि उन्हें ग, सड़क और बिजली उपलब्ध थी। दी के लिए ऋण उपलब्ध होने पर भी ाई मिल ही जाती रही है। दूसरी कमी यह कि अन्न वितरण में ही देश का धन ाप्त हो सकता है। तब सड़क नहीं बनेगी र रोजगार के अवसर उत्पन्न ही नहीं होंगे। ब सदा गरीब ही रह जाएगा।

विनोबा ने कहा था कि यदि देश में जगारी और गरीबी दूर करनी है तो बुनाई कार्य हथकरधा क्षेत्र के लिए आरक्षित कर ा चाहिए। सभी पावर लूम तथा कपड़ा मिलों वंद कर देना चाहिए। कताई मिलों में हो ु बुनाई हथकरधा पर। अवश्य ही इससे ड़ा महंगा होगा। परंतु पूरे देश के बेरोजगारों काम मिल जाएगा। गरीबी दूर हो जाएगी। ु ऐसा करने के लिए पूँजी पर अंकुश ाना होगा। पूँजी को बुनाई के लाभ से वंचित ना होगा। जनता को भी महंगा कपड़ा ीदने पर मजबूर करना होगा। इसके लिए श्व बैंक कतई तैयार नहीं है।

बैंक का कहना है कि गरीब को ऋण, ड़क तथा बिजली जैसी सुविधाएँ उपलब्ध ानी चाहिए। इस सुझाव का स्वागत है। परंतु यह पर्याप्त नहीं है। कारण यह कि उसे बाजार से टक्कर लेना होगा। ऋण, सड़क तथा बिजली उपलब्ध होने से बुनकर का कपड़ा २० रुपए प्रति मीटर के स्थान पर १५ रुपए में उपलब्ध हो सकता है। परंतु यदि मिल का कपड़ा १० रुपए में उपलब्ध हो तो उस ऋण की क्या सार्थकता रह जाएगी? हमें इस सत्य का सामना करना होगा कि पूँजी तथा श्रम का युद्ध यदि खुले बाजार में होगा तो पूँजी की ही जीत होगी। यदि श्रम श्रमिक को देश के चिंतन के केंद्र में रखना है तो मुक्त बाजार पर अंकुश लगाना ही होगा। पूँजी तथा उपभोक्ता के लाभ को कम किए बिना श्रमिक का उद्धार संभव नहीं है।

इसका यह अर्थ नहीं है कि बाजार को पूर्णतया नकार दिया जाए। बाजार की सार्थक भूमिका है। बैंक ने हाल में जारी अपने सामाजिक क्षेत्र की रणनीति संबंधी अपने दस्तावेज में बाजार की सही व्याख्या की है। कहा है कि "पूर्व के साम्यवादी देशों के अनुभव से यह दिखता है कि बाजार के संकट को प्लानिंग, मूल्य निर्धारण तथा सार्वजनिक इकाइयों के माध्यम से नहीं रोका जा सकता है।" रूस तथा चीन के साम्यवादी माडल वास्तव में फेल हो चुके हैं। परंतु उसके अनुभव से विनोबा की बात नहीं कटती है। बाजार में कुछ विशेष प्रतिबंध तो लगाए ही जा सकते हैं। साम्यवादी देशों ने गलती यह की कि बाजार को पूर्णतया नकार दिया। पूँजीवादी देश बाजार को स्वच्छन्द छोड़ दे रहे हैं। दोनों ही गलत हैं। आवश्यकता इस बात की है कि बाजार की सार्थक भूमिका को स्वीकार करते हुए उसे नियंत्रण में रखा जाए। घोड़े को न तो जूए में बाँधना चाहिए न ही उसे स्वच्छन्द छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार घोड़े पर लगाम लगाई जाती है उसी तरह बाजार में पूँजी के प्रयोग पर लगाम लगानी चाहिए।

बैंक ने हाल में जारी अपने सामाजिक क्षेत्र की रणनीति संबंधी अपने दस्तावेज में बाजार की सही व्याख्या की है। कहा है कि "पूर्व के साम्यवादी देशों के अनुभव से यह दिखता है कि बाजार के संकट को प्लानिंग, मूल्य निर्धारण तथा सार्वजनिक इकाइयों के माध्यम से नहीं रोका जा सकता है।"

सरकार को चाहिए कि अध्ययन कराए कि आवश्यक संख्या में रोजगार उत्पन्न करने के लिए हल्की से हल्की लगाम कौन-सी है? बुनाई, साफ्ट ड्रिक्स, चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि अनेक क्षेत्रों का अध्ययन करना चाहिए। जिस क्षेत्र में पूँजी पर न्यूनतम प्रतिबंध लगाकर पर्याप्त मात्रा में रोजगार उत्पन्न हो सके उन पर प्रतिबंध लगा देने चाहिए। साथ-साथ गरीब को ऋण, सड़क तथा बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। तब ही देश के हर नागरिक को रोजगार मिलेगा और उसकी गरीबी दूर हो सकेगी अन्यथा नहीं।

बैंक और हमारी सरकार ऐसा प्रतिबंध लगाने को तैयार नहीं है इसलिए हमें मान कर चलना चाहिए कि देश में गरीबी बरकरार होगी। बैंक के चिंतन में दूसरी कमी सरकारी खर्च में प्राथमिकता की है। बैंक का यह कथन सही है कि केवल अवसरों का सृजन करना पर्याप्त नहीं है। यदि नदी के पार स्कूल बना दिया जाए और पार जाने के लिए पुल नहीं हो तो स्कूल निरर्थक है। इसी तरह ऋण, सड़क तथा बिजली के साथ-साथ गरीबों को कानूनी सहायता, जीवनयापन के अवसरों की सूचना, अंतरराष्ट्रीय बाजार से माल बेचने की सुविधा, अन्न वितरण, पेंशन, स्वास्थ्य एवं बेरोजगारी बीमा आदि के माध्यम से सक्षम बनाना चाहिए ताकि वह उन अवसरों का लाभ उठा सके। परंतु सवाल प्राथमिकता का है। विकासशील देशों की सरकार के पास सब कुछ कर पाने के लिए असीमित धन नहीं है। यह तो सत्य करना ही होगा कि प्रमुख खर्च कौन सा है : सड़क अथवा अन्न वितरण।

सड़क प्राथमिक है। यदि कपड़ा की मांग ही नहीं तो सड़क बनाने से क्या होगा? यदि स्कूल ही नहीं तो पुल बनाने से क्या होगा? इसलिए सरकार को पहले जीविकापार्जन के अवसरों का सृजन करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

समस्या विकट इसलिए है कि हमारी सरकार विश्व बैंक के द्वारा ऋण प्राप्त करने के लालच में अपना स्वयं का पैसा भी बर्बाद कर रही है। चूँकि बैंक अन्न वितरण आदि के लिए ऋण देने को तैयार है इसलिए सरकार भी उसी दिशा में चल निकलती है। नतीजा यह होता है कि बाजार पर नियंत्रण की तो बात दूर; रोजगार के अवसर भी नहीं उत्पन्न होते हैं।

वास्तव में हमारी प्राथमिकता इस प्रकार होनी चाहिए – (१) पूँजी पर न्यूनतम प्रतिबंध लगाकर अधिकतम जीविकोपार्जन के अवसरों का सृजन करना; (२) सड़क तथा बिजली जैसी बुनियादी संरचना में निवेश करना; (३) विशेष परिस्थितियों में दलितों, आदिवासियों, भूकम्प पीड़ितों आदि की इन्हीं बुनियादी संरचना के बनाने के बहाने अन्न वितरण में मदद पहुँचाना। इसके विपरीत बैंक का कहना है कि पूँजी पर प्रतिबंध कत्तई नहीं लगाना चाहिए तथा सड़क को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। बैंक के सुझाव का नतीजा यह होता है कि एक तरफ पूँजी का बेलगाम घोड़ा गरीबी उत्पन्न करता जाता है। दूसरी तरफ सरकार अन्न वितरण करने में अपना धन खर्च कर बैठती है और उसके पास सड़क बनाने के लिए भी पैसा नहीं बचता है। देश में पूँजी फलती फूलती है और गरीब अन्न वितरण के भरोसे जीवनयापन करता रहता है।

इसी बात को हमारी परम्परा में धर्म का अर्थ पर अंकुश के माध्यम से कहा गया। नियम था धर्म-अर्थ-काम। उपभोग इस तरह से करो कि पूँजी ओर समाज की हानि न हो। अर्थ को इस तरह से सिद्ध करो कि समाज भी फले फूले। परंतु विश्व बैंक का फार्मूला काम-अर्थ-धर्म का है। अधिकाधिक उपभोग करो। पूँजी का नाश हो तो भी उपभोग करो। पूँजी को पूरी छूट दो। यदि पूँजी के आतंक से समाज टूटता है तो उस पर अन्न वितरण करके मरहम पट्टी कर दो। पूँजी का हित सर्वोच्च रखो। हमारी सरकार को चाहिए कि विश्व बैंक से सुझावों को लेकर भ्रमित न हो। हमें अपनी प्राथमिकताएँ स्वयं निर्धारित करनी चाहिए और अपने पारंपरिक धर्म-अर्थ-काम की प्राथमिकता को कायम रखने का प्रयास करना चाहिए। ■

संयंत्र बनाम षड्यंत्र

■ अजय कुमार

देश की राजधानी दिल्ली में राजनैतिक तापमान फिर एक बार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, कारण कि सन् १९९१ में जारी उदारीकरण की नीतियों के कारण लाभ देने वाली भारत एल्यूमीनियम लिमिटेड (बाल्को) को एक कंपनी स्टरलाइट को ५५५ करोड़ रुपए में बेंच दिया गया। जहाँ एक तरफ कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री इन सौदे में भारी दलाली के लेन-देन की बात कर रहे हैं वही सत्तापक्ष का यह कहना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। सरकार का कहना है कि ईमानदारीपूर्वक विनिवेश की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है जिसे उदारीकरण के नाम पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने प्रारंभ किया था।

सवाल यह नहीं कि बाल्को को ५५५ करोड़ में बेंचने के कारण भारत पर कोई बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। बल्कि सवाल यह खड़ा हो रहा है कि केंद्र सरकार चाहे तत्कालीन हो या वर्तमान वह किस प्रकार से देश की संप्रभुता को गिरवी रखती जा रही है। उसकी सीधी और स्पष्ट झलक बाल्को के विनिवेश की प्रक्रिया को प्रारंभ करने से मिलती है क्योंकि इसे तत्कालीन भारत सरकार द्वारा ही सन् १९९३ में किए गए एक समझौते से मिलता है। जिसमें केंद्र बिंदु में एक तरफ उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार थी और दूसरी तरफ नरसिंहराव के नेतृत्व वाली सरकार थी। कारण था एन.टी.पी.सी. का उत्तर प्रदेश पर बिजली का लगभग ८००० करोड़ रुपए बकाया। जिसे देने में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने को असमर्थ घोषित कर दिया था। फिर तत्कालीन ऊर्जा राज्य मंत्री कल्पनाथराय और मुलायमसिंह के बीच यह समझौता हुआ कि चूँकि उत्तर प्रदेश पर एन.टी.पी[.सी.] का लगभग ८००० करोड़ रुपए बका[या है] और उसे देने में यह सरकार असम[र्थ है] अत: एन.टी.पी.सी. के बकाए ८००० [करोड़] रुपए में बदले में हम उत्तर प्रदेश सा[रकार] द्वारा नियंत्रित ४५० मेगावाट की क्षमता [वाली] ऊँचाघर तापीय बिजली परियोजना को [एन.] टी.पी.सी. के बकाए पैसे के बदले उसे [दे देते] है और इस प्रकार उक्त समझौते के [तहत] ऊँचाघर तापीय परियोजना एन.टी.पी.सी. [के] हवाले कर दिया गया।

कहने का तात्पर्य यह है कि [जब] बाल्को को मात्र ५५५ करोड़ रुपए में [बेचा] गया तो स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार [की] इस विनिवेश प्रक्रिया का विरोध [किया] क्योंकि उसे लगता था कि यह नियम [विरुद्ध] है। क्योंकि जहाँ एक तरफ १९९३ में ४५० मेगावाट की क्षमता वाले स्टेशन [को] ८००० करोड़ रुपए में एन.टी.पी.सी. [को] बेंचकर उसे घाटे में लाने का प्रयास [किया] जा रहा है वही दूसरी तरफ लाभ देने [वाले] सार्वजनिक उपक्रम बाल्को को मात्र [५५५] करोड़ रुपए में बेंचने का सरकार का [निर्णय] किसी के गले नहीं उतर रहा है। [क्योंकि] बाल्को संयंत्र में एल्यूमीनियम फैक्[ट्री के] साथ-साथ एक ५०० मेगावाट क्षमता [का] बिजली संयंत्र भी है। अब प्रश्न यही होता है कि अगर १९९३ में ४५० मे[गावाट] के स्टेशन को एन.टी.पी.सी. को ८[०००] करोड़ रुपए में बेचा जाता है तो [५००] मेगावाट के पॉवर स्टेशन को बाल्को में शामिल करते हुए सन २००१ में ५५५ करोड़ रुपए में बेचना यह कुछ [ऐसे] बिन्दु है जो सरकार के नीतियों पर [प्रश्न] उठाते है। सरकार को इन दोहरी नीतियों [का] जवाब देना ही होगा क्योंकि यह राष्ट्[र की] समृद्धि से जुड़ा हुआ मामला है।

Scanned with OKEN Scanner

आज सम्राट अशोक जीवित होते तो.....

■ डॉ. प्रमोदकुमार दुबे

आज सम्राट अशोक जीवित होते तो उन्हें कालिंग विजय के रक्तपात से हुई घृणा और विरक्ति के बाद केवल शांति का विश्व संदेश नहीं सुझता – उनकी नजर एक बार फिर तलवार की धार जा टिकती। उन्हें भगवद्गीता ही प्रासंगिक लगती। उन्हें एकांगी विरक्ति का खोखलापन दिखाई दे जाता। उन्हें भीष्म की वीरगति का रहस्य ज्ञात हो जाता, उन्हें स्वधर्म की समझ हो जाती।

भगवान बुद्ध की प्रतिमा को बड़े परिश्रम से अमीर-उल-मोमिनीन व अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के अमीर काने मुल्ला मोहम्मद उमर के फतवे पर नेस्तनाबूद किया गया। २६ जनवरी को गुजरात में भूकंप ने कहर ढाया था। ठीक एक माह बाद २६ फरवरी को मुल्ला उमर के फतवे ने भी कहर बरपा किया। यह भी भूकंप से कम नहीं कहा जा सकता। इस कहर में जन की हानि भले नहीं हुई हो, मन की हानि जरूर हुई। लाखों मन टूटे-कुचले-पीसे। लेकिन, मुल्ला उमर ने मूर्तिभंजन का काम नहीं रोका।

बामियान में हिन्दूकुश पर्वतमाला में बनी बुद्ध की विशाल प्रतिमा का अतीत कितना गौरवशाली था, इस बात से मुल्ला उमर को क्या मलतब? बुत काफिरों की चीज हैं, काफिर बुत को इज्जत बख्शते हैं। अल्लाह ही पवित्र हैं और बाकी सब नेस्तनाबूद कर देने लायक है – रेडियो शरिआ से जारी उमर के फरमान के मुताबिक यही सही है। एक दुआ मेरी भी, यह है कि उमर की उम्र बेहिसाब लम्बी हो। किस काम के लिए? बड़े खतरनाक काम के लिए। शायद उमर वह काम करने में सफल हो जाएँ तो वह संसार में सदा याद किए जाएँगे। काम यह है कि भगवान बुद्ध ने कुछ उपदेश दिए हैं – ईसा से ५४४ वर्ष पहले, उन उपदेशों को जहाँ कहीं मुल्ला उमर देखें – चाहे वे उपदेश किसी भी धर्मग्रंथ के भीतर क्यों न दिखें, उनका सफाया कर दिखाएँ। मसलन, सारे पापों से दूर रहना, सभी अच्छी बातों को जमा करना, मन को पवित्र करना, हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार और मादक व्यसनों से दूर रहना आदि। गृहस्थों के लिए दिए हुए बुद्ध के इन उद्देश्यों की जरूरत अब रही भी क्या? उन्होंने शील-सद्व्यवहार को मनुष्य जीवन की प्रगति का मूलाधार बताया था, यह ढाई हजार वर्ष पुरानी धारणा हो गई। इसे अब रखने की जरूरत क्या है?

बुद्ध ने बताया था कि निंदा, कठोरवचन, अहंतापूर्ण आचरण, लोभ, ईर्ष्या, मिथ्या दार्शनिक मत छोड़ देना चाहिए। उन्होंने स्वयं इस प्रकार के आचरण किए, कठोर तप करके इन शील और संयमों को प्राप्त किया। कैसा कठोर संकल्प था उनका? उन्हीं के शब्दों में देखिए – 'इसी आसन पर मेरा शरीर सूख जाए चमड़ा, हड्डी और मांस विलीन हो जाएँ। अनेक कल्प में जो ज्ञान दुर्लभ है उसे बिना पाए इस आसन से यह शरीर न हिले।' उन्होंने संकल्प लिया था, 'तप के विघ्नों का नाश करके मैं काम ध्वंसक बनूँगा, मैं मृत्यु पर विजय पाऊँगा और सत्-चित्-आनन्द ही मेरा शरीर होगा'–

नाशयित्वा तपोविघ्नान् कामध्वंसी भवाम्यहम्।
मृत्युंजयो भविष्यामि सच्चिदानंद विग्रहः॥

सच्चिदानंद विग्रह हो जाने के बाद बुद्ध ने उपदेश दिए थे। उन्होंने तत्कालीन आडम्बरों का विरोध किया, पशुबलि को उद्वेग का कारण बताया। उन्होंने अपने उपदेशों को आर्य सत्य (अरिय सच्च) कहा और वैदिक ब्रह्मविद्या को नए रूप में स्थापित किया।

उन्होंने कहा था, 'अतः भिक्खुओ! मैंने एक प्राचीन मार्ग देखा है, ऐसा प्राचीन मार्ग जो कि पुरातन काल के पूर्ण जागृतजनों द्वारा अपनाया गया था – उसी मार्ग पर मैं चला। और उस पर चलते हुए मुझे कई तत्वों का रहस्य मिला। वही मैंने भिक्षु-भिक्षुणियों, नर-नारियों और दूसरे सर्वसाधारण अनुयायियों को बताया।' इस कथन के अनुसार बुद्ध के उपदेश की प्रमाणिकता पर आशंका नहीं की जा सकती। बुद्ध ने धर्म के वास्तविक रूप को ही पुनर्स्थापित किया था। इन उपदेशों में धर्म के आदि और निरंतर मान्य तत्वों का समावेश है। यदि मुल्ला उमर इन उपदेशों के सर्वथा विपरीत किसी धर्मपंथ का रास्ता निकाल सकें तो यही बुद्ध की प्रतिमा का वास्तविक विध्वन्स माना जा सकता है। यह काम खतरनाक इसलिए है कि 'सत्यं वद' – सत्य बोलो के उपदेश को यदि मुल्ला उल्ट कर 'झूठ बोलो' कर दें ताकि बुद्ध की पूज्य विचार-मूर्ति खंडित हो जाए। इस कार्य के बाद जब मुल्ला को भूख लगी होगी और वह अपने धर्मानुसार झूठ बोलेंगे – उन्हें भूख नहीं हैं। नतीजा यह होगा कि सच नहीं बोलने के कारण उन्हींकी भूख उन्हें कब्र तक ले जाने में मदद करेगी। सच बोलना यदि धर्म है तो इसलिए कि वह जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसा धर्म जो जीवन विरोधी हो, सर्वस्वीकृत नहीं हो सकता।

बुद्ध के उपदेशों का ऋण विश्व के

Scanned with OKEN Scanner

सभी धर्माचरण पर है। सभी धर्म प्रवक्ता जो भी उपदेश करते आए हैं, उनमें बुद्ध के उपदेश होते ही हैं। यदि उन्हें बौद्ध धर्म के जन्म के बाद उपजे सभी धर्मग्रंथ से निकाल दें तो कोई उचित उपदेश नहीं बचेगा।

बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने ईश्वर की अलग से कोई स्थापना भी नहीं की। ऐसा नहीं था कि वह परम सत्ता की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बने थे। उनकी अलौकिता में बारबार परम सत्ता मुखरित हो रही थी। फिर भी उन्होंने ईश्वर की अलग से घोषणा नहीं की। उन्होंने अर्निवचनीय का बोध स्वयं करने के लिए अनुयायिओं को केवल मार्ग दिया कि वे उस परमतत्व को जानें। उसे केवल तर्क-वितर्क का विषय न बनावें।

परम सत्य का साक्षातकार कर लेने के बाद वह आनंद के उल्लास में बोल पड़े थे, ''मैंने पा लिया, मैं इस अमृत की धारा को संतप्त संसार में बहा दूँगा। अब जरा, मरण और रोग का भय संसार से मिट जाएगा।'' उन्होंने जिस परमतत्व का बोध किया, उसे उन्होंने 'कारणचक्र' नाम दिया था। कारण चक्र की निर्भ्रान्त शब्दावलियों से मनुष्य को निर्बोध आस्था से मुक्त करने के लिए उपदेश दिए। तत्कालीन समय में ये उपदेश अत्यंत विकसित बौद्धिकता के प्रमाण बने। इससे पूर्व की जड़ताएँ टूटीं। जड़ीभूत आस्थाओं के बंधन से मुक्त हो वही सनातन धर्म-बोध नए रूप में विश्वव्यापी बन गया।

इस दर्शन में कोई प्रतीक ऐसा नहीं था, जिसे विशेष समाज के लोग ही समझें और स्वीकारें। इसमें किसी देश की सांस्कृतिक विरासत को क्षतिग्रस्त करने वाले तत्व नहीं थे। सबने अपनी-अपनी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में इस मत को स्वीकार किया। तर्कसंगत-निर्मल-अभेद परमधर्म की इस करुण धारा ने विश्व जनजीवन को एक नई चेतना से भर दिया।

आज बुद्ध के उपदेश ज्ञात-अज्ञात कितने रूपों में किन-किन भाषाओं – संस्कृतियों में प्रवाहित हो रहा है उन्हें खोजकर अलग करना कठिन है। और यह खोज भी अनावश्यक है। फूलों की सुगंधि तो हवा में व्याप्त हो जाती है। उसे हवा से पुनः निकल कर फूलों में समा जाने की इच्छा नहीं होती। विश्वात्मा की फुलवारी सदा ऐसे सुगंधित

विश्व-मानस के वैकासिक इतिहास में सर्वत्र सुगंधि बन व्याप्त हुए बुद्ध की विचारमूर्ति को मुल्ला उमर तोड़ सकें तो बड़ा काम होगा।

फूलों से भरी रहे। वाणी और कर्मों की ऐसी सुगंधि सर्वात्मा में विर्सजित होकर आनंद बनती रहे, मात्र इतने से ही संपूर्णता की अनुभूति हो जाती है।

विश्व-मानस के वैकासिक इतिहास में सर्वत्र सुगंधि बन व्याप्त हुए बुद्ध की विचारमूर्ति को मुल्ला उमर तोड़ सकें तो बड़ा काम होगा। पत्थरों-पहाड़ों को किन्हीं लोगों ने काट-तराश कर मूर्तियाँ बनाई और किन्हीं लोगों ने तोड़ दिया – इससे क्या सचमुच बुद्ध या बुत का अंत हो गया? वास्तव में यह बुद्ध का अंत नहीं है, काफिरों का अंत नहीं है बुत परस्तों का सफाया नहीं है। बुद्ध के वास्तविक अंत के लिए मुल्ला फिर सोंचे।

विश्व संस्कृति के चिंतक आजकल सभ्यताओं के आपसी द्वंद्व का गणित लगाने में लगे हैं। उनके विश्लेषण में बुद्ध प्रतिमा का विध्वंस मनुष्य जाति की वैचारिक उत्था... का ध्वंस हो सकता है, संवेदनावि... हिंसकवृत्ति का उदाहरण हो सकता... आर्थिक समीकरणों को संसार की गतिशी... का ईंधन मानने वाले विचार-विश्लेषक... भूमंडलीकरण के और पूँजीवाद के दायं... देख सकते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद... इतिहास दृष्टि इस विचारमंथन की व्याख्या... सहयोग दे सकती है। इन सभी के साथ... स्वयं भगवान बुद्ध के 'कारणतत्व' की... नितांत लौकिक व्याख्या अनगढ़ रूप में... हो सकती है तो उससे भी कुछ रहस्य... सकते हैं।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाजशा... की पढ़ाई आरंभ करने वाले, 'सोसल ए... कल्चरल डाइनेमिक्स नामक पुस्तक... सुप्रसिद्ध लेखक, रूस के तौरिया नामक... में जन्मे पित्रिम सोरोकिन (१८८९ - १९... ई०) के संस्कृति संबंधी विचारों के आ... में अफगानिस्तान में ध्वस्त किए गए... प्रतिमा के विषय में विश्लेषण प्रस्तुत क... उचित लग रहा है।

सोरोकिन ने संस्कृति को दो अंश... बाँटकर देखा। एक अंश को इंद्रिय... संस्कृति कहा, दूसरे अंश को विचार... संस्कृति। उन्होंने इन दोनों को मिलाकर... सर्वग्राह्य सक्षम संस्कृति की अवधारणा... व्याख्या भी प्रस्तुत की थी। इस अवधारणा...

आधार था सार्थक समन्विता का सिद्धांत (लॉजिकोमीनिगफुल इंटिग्रेशन)।

विचारपरक संस्कृति के व्यक्ति निष्ठावान, इंद्रिय वांक्षाओं से ऊपर, अभौतिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी तृप्ति बहुत थोड़े सुख-साधन में हो जाती है। इनके जीवन का ध्येय ऊँचे विचार, श्रेष्ठ कला-रचना और दर्शन का निर्माण करना होता है। इससे विपरीत इंद्रियपरक संस्कृति को अनुसरण करने वाले लोग किसी अतीन्द्रीय सत्ता में विश्वास नहीं करते। ये इंद्रियों की भूख-प्यास में ही सोंचते-विचारते हैं। यह संस्कृति संसार की व्यवस्थाओं के भीतर ऐसे परिवर्तन के लिए प्रयास करती है जिससे इसे मानने वाले लोग संतुष्ट हो सकें। यह उन्नति की प्रक्रिया नहीं अपनाती।

दूसरी ओर विचारपरक संस्कृति अपने चरम विकास की दशा में वैराग्य की ओर बढ़ने लगती है। जबकि इंद्रियपरक संस्कृति अपने चरम विकास में भोगवाद में केंद्रित हो जाती है। इन दोनों के मध्य एक आदर्श संस्कृति का निर्माण हो सकता है, जिसमें विचारपरक संस्कृति की निष्ठा-नैतिकता अभौतिक जीवन दृष्टि और रचनात्मक शक्ति हो और इंद्रियपरक संस्कृति के सक्रियरूप अर्थात् तकनीकी उन्नति, व्यापार संगठन आदि सम्मिलित हों। सोरोकिन विचारपरक संस्कृति के पलायनवाद और वैराग्य से असहमत हैं और इंद्रियपरक भोगवादी संस्कृति से भी। सोरोकिन यह मानते हैं कि हमारे युग के आधुनिक संकटों का मूल कारण इंद्रियपरक भोगवादी संस्कृति की शक्तिहीन दशा ही है।

सोरोकिन के संस्कृति मानकों से जब हम मूर्तिभंजक प्रवृत्ति के आज के आवतरण का विश्लेषण करते हैं, यह ज्ञात करने के लिए कि इन प्रवृत्तियों को संस्कृति की किस कोटि में रखना चाहिए – इंद्रियपरक में अथवा विचारपरक में? तब एक धार्मिक व्यवस्था का ओट होने के कारण सीधे विश्लेषण करने में बाधा आती है। फिर भी अफगानिस्तान की वर्तमान संस्कृति-निर्माण में इंद्रियपरक संस्कृति के लक्षण ही दिखाई देते हैं। ये अशांत लोग संसार की व्यवस्था में

जाली धर्मों की अंधास्थाएँ आपस में टक्कर मारना शुरू करेंगी और तब इस संकट को दूर करने के लिए किसी अर्निवचनीय ईश्वरीय अवधारणा की मान्यता और उसके प्रवक्ता दर-किनार कर दिए जाएँगे। और तब शील (सद्व्यवहार) और संयम आदि मानवीय आचार की लोक स्वीकृति ही आगे आएगी। उस समय भी भगवान बुद्ध पुनः सामने खड़े मिलेंगे।

वांक्षित परिवर्तन इसलिए चाहते है कि उन्हें भरपूर भोग साधन प्राप्त हों। ये लोग उन्नति के प्रयासों में सक्रिय नहीं है। यदि सक्रिय होते तो बुद्ध की प्रतिमाएँ उनके यहाँ पर्यटन उद्योग का सबसे बड़ा माध्यम होती, उनसे बड़ी

कमाई हो सकती थी। लेकिन नहीं, यह उन्नति उन्हें नहीं चाहिए। मुल्ला ने अभी फिर शरिआ रेडियो से फरमाया है कि मूर्ति तोड़ने में हुए विलम्ब के पापों को धोने के लिए हमें तीन सौ गाएँ काटनी पड़ेंगी। गौमाता की पूजा करने वाले हम काफिर लोग इससे दुःख मनाएँगे-मुल्ला उमर को बुरा कहेंगे, यह स्वाभाविक हैं। पर गाय के गोबर तक में लक्ष्मी का वास मानने वाले हम लोग भी गाय का आर्थिक महत्व स्वयं भूल रहे हैं। हम उमर को क्या सिखलाएँगे। ईसाई दुनिया के लोगों के लिए इस फतवे का कोई महत्व नहीं है। वे लोग 'विफ-अप' होते उमर को धन्यवाद भी नहीं देंगे। पश्चिमी देशों की आर्थिक दृष्टि क्रूर है। फिर भी पश्चिम यही सोंच सकता है कि इन मुल्लों की आर्थिक दृष्टि घटिया है, व्यवसाय करते तो भूखमरी मिटती।

सोरोकिन के संस्कृति विश्लेषण में ऐसे भोगवादियों की चर्चा नहीं है जिनकी इंद्रियपरकता या भोगवाद किसी धर्म के पर्दे में हो। यदि सचमुच हमारे युग के आधुनिक संकटों का मूल कारण इंद्रियपरक भोगवादी संस्कृति की शक्तिहीन दशा ही है तो अफगानिस्तान के वर्तमान तालिबानी संकट के लिए एक अलग सांस्कृतिक भेद जड़वादी संस्कृति बनना होगा। दुनिया के कई देश विविध रूपों में इस संकट से ग्रस्त हो चुके हैं। विश्व की अनेक धर्म-धारणाएँ भी परस्पर विचार-द्वंद्वों में उलझती रही हैं। इन धर्म धारणाओं में निहित शक्तियों का आपसी टकराव भी संकट बन सकता है। दिन-दिन बढ़ती जा रही पतनशील प्रवृत्तियों के कारण मूल धर्म धारणाएँ जीवन-रक्षा की भूमिका से दूर हो जाएँगी। जाली धर्मों की अंधास्थाएँ आपस में टक्कर मारना शुरू करेंगी और तब इस संकट को दूर करने के लिए किसी अर्निवचनीय ईश्वरीय अवधारणा की मान्यता और उसके प्रवक्ता दर-किनार कर दिए जाएँगे। और तब शील (सद्व्यवहार) और संयम आदि मानवीय आचार की लोक स्वीकृति ही आगे आएगी। उस समय भी भगवान बुद्ध पुनः सामने खड़े मिलेंगे।

निश्चय ही बुद्ध प्रेरित समाज दृष्टि में

Scanned with OKEN Scanner

विचारपरक संस्कृति के गुण-दोष ही सामने आते हैं। अर्थात् दृढ़ता, नैतिकता, अभौतिक जीवन की सोंच वैराग्य की ओर विकसित होती हुई दोषग्रस्त भी हो जाती है। सांसारिक साधनों पर जीवनयापन करने के बाद संसार के हित का दायित्व इसलिए बनता है कि मनुष्य-वंश का भविष्य भी बना रहे, वंशधारा कभी रुके नहीं। आगत पीढ़ी को पूरा जीवन जीने का बोध और साधन मिले, सृष्टि की निरंतरता कभी क्षतिग्रस्त न हो। इस प्रकार के विचार से विश्व संस्कृति के मानक रूप की परिकल्पना करने के कारण ही जीवन से पलायन अनुचित सिद्ध होता है। भोग-आशक्त होकर हिंसक बनें हुए लोग संसार के रक्षक नहीं, भक्षक होते हैं, ये तो पलायन करने वाले लोगों से भी बुरे हैं। ऐसी दुरासक्ति को ही विश्व के आधुनिक संकट का कारण माना गया है। यही इन्द्रियपरक भोगवादी संस्कृति के लक्षण हैं। यही ध्वंस का रास्ता है।

विश्व जीवन के सतत् प्रवाह में सनातन मूल्यों को निरंतर बनाए रखने के लिए बौद्धदर्शन के विरुद्ध कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य, उदयनाचार्य जैसे महामनीषियों ने तर्कसंगत कार्य किए थे। इस विशद चर्चा में नहीं जाकर सामान्य भाषा में सनातन धर्म की धारणा को इन शब्दों से समझा जा सकता है – हिंसा से अहिंसा की ओर, विषमता से समता की ओर, विभिन्नता से अभिन्नता की ओर जाना मात्र गति ही है। इस गति में प्रवृत हुए लोगों को मुक्ति मिली। लेकिन इससे स्थिति की उपेक्षा हुई, सत्व के आधार ढहे, क्रमिक जीवन का मार्ग अवरुद्ध हुआ, व्यवस्थाएँ टूटीं।

विभिन्न आकांक्षाओं में जनमे लोगों के कर्मों के आपसी ताने-बाने से बनी हुई संसार की व्यवस्थाएँ क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वैचारिक अंधकार जाता है। सत्व के आधार का नाश होने पर तमस की तीव्र बढ़ोत्तरी होने लगती है। तमस स्थितिशील है यह भोगाकांक्षा से भरा हुआ है। यदि पिछले दो-ढाई हजार वर्ष में जीवन से पलायन की प्रवृत्ति नहीं बढ़ी होती, समग्र जीवन बोध बना रहता तो तमस का वर्तमान रूप इतना प्रचण्ड नहीं होता।

वैदिक मार्ग से प्राप्त समृद्धि के चरम पर आई विकृतियों ने भगवान बुद्ध को नए उपदेश के लिए बाध्य किया। उन्होंने सुदृढ़तम स्थिति को गति प्रदान करने का कार्य किया था। भारत में इतनी संपत्ति थी कि लाखों लोग भिक्षुक हो सकते थे, त्याग-तप के मार्ग पर चल सकते थे। उनके भरण पोषण की व्यवस्था हो सकती थी। रेशम मार्ग से होने वाले भारत के विश्व स्तरीय व्यापार से बामियान का क्षेत्र ही नहीं पूरा देश साधन सम्पन्न हो रहा था। यूँ ही नहीं भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाओं के स्वर्ण अलंकारों की चमक-दमक से सातवीं शताब्दी में आए चीनी यात्री ह्वेन सांग की आँखें चौंधिया गई थीं। तब भारत की सुदृढ़ व्यापार व्यवस्था से

विभिन्न आकांक्षाओं में जनमे लोगों के कर्मों के आपसी ताने-बाने से बनी हुई संसार की व्यवस्थाएँ क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वैचारिक अंधकार जाता है। सत्व के आधार का नाश होने पर तमस की तीव्र बढ़ोत्तरी होने लगती है। तमस स्थितिशील है यह भोगाकांक्षा से भरा हुआ है। यदि पिछले दो-ढाई हजार वर्ष में जीवन से पलायन की प्रवृत्ति नहीं बढ़ी होती, समग्र जीवन बोध बना रहता तो तमस का वर्तमान रूप इतना प्रचण्ड नहीं होता।

अर्जित सम्पत्ति की रक्षा में शक्तिशाली राज्य व्यवस्थाओं का सहयोग खड़ा था।

बौद्धमठों की अपार सम्पत्ति की रक्षा अहिंसा के परमधर्म से नहीं हो रही थी। जीवन के दायित्वों से पलायन कर जाने पपर कोई रक्षा संभव नहीं होती। उन दिनों भी इसके लिए युद्ध का कौशल तत्पर था। पौरुष-वीरता-शौर्य के अर्जित सार्मथ्य पर ही अहिंसा का परमधर्म टिका हुआ था। अर्थात् प्रचूर साधनों के एकत्र हो जाने के बाद दुख की निवृत्त के कारण की आध्यात्मिक खोज होने लगी थी और तब वैराग्य की चरम स्थिति उत्पन्न हुई थी, अहिंसा एवं करुणा का सागर लहरा उठा था और तभी प्रवृत्तियों के भेद का समायोजित रूप – उस काल व्यवस्थाएँ सपाट हो चली थी। रंग-बि बेलबूटों की चमक-दमक पर सफेद बि बिछने लगी। ऐश्वर्य को अध्यात्म-पथ शत्रु माना जाने लगा था। वैराग्य का निर्धारित वय नहीं रहा – वानप्रस्थ अवधारणा ध्वस्त हो गई। तरुण-तरुणियाँ मुण्डित सिर होकर 'धम्म शरणं गच्छामि' उठे। प्रकृति की व्यवस्था निराकार रूप लगी। युद्ध धर्म नहीं, पाप बन गया।

इस उर्ध्वगति का परिणाम सामने आया कि जब कालांतर में तामसि भोगाकांक्षी लूटेरी हिंसक प्रवृत्तियाँ एक मत संगठित हुईं उनके लिए बौद्धों द्वारा उपेक्षि की गई अपार सम्पति साधन के रूप में प्रा होती चली गई। बर्बरता को इससे भा मनोबल मिला। अहिंसा का परमधर्म हिंसक प्रवृत्ति के लोगों के लिए उर्वरक बना। आ सम्राट अशोक जीवित होते तो उन्हें कलिं विजय के रक्तपात से हुई घृणा और विरक्ति के बाद केवल शांति का विश्व संदेश नहीं सुझता – उनकी नजर एक बार फिर तलवा की धार जा टिकती। उन्हें भगवद्गीता प्रासंगिक लगती। उन्हें एकांगी विरक्ति का खोखलापन दिखाई दे जाता। उन्हें भीष्म की वीरगति का रहस्य ज्ञात हो जाता, उन्हें स्व की समझ हो जाती।

बौद्ध पंचशील के आकाश में स्वतं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी शांति के कपोत उड़ा रहे थे। इसका दुष्परिणाम भारत को चीन के हाथों अपनी धरती गवाँकर भोगना पड़ा था यही अनुभव एक दिन परमाणुविक अस्त्रों की आवश्यकता का कारण भी बना।

भारतीय मनीषा केवल उर्ध्व वैराग्य की गति को ही आवश्यक नहीं मानती है अपितु यह स्थितिशीलता और गतिशीलता की स्पर्धा के मध्य समानुशासन से क्रमशील और उन्नत जीवन दृष्टि को स्थापित करती है। गति और स्थिति की स्पर्श से अभिव्यक्त होने वाली संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है। जिसके अन्वेषण और स्थापना की आवश्यकता सोरोकिन जैसे विख्यात चिंतक की परिकल्पना में भी आई थी। जिसमें उन्हें हमारे युग के आधुनिक संकटों का समाधान दिख रहा था। ■

Scanned with OKEN Scanner

इस तथ्य से विमुख नहीं हुआ जा सकता कि कला और विचार का फैलाव दुनिया को समृद्ध करता है, लेकिन जिस तरह धनी देशों, खासकर अमेरिका से इसका चकाचौंध और कूटनीतिजन्य आक्रमण हो रहा है उससे गरीब देशें में समुदाय, रीति और परम्परा का विनाश हो रहा है– फलस्वरूप तथाकथित सांस्कृतिक उत्पाद खरीदने-बेचने में उनकी स्वदेशी धारणा भी विलुप्त हो रही है।

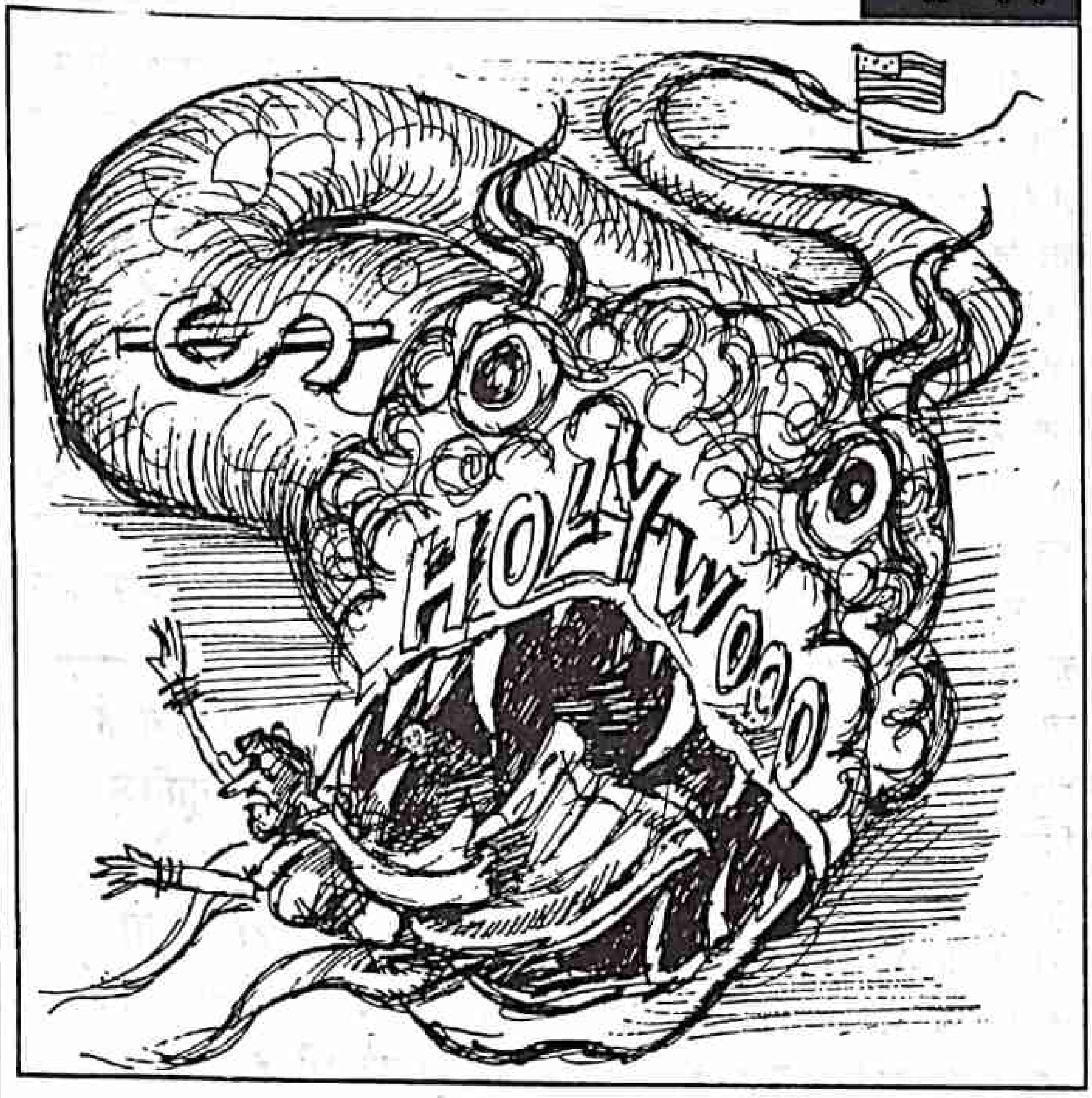

■ भोगेन्द्र पाठक

हॉलीवुड निगलना चाहता है सांस्कृतिक विविधता

आज दुनियाभर के लोगों के विचार, जीवन-मूल्य, जीने के तरीके अभूतपूर्व रूप से गहराते जा रहे हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें नयी संस्कृतियों की जानकारी रोमांचक और बलदायी लगती है; वहीं अनेक ऐसे भी लोग हैं जो तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में पिछड़ जाते हैं और तब उनके हाथों में बच जाती है बेचैनी/कुण्ठा/आत्मग्लानि। इस समस्या का हल गाँधीजी ने हमें बहुत पहले ही बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के दरवाजे बन्द हों, खिड़कियाँ बन्द कर दी जाएँ; मैं चाहता हूँ कि हर देश की संस्कृति की हवा मेरे घर तक मुक्त भाव से आए। साथ ही वे यह भी कहते थे कि किसी भी संस्कृति के झोंके से मैं अपने पैरों को उखड़ने देना नहीं चाहूँगा। लेकिन हमारी तरफ वाह्य संस्कृति के जो झोंके आ रहे हैं– तथाकथित सांस्कृतिक उत्पादों का जो बहाव हो रहा है– उसकी दिशा एकतरफा है और वह बलशाली भी है– उनकी मंशा हमारे पैरों को उखाड़ने की ही है। पूरी दुनिया के स्तर पर देखें तो चिन्ता का विषय यह भी है कि इनका बहाव धनी देशों से गरीब देशों की तरफ है।

शिल्प, संगीत, नाटक (फिल्म), चित्र, पुस्तक आदि को भारतीय संस्कृति कला की कोटियाँ मानती है, विश्वविद्या मानती है, लेकिन पश्चिम के ठेकेदार इसे सांस्कृतिक उत्पाद / सांस्कृतिक माल मानते हैं और संस्कृति के उत्थान एवं फैलाव के लिए इनकी मान्यता आर्थिक वस्तुओं के रूप में देते हैं। इस तथ्य से विमुख नहीं हुआ जा सकता कि कला और विचार का फैलाव दुनिया को समृद्ध करता है, लेकिन जिस तरह धनी देशों, खासकर अमेरिका से इसका चकाचौंध और कूटनीतिजन्य आक्रमण हो रहा है उससे गरीब देशों में समुदाय, रीति और परम्परा का विनाश हो रहा है– फलस्वरूप तथाकथित सांस्कृतिक उत्पाद खरीदने-बेचने में उनकी स्वदेशी धारणा भी विलुप्त हो रही है।

भारत में संस्कृति जीवन-मूल्य के रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि पश्चिमी दुनिया में संस्कृति आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण हो गई है और इसी अर्थ को केन्द्र में रखकर संस्कृति का व्यापार दनदना रहा है। यूनेस्को का एक अध्ययन बताता है कि १९८० और १९९१ के बीच साहित्य, संगीत, दृश्यकला, सिनेमा, छायांकन, मुद्रित सामग्री, रेडियो एवं टेलीविजन के उपकरण का विश्व व्यापार ६७ अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर २०० अरब अमेरिकी डॉलर हो गया; और इसमें वृद्धि हो ही रही है।

मगर चौंकानेवाली बात यह है कि सांस्कृतिक उत्पाद का विश्वव्यापी बाजार अमेरिका की मुट्ठी में केन्द्रित होता जा रहा है– खासकर मनोरंजन व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व ने छोटे-छोटे देशों

के मनोरंजन व्यापार को मुरझाना शुरू कर दिया है। अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग मोटर वाहन या वायुयान या कम्प्यूटर नहीं है, बल्कि फिल्म और टेलीविजन द्वारा तैयार किया गया मनोरंजन है। १९९७ में हॉलीवुड फिल्मों ने दूसरे देशों से तीस अरब अमेरिकी डालर से अधिक कमाया। १९९८ में तो अकेले 'टॉयटेनिक' फिल्म ने अन्य देशों से एक अरब अस्सी करोड़ अमेरिकी डालर से अधिक अर्जित किया।

भारत दुनिया में सबसे अधिक फिल्में बनाता है, लेकिन फिल्म बाजार में हर जगह पहुँच और वर्चस्व हॉलीवुड का ही है और दिनानुदीन हॉलीवुड का आधिपत्य और अधिक होता जा रहा है। १९८० के दशक में बाहर के देशों से हॉलीवुड जितना अर्जित करता था वह उसकी अपनी आय का मात्र ३०% था, जो १९९९ में ५०% से अधिक हो गया। १९८७ में यूरोप के फिल्म बाजारों में हालीवुड की मात्र ५६% हिस्सेदारी थी जो १९९६ में बढ़कर ७०% हो गई। अब इसने लेटिन अमेरिका के फिल्म बाजार का ८०% और जापान के फिल्म बाजार का ५०% से अधिक दबोच लिया है। जहाँ तक अमेरिका में विदेशी फिल्मों के व्यापार की हिस्सेदारी की स्थिति है– वह ३% से भी कम है।

मैक्सिकों ने एक वर्ष १०० से अधिक फिल्में बनाईं, लेकिन हॉलीवुड के फैलते शिकंजे ने १९९५ में मैक्सिकों को ४० फिल्में भी नहीं बनाने दी और १९८० में तो इसकी संख्या १० से भी कम हो गई। १९९० के दशक के मध्य से ही हॉलीवुड के मनोरंजन-उत्पाद का उत्पात इतना बढ़ गया कि मैक्सिको का घरेलू फिल्म उद्योग धूल चाटने लगा। ऐसी दुर्दशा झेल रहे देशों ने सांस्कृतिक उत्पादों को मुक्त व्यापार समझौता से मुक्त करने की गुहार की है, लेकिन उरुग्वे राउण्ड ने किंचित मात्र छूट उपलब्ध कराया और उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (एन.ए.एफ.टी.ए.) ने इस संदर्भ में पहले ठोस बातचीत की आवश्यकता पर बल दे दिया। जापान, ब्रिटेन और अमेरिका सांस्कृतिक उत्पादों को आर्थिक उत्पाद मानते हैं या दूसरी आर्थिक सेवाओं की तरह मानते हैं; जबकि कनाडा और फ्रांस इसकी सुरक्षा, कलात्मक विविधता और राष्ट्रीय पहचान चाहते हैं।

उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी, सी.एन.एन. जैसे विश्वव्यापी मीडिया नेटवर्क, इंटरनेट, मल्टीमिडिया उद्योग, फिल्म, टेलीविजन आदि की विश्वव्यापकता से प्रभावित होकर लोग पूरी दुनिया में फैली ग्राहक-संस्कृति और सांस्कृतिक सजातीयकरण से जुड़ने लगे हैं। विश्वव्यापी ब्राण्ड लोगों की आकांक्षा को

जीवन संस्कृति के प्राण है और पाश्चात्य सांस्कृतिक उत्पाद एवं मनोरंजन में हमारा जीवन नहीं है। तो बिना सांस के जीवन जीने की आशा भी हम कैसे कर सकते हैं। अगर कला के नाम पर ही हम उन्हें स्वीकार करें तो क्या कला मात्र ग्रहण या अनुकरण कर लेने से उपयोगी हो जाती है? जब तक अपनी ओर से अपने जीवन-मूल्य-जनित नवीनता उसमें हम नहीं पिरोयेंगे तब तक वह कला हमारे लिए काल बनी रहेगी।

रूपायित करते दिखते हैं। कैरीबियन का साल्सा संगीत, इथोपिया और थाईलैण्ड का क्वीजंस और अनेक ऐसी परम्पराएँ दुनियाभर में फैल रही हैं। ये भी सच है कि राजनैतिक आन्दोलनों के सहारे क्षेत्रीय संस्कृतियों को भी नया उत्साह मिला है। फिर भी कहना मुश्किल हैं कि विश्व स्तर पर संस्कृति का सजातीयकरण हो रहा है या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि वैश्विक संस्कृति थोपने का एक वैचारिक तरीका है वैश्वीकरण; जबकि दूसरे लोगों की मान्यता है कि पूरी दुनिया में फ़ैल रहे सांस्कृतिक उत्पादों को अलग-अलग ढंग से ग्रहण करते हैं। तक भारत की बात है– हमने वाह्य सं और जीवन मूल्यों को पहले देखा-सुना परखा है, तब पूर्णतः या अंशतः यथा स्वदेशी रंगों में उन्हें स्वीकार किया है। अब हॉलीवुड की फुफकार से फैल विष बॉलीवुड तक धड़ल्ले से पहुँच रहा

जो हम देखते हैं उसे धीरे-धीरे मानने लगते हैं। इसलिए बिना स्वदेशी को फैलाये हम उनका मुकाबला कैसे सकते हैं। हम उन्हें निष्प्रभावी कर सकते अपने मनोरंजन माध्यमों को समृद्ध, ध्येय और चेतनशील बनाकर; इसे विश्वव्य बनाकर और अपने सांस्कृतिक उपादान सांस्कृतिक उत्पाद नहीं, को दुनिया कोने-कोने में पहुँचाकर। भारत की फि कला को चलताऊ फॉरमेट से बा निकालकर और प्रभावी प्रचार कर सौ हर देश तक पहुँचने की जरूरत है। क हमारी सूक्ष्म, सजग, सक्रिय, गहन स्थायी सौन्दर्य-भावना का परिणाम होती जो प्रधानतः आध्यात्मिक होती है उसका लक्ष्य उत्तम जीवन होता है। इसलि हमारी संस्कृति अन्य संस्कृतियों को भटक नहीं है, बल्कि उनका मार्गदर्शन करती और हमारे सांस्कृतिक उपादान उनके लि वरदान से कम नहीं होते। मगर सांस्कृति उत्पाद के नाम पर हमारे यहाँ पश्चिम से संगीत, नृत्य, फिल्म, साहित्य आदि की बह रही है, वह हमारी अनुभूतियों को वि कर रही है– क्योंकि अनुभूतियाँ जीवन परिस्थितियों की भूमिकाएँ होती हैं और संस्कृति वस्तु बनकर हमारे आँगन में आ है उसका हमारे जीवन से कोई सरोकार न है। जीवन संस्कृति के प्राण है और पाश्चा सांस्कृतिक उत्पाद एवं मनोरंजन में हम जीवन नहीं है। तो बिना सांस के जीवन जी की आशा भी हम कैसे कर सकते हैं। अ कला के नाम पर ही हम उन्हें स्वीकार क तो क्या कला मात्र ग्रहण या अनुकरण क लेने से उपयोगी हो जाती है? जब तक अप ओर से अपने जीवन-मूल्य-जनित नवीन उसमें हम नहीं पिरोयेंगे तब तक वह कल हमारे लिए काल बनी रहेगी।

Scanned with OKEN Scanner

कोयला में है तेल संकट का समाधान

■ धीप्रज्ञ द्विवेदी

किसी देश की संप्रभुता उसके ऊर्जा-स्रोतों पर निर्भर होती है, ऊर्जा-स्रोत पर विकास निर्भर होता है, विकास पर देश की जीवनीशक्ति और उसका इतिहास निर्भर होता है। अन्वेषणों से नए ऊर्जा-स्रोतों की प्राप्ति होती है। इससे विकास का नया दौर शुरू हो जाता है और इसीके साथ इतिहास भी करवट बदल लेता है। ऊर्जा-स्रोतों की खोज के लिए तत्पर होना व्यापक अर्थ में देश की संप्रभुता को सबल करना ही है। लगभग तेईस वर्ष पहले वैकल्पिक ईंधन के रूप में अच्छी योजनाएँ बनीं, जिन्हें पेट्रोलियम की लॉबी ने धर दबोचा। इस तरह की घटनाओं से पता चलता है कि देश को खोखला करने वाले ऐसे दीमकों का प्रभाव भी सत्ता में रहा है जो राष्ट्रहित को नापसंद करते हैं। इनसे समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और समाधान की चुनौती सामने आती है। इस दिशा में आज प्रयास होने लगे हैं।

पिछले दिनों तेल के अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोत्तरी से भारत का तेल पुल घाटा ८१,००० करोड़ रुपयों तक जा पहुँचा। फिर भी हम इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं, तेल की कीमतों में कमी होगी और एक निम्न स्तर पर जाकर स्थिर हो जाएगी। इस इंतजार की प्रक्रिया में हम इस समस्या के बड़े स्वरूप को नजरअंदाज कर रहे हैं, बढ़ती हुई कीमतें हमारी अर्थव्यवस्था को जकड़ती जा रही हैं और तेल के भंडार कम होते जा रहे हैं।

पहले तेल मूल्यों की वृद्धि राजनीतिक कारणों – जैसे अरब-इजराइल या इराक-अमरीका युद्ध से होती थी। लेकिन वर्तमान बढ़ोत्तरी के पीछे दूसरे कारक कार्यरत हैं। विश्व के तेल भंडार खत्म होते जा रहे हैं और माँग बढ़ती जा रही है। तेल भंडार अगले २० वर्षों में खत्म हो जाएंगे। तेल विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है कि माँग के साथ उत्पादन बढ़ेगा और एक निश्चित सीमा के बाद गिरावट प्रारंभ हो जाएगी। तेल उत्पादन का ग्राफ घंटे की तरह होगा जो आधे उपभोग के समय चरम पर होता है।

कोहेन कैम्पबेल एवं जीन एच० लाहेरे नामक वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में लगभग १ ट्रिलियन बैरल तेल विभिन्न ज्ञात एवं अज्ञात स्रोतों में जमा है। उत्पादन का चरम उस समय होगा जब उपयुक्त तेल और तेल भंडार बराबर रह जाएंगे। इनके अनुसार यह समय १० वर्षों में आ सकता है। लेकिन इन्हें डर है कि तेल की कीमतों में वृद्धि जल्द ही होगी। इसका आर्थिक प्रभाव तब दिखेगा जब पश्चिम एशिया के बाहर तेल का उत्पादन शून्य हो जाएगा और तेल बाजार पर अरब राष्ट्रों का एकाधिपत्य होगा।

तेल कंपनियों का यह कहना है कि तेल उत्पादन तो अभी शुरू हुआ है, यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में साखा बनाए रखने के लिए बोला गया एक झूठ है। सच तो यह है कि तेल भंडार एक निश्चित मात्रा से कहीं ज्यादा अपने तेल भंडारों को दर्शाती हैं। इसमें उनका आर्थिक एवं राजनीतिक हित छुपा होता है। तेल भंडारों में लगातार तेजी से कमी होती जा रही है और अब इनके विकल्प को ढूंढ़ना ही होगा।

सच तो यह है कि तेल भंडार एक निश्चित मात्रा से कहीं ज्यादा अपने तेल भंडारों को दर्शाती हैं। इसमें उनका आर्थिक एवं राजनीतिक हित छुपा होता है। तेल भंडारों में लगातार तेजी से कमी होती जा रही है और अब इनके विकल्प को ढूंढ़ना ही होगा।

भारत के पिछले ५० वर्षों का तेल उत्पादन इसी की पुष्टि करता है। भारत का संरक्षित तेल भंडार ५ बिलियन बैरल से भी

कम है। सबसे महत्वपूर्ण तेलक्षेत्र ३० वर्ष पहले खोजा गया बॉम्बे हाई है, जो कुल घरेलू उत्पादन का २८% यानि ६५९,००० बैरल तेल प्रतिदिन उत्पादित करता है। इसमें भी कमी हो रही है। योजना आयोग के नवें पंचवर्षीय योजना में आकलन है कि वर्तमान घरेलू तेल भंडार २०१२ तक चलेगा। नए क्षेत्रों की खोज भी नहीं हो रही है।

क्या आयातित तेल पर निर्भर रहना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण नीति है?

एक टन कोयला एक बैरल तेल उत्पादित कर सकता है। हम ३७० मिलियन टन कोयले का उत्पादन ३९० कोयला खदानों में करते हैं। अगले दस वर्षों में कोयला उत्पादन ४६५ मिलियन टन तक पहुँच सकता है। हम इसे ४६५ मिलियन बैरल तेल में बदलकर आयातित तेल के मकड़जाल से अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त कर सकते हैं। यह वास्तव में कैसे संभव है इसे हम दक्षिण अफ्रीका से सीख सकते हैं।

१९५५ से दक्षिण अफ्रीका सिन्थेटिक लिमिटेड (सासोल) कोयले से तेल का उत्पादन करता आ रहा है। यह अब तक ७०० मिलियन बैरल से अधिक तेल का उत्पादन कर चुका है। कंपनी लगातार अपनी तकनीक एवं उत्पादन क्षमता को उन्नत करती जा रही है। इसका आधुनिकतम प्लांट प्रतिदिन अन्य रसायनों के साथ १,५०,००० बैरल तेल का उत्पादन कर रहा है। इस प्रक्रिया में कोयले को पहले गैस में फिर क्रूड तेल और अन्त में पेट्रोलियम उत्पादों में बदला जाता है। सर्वप्रथम कोयले को ऑक्सीजन एवं वाष्प से एक निश्चित ताप पर प्रतिक्रिया करा कर सिंथेटिक गैस (CO+H) को उत्पादित किया जाता है। इससे सल्फर और अन्य अशुद्धियों को निकाल कर दो भागों में बाँटा जाता है।

पहले भाग में कम ताप पर फिशर-ट्राप्श प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे उच्च स्तर का डीजल, किरोसिन, मोम, अमोनिया एवं टाउन गैस का उत्पादन होता है।

दूसरे भाग में उच्चताप पर फिशर-ट्राप्श प्रतिक्रिया लौह आधारित कैटेलिस्ट की उपस्थिति में कराई जाती है, इससे C1-C21 तक के टाइड्रोकार्बनों का उत्पादन होता है। इनके अलग-अलग बॉयलिंग बिन्दु के आधार पर इन्हें अलग-अलग किया जाता है। इनसे मुख्यतः मिथेन मिश्रित टाउन गैस, इथीलिन, प्रोपिलिन, अल्फा ऑयलाफेन, पेन्टिन, हेक्सेन ईंधन तेल, किरोसिन, डीजल, एल.पी.जी. गैसोलिन, जेट ईंधन, बिटुमेन, अल्कोहल, एसेटिक एसीड इत्यादि का उत्पादन होता है।

टार से फिनॉल, क्रिसॉल, पिंच और अन्य उत्पादन प्राप्त होते हैं। लगभग १२० रसायनों का उत्पादन एवं व्यावसायिक वितरण इसके द्वारा होता है। इस उत्पादन इकाई में ४० मिलियन टन कोयले का प्रतिवर्ष उपयोग होता है। सासोल का वार्षिक टर्न ओवर १९७७ में २ बिलियन डॉलर था।

सासोल से प्रेरणा लेकर अमरीका ने भी अपने कोयला से भरे हुए राज्य पेनसिल्वेनिया में कोयला से गैसोलिन बनाने का संयंत्र लगाया है।

भारत को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें प्रतिदिन १ बैरल तेल एवं रसायनों के उत्पादन का संयंत्र लगाना चाहिए। इसके लिए लगभग ३५० मिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी। लगभग २७,००० करोड़ रुपए लगाकर हम ७०,००० करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का टर्न ओवर प्राप्त कर सकते हैं। इससे उत्पादित कच्चे तेल का मूल्य लगभग १४ डॉलर प्रतिबैरल आएगा जो वर्तमान अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्य का आधा है।

इसके लिए हम, गुजरात, ... उड़ीसा जैसे कोयला उत्पादक ... लिग्नाइट आधारित संयंत्र लगभग ... करोड़ रुपए की लागत से सासोल ... १,५०,००० बैरल प्रतिदिन तेल उत्... लिए लगा सकते हैं।

इसके अलावा हमारे यहाँ एल... का भंडार २४ ट्रिलियन क्यूबिक फी... मुश्किल से वर्तमान उत्पादन स्तर ... पर १२ वर्षों तक चलेगा। इसके उप... लिए हमारे पास दो विकल्प हैं या तो ह... आयात टर्मिनलों और गैस पाइप ला... खर्च वहन करें या फिर अमरीका ... अपनी वार्षिक मांग २ ट्रिलियन क्यूबि... गैस का उत्पादन अपने २६० मिलि... लिग्नाइट कोयले के मा... पूरा करें। अमरीका के ... गैसीफिकेशन कंपनी में ... १६,००० टन लिग्नाइट ... को १२५ मिलियन क्यूफि... गैस में बदला जाता है और ... पूर्वी अमरीका के हजारों ... उपयोग होता है। यह संयंत्र ... से कार्यरत है। हम इस त... संयंत्र तमिलनाडु या राजस्थान में लगा... हैं।

हम तेल या गैस में आत्मनिर्भर नहीं है अतः आयातित तेल या गैस पर अपनी निर्भरता रखना एक गलत नीति है। हमें इसके विभिन्न विकल्पों पर ध्यान देना होगा। इसके लिए कोयला सर्वोत्तम विकल्प है।

हम तेल या गैस में आत्मनिर्भर ... अतः आयातित तेल या गैस पर ... निर्भरता रखना एक गलत नीति है। हमें ... विभिन्न विकल्पों पर ध्यान देना होगा। ... लिए कोयला सर्वोत्तम विकल्प है। इस प... बहुत पहले १९७० के तेल संकट के ... ही सावधान होना चाहिए था।

इंदिरा गांधी ने तब आई.आई.... के तत्कालीन निदेशक को लिखा था, 'यह स्पष्ट हो चुका है कि को... आधारित ऊर्जा ही हमारे लिए स... विकल्प है। इसके लिए हमें कोयला ... उत्पादन एवं उपभोग हेतु तकनीकी वि... करना है।

अब जबकि समस्याएं सामने आ ... है क्या हम आने वाले तेल संकट के ... तैयार हैं?

Scanned with OKEN Scanner

जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन

भोजन स्वस्थ तन और मन के अतिरिक्त और किन-किन दिशाओं में महत्वपूर्ण कार्य करता है? परिवार, समाज और देश के लिए इसकी भूमिका क्या है? इन विषयों पर आज विचार करना बहुत जरूरी हो गया है।

■ सुषमा शर्मा

व्यापार बढ़ाने और पैसा कमाने की मानसिकता आज मनुष्य के जीवन के प्रत्येक जरूरतों पर अपने उत्पादनों का बाजार खड़ी करती जा रही है। इस व्यावसायिक प्रवृत्ति को अपनी सीमा की जानकारी नहीं है। हमारे समाज में भी ऐसे विचारों के प्रति जागरूकता का अभाव है, जिनसे घातक व्यवसायिकता से हमारी रक्षा हो सकती है। पुराने समय में हमारी परंपरा, धर्म निष्ठा और पारिवारिक संरचना ऐसी थी, जिनसे हम व्यवसायिकता के घातक हमलों से बच जाते भी, किन्तु पराधीन देश में शिक्षा और रोजगार का ढाँचा बदला चला गया है। स्वतंत्र भारत का दुर्भाग्य रहा कि व्यवसायिकता का क्रमशः फैलाव के लिए सारी सीमाएँ तोड़ने लगी है। इस भूमंडलीकरण को बनाने वाली व्यापारिक शक्तियाँ विश्व के जनजीवन को किस दिशा में ले जा रहीं हैं, आज इस पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

व्यवसायिकता के चंगुल में फँसती जा रही हमारी भोजन-संस्कृति की सुरक्षा आज एक बड़ा प्रश्न बनकर सामने खड़ा है। भारत की परंपरा में भोजन कोई सामान्य बात नहीं है कि जैसे-तैसे पेट भरने, या स्वाद लेने के लिए ही इस का प्रचलन हो। भोजन मनुष्य के शरीर के स्वास्थ्य और विचारों की शुद्धता अर्थात् मन के स्वास्थ्य से भी सम्बन्धित है। शरीर स्वस्थ हो और मस्तित्व भी स्वस्थ हो, तभी अच्छे विचार और अच्छे कार्य हो सकते हैं। इन दोनों दृष्टियों से भोजन को संतुलित किया गया। लेकिन आज के चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानव शरीर के स्वास्थ्य की बात तो करते हैं, पर मानव के मस्तिष्क और उसके विचारों के स्वास्थ्य पर कोई प्रकाश नहीं डालते। प्रोटीन और विटामिनों की जरूरत कैसे पूरी होगी? संतुलित आहार कैसे होगा? कुपोषण कैसे दूर होगा इन बातों पर बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनती हैं। करोड़ों-अरबों रुपये खर्च किये जाते हैं लेकिन इन योजनाओं में कहीं भी भोजन से स्वस्थ विचारों के बनने की व्याख्या नहीं सुनाई पड़ती। आहार-विहार के संतुलन से दीर्घायु होने की बात तो छोड ही दीजिए। वर्तमान समय के वैज्ञानिक अभी पेट भरने के प्रयास में इतने परेशान हैं कि भोजन की सूक्ष्म गुणवत्ता पर शायद उनका ध्यान नहीं जा रहा।

भोजन स्वस्थ तन और मन के अतिरिक्त और किन-किन दिशाओं में महत्वपूर्ण कार्य करता है? परिवार, समाज और देश के लिए इसकी भूमिका क्या है? इन विषयों पर आज विचार करना बहुत जरूरी हो गया है। व्यवसायिक शक्ति अपनी मजबूती के लिए चाहतीं हैं कि परिवार टूटे, समाज टूटे, राष्ट्र भक्ति की भावना और उसकी सीमा भी टूट जाए। मनुष्य बेहद अकेला हो जाए, अपनी जीवन की जरूरतों के लिए मोहताज होकर खड़ा हो। उसका कोई सहारा नहीं हो। वह पैसों में बिके, पैसों पर दौड़े। तभी वह सबसे अच्छा उपभोक्ता बन सकता है उसके श्रम के बदले मिले हुए पैसों को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के बहाने खींचा जा सके। इसके लिए व्यवसायिक शक्तियाँ अनेक प्रकार के प्रचार माध्यमों का उपयोग करती है। इस कार्य में आज तक मनोरंजक कार्यक्रमों को भी हथियार बनाया जा रहा है। टी.वी. चैनल ऐसे कार्यक्रम दिखाते हैं जो पारिवारिक ढाँचे तोड़ने को प्रभावित करते हैं, हमारी मान्यताओं का

Scanned with OKEN Scanner

भारत में भी जिन-जिन स्थानों पर व्यापार और पैसे का दबदबा बढ़ गया है, वहाँ मानवीय भावना समाप्त हो गई है। भूख से बिलबिलाते गरीब लोगों के बच्चों को अनाथालय में रखकर उनके गुर्दे आदि शरीर के अंगों को बेचने का पाप भी हो रहा है।

मजाक उड़ाते हैं। हमारे आचार-विचारों को पिछड़ा बताते हैं। इनका उद्देश्य समाज का नवनिर्माण करना नहीं होता, इनका उद्देश्य सामाजिक ढाँचे को तोड़ना, और पारिवारिक संस्था नष्ट करना है। इस विघटन से ही व्यक्तिवादी प्रवृतियों का निर्माण किया जा सकता है। व्यक्तिवाद जितना फैलेगा, नातों, रिश्ते और सम्बन्धों के भावनात्मक जुड़ाव मिटेंगे परिवार, समाज और देश के दायित्व का बोध भी समाप्त होगा, लोग एक दूसरे के शोषण पर तुल सकेंगे। यह घमासान द्वन्द्व जब तक समाज में नहीं फैलेगा व्यवसायिकता को सर्वाधिक लाभ नहीं मिल सकता।

दूसरी ओर भारतीय भोजन संस्कृति परिवार को एक मानसिकता और एक भावना में जोड़ती है। एक साथ भोजन करने और एक समान शक्ति सम्पन्न होने का वेदों ने आदेश दे रखा है। मिल-बाँट कर खाने का आचरण हमारे यहाँ प्रचलित रहा है। अकेले खाने को पाप माना जाता रहा है। भोजन करने के पहले दूसरों से पूछ लेना आवश्यक माना जाता रहा है कि वह भोजन लेगा या नहीं। यह धारणा आज भी समाज में कहीं न कहीं दिख जाती है। यह कार्य समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिये किया जाता रहा है। इससे एक दूसरे का आपस में मन जुड़ता है, आपस में सहानुभूति बनती है और व्यक्ति एक दूसरे के सहयोगी बनता है। इस प्रकार सहयोग और सहकार की भावना से आपसी ताकत बढ़ती है। एक दूसरे की आवश्यकताएँ अपने अतिरिक्त पड़े साधनों से ही पूरी हो जाती हैं। दूसरे स्वार्थी लोगों को शोषण का अवसर नहीं मिलता।

आज फास्ट फूड और होटल के भोजन की ललक ने पति-पत्नी के सम्बन्ध को भी खोखला करना शुरू कर दिया है। परिवार में एक साथ भोजन करने से प्रतिदिन एक साथ बैठने, आपस में बातचीत करने एक दूसरे के सुख दुःख को जानने का अवसर मिलता है। यह अवसर सम्बन्ध और जिम्मेदारियों को आत्मिक रूप से जोड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज दुनिया-आपस में मिलकर भोजन करने से पैदा होनेवाले संसर्ग-लाभ से अनजान हो गई है। राजनीतिक और व्यवसायिक हलकों में टी-पार्टी से लेकर डिनर, लंच और अफतार की पार्टियाँ भी इसलिए होती हैं कि ससंर्ग मे वृद्धि होगी। फिर बाजार की शक्तियाँ जब हमारी भोजन संस्कृति को तोड़ती है तो हमें यह साफ-साफ ज्ञान क्यों नही होता कि परस्पर निर्भरता को नष्ट हो जाने से समाज में शोषण की आसुरी प्रवृत्ति बढ़ेगी, आत्मीयता का रस सूख जाएगा। इस से भावना शून्य मनुष्य निर्मित होगा। मनुष्य को भावना-शून्य बनाने वाला कोई भी प्रयास एक प्रकार का अपराध है। यहीं से मनुष्य में अनेक विकृतियाँ जन्म लेती हैं, यहीं से समाज अपराध की ओर उन्मुख होता है। जब मनुष्य में परस्पर निर्भरता और भावना होगी तभी परिवार संस्था बन पाएगी साथ ही अच्छी सामाजिक प्रवृत्ति भी बनेगी।

अमेरिका और यूरोप के देशों में व्यवसायिकता इतनी बढ़ गई है कि परिवार नाम की चीज नहीं है। अमेरिका व्यापार के गर्भ से पैदा हुआ देश है परिवार संस्था का अभाव है। परिवार संस्था नहीं होने के कारण वहाँ हमारी कल्पना में नहीं अँटनेवाली सामाजिक विकृतियाँ फैली हुई हैं। मुट्ठीभर लोग अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए अधिकतम जनसंख्या को मजबूर बनाकर उनका मनमाना शोषण करते हैं। भारत में भी जिन-जिन स्थानों पर व्यापार और पैसे का दबदबा बढ़ गया है, वहाँ मानवीय भावना समाप्त हो गई है। भूख से बिलबिलाते गरीब लोगों के बच्चों को अनाथालय में रखकर उनके गुर्दे आदि शरीर के अंगों को बेचने का पाप भी हो रहा है।

इन सभी विकृतियों की जड़ों में जाकर समाधान की खोज करें तो भोजन की भारतीय संस्कृति एक आधारशिला के रूप में दिखाई पड़ेगी। हमारा - सूत्र है" 'जैसा खाओ अन्न-वैसा होगा मन'। अन्न की शुद्धता और उसे ग्रहण करने का आचार कोई सामान्य बात नहीं है। इससे उत्तम विचार और उत्तम समाज का निर्माण होता है और विकृतियाँ दूर होती हैं।

आज जरूरी है कि भोजन की भारतीय संस्कृति के मूल्यवान मान्यताओं को फिर से परखा जाए और उसका पुनः अनुसरण किया जाए। रसायनिक उर्वरकों, जीन सम्बन्धित बीजों और कीटाणुनाशक विषैले पदार्थों से उपजे अन्न, फल साग-सब्जियों, खाद्य तेल के साथ-साथ भोजन पकाने में उपयोग होनेवाली जहरीली गैस के प्रति भी जागरूकता आनी चाहिए। जब सारा भोजन जहरीले साधनों से निर्मित हो रहा है तो ... और आत्मघाती विचार क्यों नही पैदा होंगे। आज अन्न खराब है इसीलिए लोगों का मन भी खराब है। लोगों के मन की खराबी से समाज में विकृति फैलेगी ही। सुसंस्कृत परिवार के निर्माण के लिए भारत की भोजन संस्कृति ही एकमात्र मार्ग है।

Scanned with OKEN Scanner

अब बिहार में बोरलॉग बो रहे हैं मक्का

■ हीरेन्द्र पाठक

अस्वाभाविक रूप से पैदावार बढ़ाने की अंधी दौड़ पश्चिमी मानसिकता है, जहाँ गायों को मांस खिलाकर उसे शीघ्र से शीघ्र मोटा तगड़ा करने का प्रयास किया गया, ताकि ऐसी गायों को काटकर अधिक से अधिक मांस उत्पादित किया जा सके। नतीजा यह हुआ कि वहाँ की गाएँ मांस खा-खाकर कर पागल हो गईं जिनके आतंक के कारण उन्हें मौत की सजा दी जाने लगी। यह विदेशी उन्नति का सूत्र है कि कम-से-कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जाए और उसे बेचकर किस प्रकार अधिक से अधिक धन जमा किया जाए। अधिक से अधिक धन कमाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन यापन के साधन पर कब्जा जमा लिया जाए और लोगों को दास बनाकर असुरी ठहाके लगाए जाएँ।

जनवरी २००१ में संपन्न हुए विज्ञान कांग्रेस में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा में हार्टिकल्चर के प्रोफ़ेसर डॉ. के.एल. चड्डा ने एक ऐसे गाजर की किस्म पैदा कर लेने का दावा किया था जिसे सिर्फ एक खा लेने के बाद सप्ताह भर भोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस गाजर में सभी विटामिन प्रचूर मात्रा में हैं। नोबेल पुरस्कार पाए हुए शोधकर्त्ता नार्मन ई. बोरलॉग ने मक्का के एक ऐसे किस्म 'क्वालिटी प्रोटीन मेज़' विकसित किया है जिसमें साधारण मक्का की तुलना में प्रोटीन ज्यादा रहता है। उसे खाकर गरीब लोग भी प्रोटीन की उचित मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें दूध, अण्डा, मांस-मछली खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है और उनका स्वास्थ्य डाँवाडोल हो रहा है, बोरलॉक साहब का मक्का खाकर वे लोग ताकतवर बन सकते हैं। इस मक्के में लेसीन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा दूनी है, जिन्हें खाने से अमीनो अम्ल की पूर्ति होती है। छोटे बच्चों और कुपोषण के शिकार लोगों के लिए बोरलॉग ने अपने मक्के को वरदान बता रखा है।

बोरलॉग ने अपने मक्के की खेती के लिए बिहार के भागलपुर, बेगूसराय और पूर्णिया जिलों को सबसे उपयुक्त माना है। मक्का अनुसंधान महानिदेशालय, नई दिल्ली ने तो बेगूसराय जिला को इसकी खेती के लिए पहले ही चुन लिया था। वहाँ अनुसंधान-कार्य भी आरंभ हो चुका है।

बिहार की उपजाऊ धरती की पहचान कर उसे विश्व स्तरीय खेती के लिए योग्य मान लेना बहुत प्रशंसनीय कार्य कहा जा सकता है। देश के विकसित प्राय क्षेत्रों – मसलन पंजाब, आंध्र प्रदेश आदि का चुनाव नहीं कर बिहार को विकसित करने का प्रयास करना भी उत्तम बात है। वस्तुतः पंजाब, आंध्रप्रदेश इत्यादि विकसित कृषि के लिए काफी चर्चा में आने लगे थे। यहाँ हरित क्रांति का प्रतिफल पककर जमीन पर खुद गिरने लगा है। किसानों की आत्महत्याओं, रसायनिक खादों और कीटनाशकों से उर्वर भूमि और पानी के विषैले हो जाने और जीन से विकसित किए हुए बीजों के दुष्परिणामों को देखकर लोगों में प्रतिक्रिया फैल गई है। लोग देशी बीजों और गोबर-कम्पोस्ट की खेती की ओर लौटते हुए महसूस कर रहे हैं कि वे लालच में भटक जाने के बाद अपने घर को लौट रहे हैं। वास्तव में, अस्वाभाविक रूप से पैदावार बढ़ाने की अंधी दौड़ पश्चिमी मानसिकता है, जहाँ गायों को मांस खिलाकर उसे शीघ्र से शीघ्र मोटा तगड़ा करने का प्रयास किया गया, ताकि ऐसी गायों को काटकर अधिक से अधिक मांस उत्पादित किया जा सके। नतीजा यह हुआ कि वहाँ की गाएँ मांस खा-खाकर कर पागल हो गईं जिनके आतंक के कारण उन्हें मौत की सजा दी जाने लगी। यह विदेशी उन्नति का सूत्र है कि कम-से-कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जाए और उसे बेचकर किस प्रकार अधिक से अधिक धन जमा किया जाए। अधिक से अधिक धन कमाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन यापन के साधन पर कब्जा जमा लिया जाए और लोगों को दास बना कर असुरी ठहाके लगाए जाएँ। बोरलॉग का मक्का हो या कोई भी जीन-परिवर्द्धन से बना हुआ अन्न, सब्जी, फल अथवा पशु सभी प्रकृति-विरोध के दोष से ग्रस्त हैं। बिहार के पिछड़े के लोग देश के अनुसंधान केंद्रों में बनें 'ब्लॉक अन्न' शंकरकंद से लेकर गोभी तक के संकर किस्मों से परिचित हैं जिनमें मात्रा तो बड़ी होती है, स्वाद और सुगंध नहीं होता अर्थात् संकर किस्मों में उत्पादन को लक्ष्य बनाया गया, गुणवत्ता को खो दिया गया। इसके साथ ही उसके उत्पादन में रसायनिक खाद और पानी की खपत बढ़ गयी और खेती घाटे का रोजगार हो गया। पशुधन की उपयोगिता घटती चली गई। गोबर और गोरस दुर्लभ हो गया। आज लोग सिन्थेटिक दूध पीने पर मजबूर हैं। ब्रोरलॉग होशियार हैं कि उन्होंने अपने चमत्कारी और कल्याणकारी मक्के की खेती

Scanned with OKEN Scanner

के लिए बिहार की भूमि का चुनाव किया है। पर ध्यान रखने की बात है कि उन्हें बेगूसराय-बढइया के पानी से पल्ला पड़ सकता है। ग्रामीण जनजीवन में इस बात की चर्चा फैल चुकी है कि संकर अनाजों, रसायनिक खादों और कीटनाशकों के कारण अनेक बीमारियों से असमय ग्रस्त होना पड़ रहा है। पेट की बीमारी आम है, बाल की सफेदी और आँख की रोशनी गिर जाना सामान्य रोग हैं। इसके अलावा भारी बीमारियों से भी जनजीवन परेशान हो रहा है। ये सब कुछ खानपान की गड़बड़ी के कारण ही है। क्या होगा अन्न और धन जब आदमी रोगी हो जाए। बोरलॉग के विटामिन और प्रोटीन युक्त मक्का कौन खाएगा? भारत में मक्का भोजन का प्रधान अन्न नहीं है। मक्का की रोटी, दलिया, भुट्टा और भूंजा एक मौसम में ही अच्छा लगता है। मक्का की सबसे अधिक खपत तो उन देशों में होती है जहाँ मोटे-मोटे सफेद सूअरों को मक्का खाने को दिया जाता है और उन सूअरों के मांस को खाकर विदेशी गोरे बरसाती मेढकों की तरह तगड़े दिखाई देते हैं। देह की तगड़ाई ही जरूरी नहीं होती, इसमें स्पंदन (सेन्सेशन) भी होना चाहिए। स्पंदन होता है प्राण की अधिकता से; जैसे फर्टिलाइजर पर उपजे हुए शकरकन्द के संकर (दोगली) नस्ल में स्वाद नहीं होता, इन सूअरों के मांस का आहार करने वालों में भी कोई तत्व नहीं होता।

लोग जानते हैं कि आज भारत में खाद्यात्र इतना अधिक है कि उसकी सरकारी खरीद और भंडारण समस्या बन गई है। खाद्यात्र के भंडारण पर प्रतिवर्ष बारह सौ करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैम) की रिपोर्ट में बताया गया है कि हर वर्ष एक जुलाई को २२३ लाख टन खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है। सिर्फ १९९७ का वर्ष छोड़कर १९९३ से १९९९ के बीच अन्न की मात्रा बढ़ गई। २२३ लाख टन के बदले अब ३५६ लाख टन अन्न का भंडारण करना पड़ रहा है। आर्थिक बोझ से उबरने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैम) के रिपोर्ट में सुझाया गया है कि अन्न का भंडार बढ़ जाने की परेशानी से मुक्ति का रास्ता यही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये जरूरतमंदों तक अन्न पहुँचा दिया जाए।

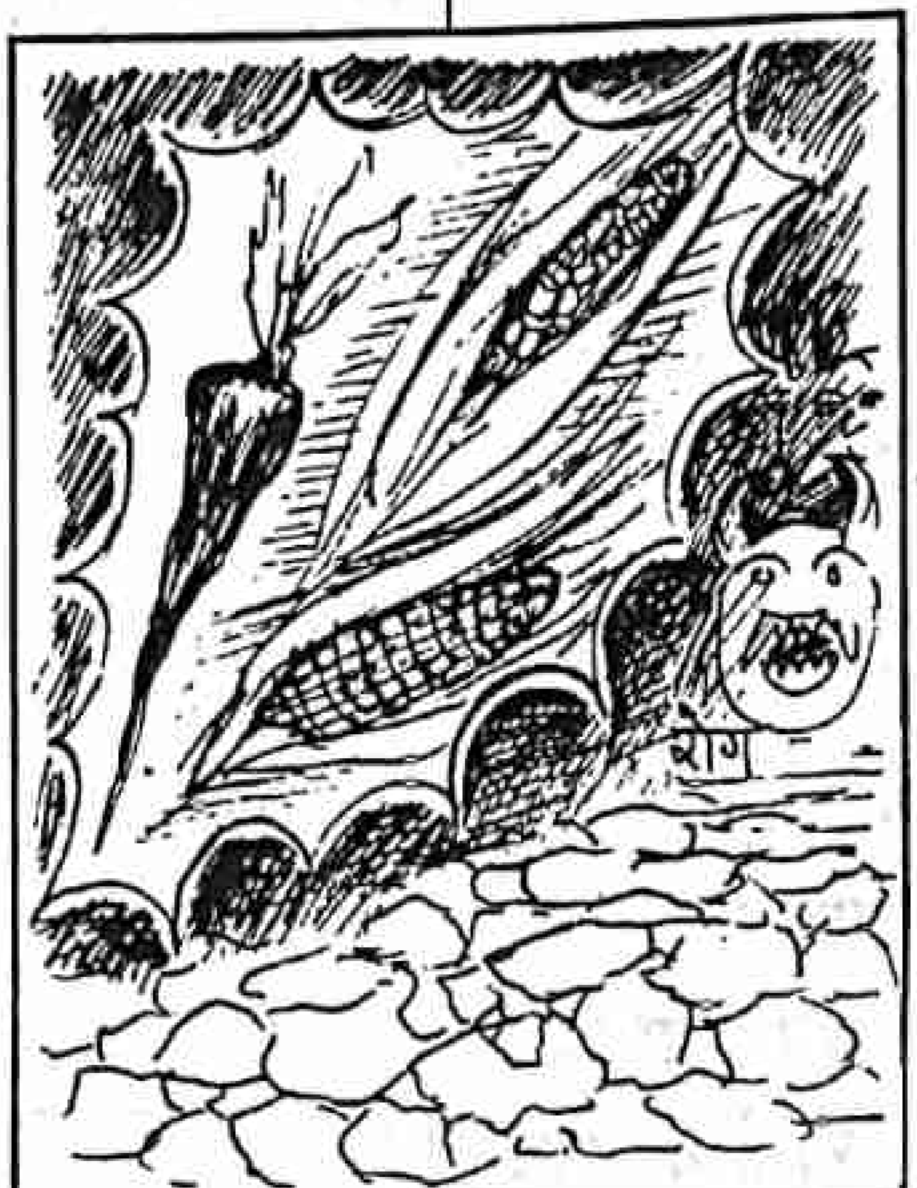

इससे क्या यह नहीं लगता कि हमारी सरकार जरूरतमंदों को अन्न पहुँचाकर भंडारण में हो रहे खर्चे को घटाने के लिए विवश हो रही है। हम सुना करते थे कि विदेश में अन्न अधिक हो जाने पर समुद्र में डाल दिया जाता है। आज यह दशा भारत में भी उत्पन्न होने जा रही है। ऐसी दशा में संकरित बीजों को छोड़ भारत की मूलभूत फसलों की खोयी हुई गुणवत्ता बचाने की जरूरत है।

जैविक खाद, कम पानी और देशी बीजों से होनेवाली खेती के अन्न की माँग आज विश्व में अधिक है और ये अधिक मूल्य पर बिक रहे हैं। रासायनिक खाद और कीटाणुनाशक से रहित अन्न, सब्जी और फल की माँग बढ़ रही है। विदेशी लोग पिछड़े देशों के पिछड़े क्षेत्रों को चुनने की कुटिल नीति के तहत ही बिहार के क्षेत्रों को बोरलॉग ने मक्के की खेती के लिए चुना है। इस विदेशी बीज कंपनियों की सक्रियता की अग्रिम योजनाएँ बिहार में भी वहीं होगी जो पंजाब, आंध्रप्रदेश आदि में हुई और तब दुष्परिणामों में भी समानता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ■

आयुर्वेदिक फार्मूले चुरा रही हैं अँग्रेजी दवा कंपनियाँ

इन दिनों बाजार में ऐसी एलोपैथिक (अंग्रेजी) रसायनों की बाढ़ आयी हुई है जो मूलत: आयुर्वेदिक दवाओं के फार्मूले उड़ाकर बनायी गयी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इन दवाओं की बदौलत देश-विदेश में करोड़ों का कारोबार कर रही हैं। सरकार की उपेक्षा के कारण वर्षों से प्रचलित आयुर्वेद की ज्यादातर दवाओं के पेटेंट नहीं किये गये हैं, जिस कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ धड़ल्ले से उनके फार्मूले चोरी कर उन पर अपना पेटेंट करा रही हैं। इस प्रकार के सैकड़ों फार्मूले अब तक एलोपैथिक दवा कंपनियों द्वारा हथियाये जा चुके हैं। स्थिति यही रही तो भविष्य में आयुर्वेदिक दवाओं के एक भी फार्मूले नहीं बच पाएंगे। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में वर्षों से खांसी की अचूक दवा 'वासा' है लेकिन अब एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में भी इसी दवा का इस्तेमाल कफ सीरप (खांसी का सीरप) के लिए हो रहा है। 'ब्रोमोहेग्जिन' नाम से इसका कफ सीरप काफी मशहूर है। बाजार में उपलब्ध ७० फीसदी कफ सीरप में मूल दवा 'वासा' ही होती है। आयुर्वेदिक दवा 'वासा' की बिक्री जहाँ सीमित है और काफी सस्ती उपलब्ध हो जाती है वहीं, एलोपैथी में खांसी सीरपों की भारी बिक्री होती है तथा इसकी कीमत भी तीन गुनी अधिक होती है। मशहूर बहुराष्ट्रीय कंपनी इक्का समेत कई कंपनियाँ इसका निर्माण कर ही हैं। इसी प्रकार मच्छरों के काटने पर इस्तेमाल होने वाली दवा 'क्लोरोक्वीन' भी मूल रूप से आयुर्वेदिक दवा का फार्मूला उड़ाकर बनायी गयी है। आयुर्वेद में यह दवा 'सिनकोना' नाम से उपलब्ध है। देश में आयुर्वेद की उपेक्षा के कारण 'सिनकोना' को तो लोग क्या एलोपैथिक डाक्टर तक नहीं जानते हैं। लेकिन 'क्लोरोक्वीन' को चार दर्जन से अधिक देशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ बनाकर चांदी काट रही हैं। सिपला, सन फार्मा (बहुराष्ट्रीय) और आईडीपीएल (देशी) जैसी कंपनियाँ भी इस दवा को बना रही हैं। रक्तचाप की आयुर्वेदिक दवा 'सर्वगंधा गनवटी' एलोपैथिक में रिसप्रिन के नाम से आ रही है। यह रक्तचाप संबंधी बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होती है। इसे भी दर्जन भर कंपनियाँ बना रही है जिसमें ज्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ बना रही है जिसमें ज्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ही हैं। इसी प्रकार 'हरि पत्री' नामक आयुर्वेदिक दवा एलोपैथी में 'डिलीटेलिस' नाम से आ रही है जो कई तरह के रोगियों को 'क्रोनिक प्राब्लम' में दी जाती है। इंटास और केडिला जैसी कंपनियाँ धड़ल्ले से इस दवा को बेच रही हैं।

अरंडी के बीज से बनने वाली आयुर्वेदिक औषधि 'अन्नामया' का इस्तेमाल गर्भपात संबंधी चिकित्सा के लिए किया जाता हैं यह एलोपैथिक दवाओं में 'एरगोटामिन' के नाम से आ रही है। इसी प्रकार लहसुन और प्याज से बनने वाली अरगापाइरीन दवा मूलतः भारतीय आयुर्वेदिक औषधि है लेकिन इसका भारतीय पेटेंट नहीं होने के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस फार्मूले को चोरी कर इस नाम से एलोपैथिक दवा का निर्माण कर लिया है। सिर्फ आयुर्वेद में ही नहीं यूनानी चिकित्सा पद्धति के फार्मूलों को भी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ नहीं बख्श रही है। उच्च रक्तचाप में अचूक मानी जाने वाली यूनानी पद्धति की दवा 'असराल' को एलोपैथी में 'सर्पनटीना' नाम से बाजार में उतारा गया है। ■

तहलका डॉन्ट कम

तख्ती पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था– 'तहलका डॉन्ट कम'। तख्ती के साथ एक डंडा भी लटक रहा था। इस रहस्यमय टोटके को देख मैं साफ-साफ कुछ नहीं समझ पाया।

■ त्रिशूलपाणि

बेरोजगारी के दौर में एक रास्ता यह सूझा कि क्यों न मैं भी एक डॉट कॉम खोल लूँ और दौड़ पड़ूँ ओहदेदार हस्तियों के पीछे, कोई न कोई तो फँसेगा ही। पत्रकारिता के इस उत्तर आधुनिक युग में कलम घिसते रहने से मोटा लाभ नहीं मिलेगा। नेता-मंत्री नौकरशाह-अधिकारी हाथ नहीं लग पाएँ तो किसी फिल्मी हस्ती को भी निशाना बनाया जा सकता है। फिल्मी हस्ती किस नेता, उद्योगपति या अधिकारी से कम हैं।

हर सफल चेहरे का आज एक ही पैमाना माना जा रहा है कि वह कितना बिकाऊ और कमाऊ है। इस पैमाने पर नेता से कोई कम तो नहीं है अभिनेता। करोड़पति होने का सपना बेचनेवाले अमिताभ बच्चन के चपेट में कौन नहीं आ रहा। अमिताभ की बुलंद आवाज और अंदाज के सभी कायल है। 'कौन बनेगा करोड़पति' के एक नारे से सभी लोग स्पर्धा में उतरते जा रहे है। जो जहाँ है वहीं करोड़पति होने के सपने में डूबता जा रहा है। अमिताभ की इस सफलता को देश ने स्वीकार लिया है उन्हें राष्ट्रपति ने 'पद्म भूषण' के अलंकार से मंडित किया है। कौन बनेगा करोड़पति के सपने से बड़ा राष्ट्रीय अवदान किसी राष्ट्रभक्त, राष्ट्रसेवक अथवा शहीद, वैज्ञानिक, साहित्यकार का हो, यह आज जरूरी नहीं। इनमें से किसी ने भी एक-एक नागरिक को करोड़पति बन जाने के सपने से नहीं जोड़ा। वर्तमान आर्थिक सुधार के युग में अमिताभ का काम बिल्कुल सही है। कोई यह आरोप लगाए कि तहलका डॉट कॉम के दायरे में फँसे ब्रिगेडियर के मन में करोड़पति होने का सपना बोने में 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसे कार्यक्रम का हाथ हो सकता है, दारू के नशे और सिगरेट के धुँए में झिलमिलाती फौजी अफसरों की बुद्धि पर मनोवैज्ञानिक असर डालने में करोड़पति बनने का सपना सफल हुआ है– तो यह मैं नहीं मानूँगा। देश का बजट प्रमाण है कि आज पैसे की अधिक से अधिक कमाई किसी जनहित से अधिक महत्व रखती है। यही भूमण्डलीकरण के प्रभाव में सबसे उत्तम विकास नीति हो सकती है। ऐसे मौसम में करोड़पति बनने का सपना बचेने वालों के ऋण से मुक्ति के लिए पद्मभूषण क्या भारत रत्न भी पर्याप्त नहीं है। इन महापुरूषों को **विश्वभूषण** या **ब्रह्माण्ड-रत्न** का अलंकार देकर कुछ राहत पायी जा सकती है। इन प्रस्तावित पुरस्कारों पर सरकार को शीघ्र विचार करना चाहिए। अन्यथा यह आइडिया किसी विदेशी के हाथ लग सकती है।

इस समय अपना देश बड़ी-बड़ी हस्तियों से जगमगा रहा है, ऐसे में मेरे डॉट कॉम का उद्योग मार नहीं खा सकता। मेरी जटिल समस्या जरूर है कि कोई नाम पंजीकरण के लिए मिल नहीं पा रहा। मैंने बड़ी मेहनत से कुछ मौलिक नाम जुटाए थे। वे सारे नाम पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। फिर भी मैंने प्रयास किया मेरी नयी सूची में बहुतेरे नाम लिपिबद्ध हैं। मैं उनमें से कुछ को सार्वजनिक रूप से बताना चाहता हूँ। डॉट कॉम का कोई विशेषज्ञ इन नामों में से अपंजीकृत नाम पा जाए तो मुझे सूचित करने की अपार कृपा कर सकता है। मेरी सूची में दर्ज उल्लेखनीय नाम निम्नलिखित हैं–

सभी नामों के अन्त में डॉट कॉम लगाकर पढ़े– कपट, लपट, झपट, चिरकुटी, भृकुटि, हाहाकार, हलाहल, चित्कार, कोलाहल, भंडाफोड़, व्यवस्था तोड, रिश्वत-छोड़, तख्ता-पलट, मामला-सलट, नींद उचाट, खड़ी-खाट, खूँटाठोक, रस्ता-रोक इत्यादि। लगभग नब्बे पन्नों में वर्णित नामों की सूची मैंने बना रखी है। संभव है कि इनमें से कोई न कोई नाम अपंजीकृत मिले ही -जाए। मेरी सहायता में दुनिया की कई भाषाओं के शब्द और क्षेत्रीय बोलियाँ भी खड़ी हैं। मेरे डॉट कॉम का नाम पंजीकृत अवश्य हो सकता है। लेकिन एक और कठोर समस्या मेरे सिर पर आ गिरी, मैं उसे कहने में संकोच करता हूँ, फिर भी आप अपने हैं इसलिए बता देता हूँ।

एक दिन वह व्यक्ति मुझे मिला जो कई करामाती डॉट कॉमों को अपने घर बुलाने को प्रयास कर चुका था। हंगामा, पर्दाफाश, बेनकाब, बेपर्द, चेहरा-जर्द और विशेष कर तहलका डॉट-कॉम को भी उसने बुलावा भेजा था, इस काम के लिए कि कोई उसके पास पहुँचे, उसकी बात सुने और उन रहस्यों को जान ले जिनसे देश को बहुत बड़े-बड़े खतरे हैं आर्थिक गुलामी का खतरा, चरित्रभ्रष्ट समाज बनने का खतरा, जनतांत्रिक राजनीति के व्यर्थ हो जाने का खतरा। लेकिन, कोई उसकी बातें सुनने के लिए नहीं आया।

मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटने से उत्पन्न हुए भय और आक्रोश में वह गलियों में पागल की तरह घूमता फिरा। वह चीख-चीखकर कहता रहा– लघु उद्योग बंद हो जाएँगे, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ नमक, तेल, चावल, आटा, बिजली, पानी, यातायात, कपड़े आदि जीवन की सभी जरूरी चीजों पर कब्जा कर लेंगी। वह कहता रहा– मैं बताऊँगा उन सभी लुटेरों का पता, आओ संगठित हो, उठा-ललकारो शत्रुओं को। उन्हें दफन कर दो। पर कोई नहीं आया–डब्ल्यू.टी.ओ. की रस्सी में कसती देश की गर्दन छुड़ाने।

इसी घटना के बाद उस व्यक्ति ने अपने दरवाजे पर एक तख्ती लटकाई थी। तख्ती पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था– 'तहलका डॉन्ट कम'। तख्ती के साथ एक डंडा भी लटक रहा था। इस रहस्यमय टोटके को देखकर मैं साफ-साफ कुछ नहीं समझ पाया। शायद वह कहना चाहता हो कि धंधेबाज डॉट कामो! तुम लोग मेरी गली में मत आना।

इस प्रसंग ने मुझे कहीं का नहीं रखा। ऐसा लगा कि मेरी कामनाओं का टाइटेनिक जहाज फट चुका है। मैं उस पर से छलांग लगा अथाह समुद्र में आ गिरा हूँ। समुद्र का पानी बर्फ बनता जा रहा है। जीवित बच पाने की आशा हाथ से छूटती चली जा रही है। चारों ओर घना अंधकार है और समुद्र की भीषण गर्जना भी। यहाँ मेरी पुकार कोई नहीं सुन सकता। ■

Scanned with OKEN Scanner

जमशेदपुर में स्वदेशी का कार्यकर्त्ता-सम्मेलन

■ वन्दे शंकर सिंह

दिनांक ४/३/२००१ को औद्योगिक नगर जमशेदपुर झारखण्ड में इस महानगर के स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्त्ताओं का सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखण्ड सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री यमुना सिंह ने दीप जला भारत माता, बाबूगेनु एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्पार्पण कर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्राचीन समय में भी स्वदेशी भावना से ओत-प्रोत लोगों ने देश की धरोहर की रक्षा की। आज भी अपने देश में अंग्रेजों के कानून प्रभावी है। जिसके कारण जंगलों की बेहिसाब कटाई चल रही है। जंगल की रक्षा करना सरकार के लिए संभव नहीं हो रहा है। हम उस कानून को बदलकर नया कानून बनाएंगे। जिसमें जंगल के आय में ग्राम सभा को सीधे हिस्सेदारी दी जाएगी। हमें विदेशी पेड़-पौधे का बहिष्कार करना होगा, अपने यहाँ के फलदार और उपयोगी पेड़-पौधों को लगाना पड़ेगा जो हमारे यहाँ के पर्यावरण को बचाने में सहयोग करेंगे। आज जंगल से वन-औषधि की चोरी हो रही है और साथ विदेशी इसका पेटेंट करा रहे हैं। हम लोगों को इस चोरी को रोकने का काम करना होगा।

अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री चिमनलाल भालोटिया भारत विकास, जमशेदपुर ने कहा कि कि आयात से मात्रात्मक प्रतिबंध हटने के कारण हमारे यहाँ के लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं। बड़े उद्योग भी आज दूसरे देशों में पलायन करने पर विवश हो रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो भारत जल्द ही आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा। तब हमारे देश में उद्योगपति नहीं, विदेशी कंपनी के दलाल बच जाएँगे। सरकार को मात्रात्मक प्रतिबंध रखते हुए आयात कर में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए।

विदेशी कंपनी कोई भामाशाह नहीं है जो हमारे यहाँ दान करने आई है। वह यहाँ सिर्फ मुनाफा कमाने आई है। मुनाफा की ललक उसे कोई अच्छा काम नहीं करने देगी एवं वह मुनाफा के लिए कोई भी काम कर सकती है।

प्रांत सहसंयोजक श्री दिनेश मंडल ने कहा कि विदेशी कंपनी कोई भामाशाह नहीं है जो हमारे यहाँ दान करने आई है। वह यहाँ सिर्फ मुनाफा कमाने आई है। मुनाफा की ललक उसे कोई अच्छा काम नहीं करने देगी एवं वह मुनाफा के लिए कोई भी काम कर सकती है।

द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि श्री अनंत राम टुडु, सभापति लोक लेखा समिति झारखण्ड सरकार ने कहा कि हमको प्रचार माध्यम हमारी संस्कृति को बदलने के लिए ही पूरा प्रचार कर रही है।

वर्तमान शिक्षा पद्धति को नकारते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रांत विचार मंडल प्रमुख श्री नीलम कुमार जैन ने कहा कि आज जो अपसंस्कृति हमारे यहाँ पनप रही है इसके पीछे पश्चिम प्रभावित शिक्षा पद्धति है। हमको अ… संस्कृति के अनुसार बच्चों को शिक्षा देने की आवश्य… है।

वैश्वीकरण के कारण पड़ने वाले प्रभाव पर एक प्र… महानगर विचार मंडल प्रमुख श्री महेश्वर प्रसाद ने रखा… प्रचार प्रमुख श्री मुनेश्वर प्रसाद ने इसका अनुमोदन कि… संचालन श्री विजय कुमार सिंह कार्यकारिणी सदस्य ने कि…

समापन सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में बोलते… श्री भृगुनाथ सिंह ने कहा कि १ अप्रैल, २००१ से … वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटने जा रहा है। जि… कारण लघु एवं कुटीर उद्योग देखते-देखते बर्बाद हो जा… अतः स्वदेशी के कार्यकर्त्ता इस स्थिति की जानकारी … जनता को घर-घर जा कर दें।

अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए व… अधिवक्ता श्री गुप्तेश्वर नारायण राय ने कहा कि सर… बारी-बारी से कानून में परिवर्तन कर देश की गुलामी… ओर ले जा रही है। सरकार को चाहिए कि विश्व व्या… के कानूनों को अपने अनुरूप बनाएँ और नहीं बन पाता… तो संगठन से बाहर आ जाएँ। दुनिया के विकसित देश ह… यहाँ के विशाल बाजार को पाने के लिए हमारी बातों… मानेंगे। परंतु इसके लिए राजनेताओं में इच्छा शक्ति… अभाव दिख रहा है।

अंत में इस सम्मेलन में स्वदेशी जागरण मंच, जमशे… ने वैश्वीकरण एवं उदारीकरण से बढ़ती बेरोजगारी, उद्यो… की दिन-दिन बिगड़ती दशा, प्रचार तंत्रों से फै… अपसंस्कृति, पेटेंट कानून के दोष, डम्पिंग, मात्रात्मक प्रति… हटाए जाने के खतरों, कृषि पर विश्व व्यापार संगठन… गिद्ध दृष्टि इत्यादि विषयों को केंद्र बनाकर प्रस्ताव पा… किया गया और सरकार से माँग की गई कि –

१. कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं कारीगर क्षेत्र में उत्पा… वस्तुओं को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाए तथा… वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया जाए।
२. ७०० से अधिक वस्तुओं पर से अप्रैल में मात्रात्… प्रतिबंध नहीं हटाया जाए तथा विदेशी सामानों… डम्पिंग पर रोक लगायी जाए।
३. कृषि क्षेत्र में सब्सिडी जारी रखी जाए तथा जैविक ह… निर्माण एवं उद्योग को बढ़ावा दिया जाए।
४. शिक्षा में नैतिक मूल्य, सामाजिक तथा राष्ट्… दायित्वबोध एवं संवेदना उत्पन्न करने वाली विषयव… का समावेश हो।

Scanned with OKEN Scanner

विश्व व्यापार संगठन से बाहर आओ : भारतीय मजदूर संघ

श्री हसुभाई दवे,
महामंत्री भा.म.सं.

विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव एवं हस्तक्षेप के कारण देश की सार्वभौमिकता खतरे में पड़ गयी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पाँच दशकों से अधिक समय बीतने तथा नौ पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के बाद भी देश की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है।

विश्व व्यापार संगठन की शोषण परस्त एवं षड्यंत्रकारी नीतियों के दबाव एवं वर्तमान सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण बिगड़ रही देश एवं गरीब जनता की दुर्दशा को ध्यान में रखकर देश की सर्वोच्च श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्रव्यापी संघर्ष की घोषणा की है। सरकार की आर्थिक सुधार के द्वितीय चरण के नाम पर विश्व व्यापार संगठन के नियमों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में सुविधा प्रदान करने के खातिर वर्तमान सरकार किस हद तक जा सकती है इसका ताजा उदाहरण मॉडर्न फूड एवं बाल्को का विनिवेश एवं ७१४ वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंध वापस लेना है।

भारतीय मजदूर संघ ने दिनांक ३, ४ एवं ५ मार्च, २००१ को बड़ौदा में संपन्न अपने केंद्रीय कार्य समिति की ९६वीं बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि राष्ट्रहित, उद्योगहित एवं मजदूरहित का अब अनदेखा नहीं किया जा सकता है एवं दिनांक १६ अप्रैल, २००१ को देश के संसद के समक्ष एक लाख से ज्यादा श्रमिकों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें पूरे देश से भारतीय मजदूर संघ के सभी महासंघों एवं सदस्य यूनियन भाग लेगा।

विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव एवं हस्तक्षेप के कारण देश की सार्वभौमिकता खतरे में पड़ गयी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पाँच दशकों से अधिक समय बीतने तथा नौ पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के बाद भी देश की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। वास्तविकता यह है कि देश के सामान्यजन के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। अधिसंख्य जनता आज भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है। स्वच्छता की बात तो दूर अधिकांश गाँवों में पीने का पानी नहीं है। निरक्षरता की समस्या विद्यमान है एवं स्वास्थ्य को आवश्यकतानुसार ध्यान नहीं दिया जाता है। बेरोजगारी एवं महंगाई सुरसा के मुँह समान लगातार बढ़ रही है।

हालात इतने बदतर हैं कि योजना आयोग इस महत्वाकांक्षी संभावना पर अध्ययन कर रहा है कि आगामी २००२-२००७ के दसवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में ९ प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है या नहीं? जबकि नौवीं पंचवर्षीय योजना में सकल उत्पाद में ५.६ प्रतिशत की ही दर प्राप्त की जा सकी है। सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने के संबंध में हम चाहें कितने महत्वाकांक्षी क्यों न हों, एक गरीब व्यक्ति के लिए जब तक रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की आवश्यकता पूरी नहीं होती, सकल घरेलू उत्पाद का बढ़ना या घटना कोई मानें नहीं रखता। सोवियत रूस के औद्योगिक ढाँचे के महालनावीस सिफारिश पर आधारित हमारी योजनायें, १९८९ में सोवियत रूस के पतन के पश्चात् उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की पश्चिमी मॉडल की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगीं। तद्नुसार १९९० के प्रारंभ के पश्चात् आने वाली प्रत्येक सरकार नई आर्थिक व औद्योगिक नीति का विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय शक्तियों के प्रभाववश अनुमोदन करने लगी।

वास्तविकता यह है कि भारत गैट के पहले अधिवेशन सन् १९४८ में शामिल हुआ तथा १/१/१९४८ से 'गैट' का सदस्य है। आठवें चक्र की वार्ता के पश्चात् भारत ने दूसरे अनुबंध पर अप्रैल १९९४ में हस्ताक्षर किए तथा १/१/१९९५ से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन की शर्तें अविकसित व विकासशील देशों की कीमत पर विकसित देशों के हित के अनुकूल है। दक्षिण एशिया के वे देश जिन्हें 'एशियन टाइगर' कहा जाता था, विश्व व्यापार संगठन को अपनाने के पश्चात् उनकी जो हालात हुई, वह सर्वविदित है। जापान भी इसकी चोट से बच नहीं सका है।

भारत में सन् १९९० के पश्चात् आने वाली प्रत्येक सरकार ने नई आर्थिक/औद्योगिक नीति को

आगे बढ़ाया है जिसके कारण 'संरक्षित अर्थव्यवस्था खुले बाजार पर आधारित अर्थतंत्र' में परिवर्तित हो गया, लेकिन इसके उपरान्त भी किसी प्रकार की सफलता दृष्टिगोचर नहीं हो रही है।

इसके ठीक विपरीत अमीर तथा गरीब के बीच की खाई चौड़ी तथा गहरी हुई है। धनी और धनी हुआ है तथा गरीब और गरीब हुआ है। 'डाउन साइजिंग' की नीति जिसे दुर्भाग्य से 'सही साइजिंग' कहा जा रहा है तथा उद्योगपतियों द्वारा 'स्वैच्छित सेवा निवृत्ति योजना' के माध्यम से पिछले दरवाजे से निकल जानें के कारण बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक सोचनीय हो गई है। श्रम कानूनों में नियोक्ता के पक्ष में आवश्यक परिवर्तन कर 'हायर एण्ड फायर' की नीति को बढ़ावा देने का प्रयत्न जोर-शोर से चल रहा है।

आज समाज के सभी घटकों में एक प्रकार का डर व्याप्त है। कोई नहीं जानता की देश कहाँ जा रहा है। इस परिस्थिति में निम्नलिखित प्रश्न स्वभाविक रूप से उठते हैं –

१. क्या सभी नीतियाँ वास्तव में नई हैं?
२. वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने प्रत्येक सरकार को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय शक्तियों के सम्मुख घुटने टेकने को विवश किया है?
३. विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुसार देश को प्रगति पथ पर आगे ले जाने वाले उपाय स्थापित प्रजातांत्रिक पद्धति के माध्यम से संसद के समक्ष न लाकर अत्यंत गोपनीय ढंग से मान लेने के लिए इन सरकारों को क्यों बाध्य होना पड़ा?
४. विश्व व्यापार संगठन की शर्तों एवं समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् भी वे शर्तें आम जनता को क्यों नहीं बताई गई?
५. जब अमरीका, चीन तथा जापान जैसे देशों के पास अपने कानून हैं जो उन्हें विश्व व्यापार संगठन की उनके देश के प्रतिकूल शर्तें मानने की अनुमति नहीं देते तो ऐसा क्यों है कि हमारी प्रत्येक सरकार विश्व व्यापार संगठन के प्रति इतनी समर्पित है तथा प्रत्येक सुधार को अत्यधिक तेजी से लागू करना क्यों चाहती है?
६. बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने देश में प्रवेश प्रशस्त करने के लिए आयात संबंधी प्रतिबंध तथा आयात कर में छूट क्यों दिया जा रहा है?
७. क्या कारण है कि इन तथाकथित प्रगतिशील तरीकों को कोई भी राजनैतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल नहीं करता है?
८. क्या यह उन राजनैतिक दलों के लिए जिन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर आम जनता का समर्थन प्राप्त किया है, आम जनता की इच्छा, आकांक्षा पर ध्यान न देना उचित है?

बजट : श्रमिक विरोधी

भारतीय मजदूर संघ ने अपनी इस बैठक में बजट का पुरजोर विरोध किया एवं दुख व्यक्त किया। पूर्व की केंद्रीय सरकारें विगत दस वर्षों में मजदूर विरोधी बजट प्रस्तुत करती रही हैं पर थोड़ा धीमें अंदाज में कुछ-कुछ गुनाह का भाव लिए हुए। परंतु वर्तमान सरकार ने खुले तौर पर खुलकर गरीब और श्रमिक पर बजट के माध्यम से हल्ला बोला है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय श्रममंत्री, के अधिकार क्षेत्र का गैर कानूनी तौर पर अतिक्रमण करते हुए और सभी लोकतांत्रिक मर्यादाओं व परंपराओं का उल्लंघन तथा त्रिपक्षीय व्यवस्थाओं की अवहेलना करते हुए श्रम नीति का प्रस्तुतिकरण बजट प्रस्तावों के द्वारा किया है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व मुद्रा कोष, बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं भारत के शासकीय वर्ग में किस सीमा तक अपवित्र गठजोड़ के परिणामस्वरूप अपने देश की सर्वसाधारण जनता व श्रमिकों पर प्रहार की गति तेज हुई है।

कार्यसमिति बैठक ने वर्तमान सरकार को विनिवेश व निजीकरण नीतियों के चलते इसे मूलत: श्रम विरोधी व जनविरोधी करार दिया और कहा कि बजट प्रस्तावों द्वारा आगामी पाँच वर्षों में सरकारी विभागों में दस प्रतिशत श्रमशक्ति में कटौती, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, छ: मंत्रालयों में अविलम्ब डाउन साइजिंग की प्रक्रिया में तेजी, तालाबंदी, छंटनी करखाना बंद के वर्तमान प्रावधानों छूट देकर एक हजार श्रमिक संख्या त बढ़ाना, ठेका श्रमिक को संस्थागत रूप दे एल.टी.सी. पर दो वर्षों के लिए रोक लगा और ऐसे ही अनेक प्रावधानों द्वारा श्रमि विरोधी कदम उठाए गए है।

बैठक में बजट के विषय और स्वा गौर किया गया और भविष्य में गरीबों श्रमिकों पर इसके अपरिहार्य दुष्परिणामों चिंता व्यक्त की गई। यह बजट सेवा मुक्ति नौकरी के प्रति असुरक्षा का भाव, ठे मजदूरी में वृद्धि, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों निजीकरण, कार्य में तेजी विनिवेश, छंट डाउन साइजिंग, लाभ अथवा सहुलियतों कभी, भविष्य निधि एवं लघु बचतों के ब्य दर में कटौती करने के कारण चिंताकारक स्पष्टतया एक ओर गरीबों पर जहाँ आघ किया गया है वहीं दूसरी ओर बहु-राष्ट्र कंपनियों, बड़े पूँजीपतियों को टैक्सों रियायत देकर तथा आयात-निर्यात नीति उनके लिए लाभकारी परिवर्तन किए गए पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस गुलाबी भविष्य तस्वीरें बनाई थी वह इस बजट से धूमिल हैं। वास्तविकता यह है कि गत दस वर्षों आर्थिक स्थिति विकट से विकटतर हुई कटु यथार्थ यह है कि भारतीय अर्थव्यव उत्पादकता में कमी, बेरोजगारी में वृ छंटनी, तालाबंदी और ज्यादा से ज्यादा लो को गरीबी रेखा से नीचे धकेले जाने के का टूट के कगार पर है। कार्यसमिति का अत सुविचारित अभिमत है कि आर्थिक नीति भारतीय आवश्यकताओं व भारतीय क संस्कृति को ध्यान में रखकर जब तक न बनाई जाएंगी तब तक किसी सुधार की आ व्यर्थ है।

कार्यसमिति की बैठक में अत: निर्ण लिया गया कि सरकार उपरोक्त मजदूर गरीब विरोधी बजट प्रस्तावों को तुरंत वापि ले। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि बजट में गरीब विरोधी भाव को जन तक ले जाया जाए। इसके लिए जनजागृ द्वारा उसे संगठनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक पर इन नीतियों के विरुद्ध आगे आने आह्वान किया जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत सर्व सहमति

निर्णय लिया गया कि आगामी १६ अप्रैल को दिल्ली में देशभर के देशभक्त श्रमिकों व नागरिकों की विश्व व्यापार संगठन तथा विश्व मुद्रा कोष द्वारा संचालित आर्थिक नीतियों का विरोध करने के लिए विशाल रैली की जाए। सभी से आह्वान किया गया कि भारी संख्या में रैली में उपस्थित होकर अपनी आवाज इस कदर बुलंद करें ताकि सरकार गलत आर्थिक नीतियाँ बदलने पर विवश हो जाए।

दिनांक १५ मार्च को स्थानीय डिपुटी स्पीकर हाल में पत्रकारवार्ता में भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्री हसुभाई दवेजी ने स्पष्ट शब्दों में सरकार को चेतावनी दी कि सरकार आर्थिक सुधार के नाम पर जल्दीबाजी करने से बाज आए। सरकार का काम मजदूर विरोधी हो गया है एवं वह उद्योगपतियों के हितों की ज्यादा चिंता करती है। श्री दवेजी ने कहा जो विषय श्रम मंत्रालय का है उस विषय में वित्त मंत्रालय का अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं ठेका मजदूर अधिनियमों के साथ छेड़छाड़ असंवैधानिक है क्योंकि संसद द्वारा पहले ही श्रम कानूनों के पुनरावलोकन हेतु एक श्रम आयोग का गठन किया जा चुका है।

विनिवेश के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। इसमें पारदर्शिता का अभाव होता है। लाभ कमा रही सार्वजनिक उद्योगों को ओने-पोने दामों में बेचा जा रहा है एवं मजदूरों से विमर्श तक नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप मजदूरों को आंदोलन करना पड़ता है। बाल्को में मजदूरों का आंदोलन इसी का परिणाम है।

यह पूछे जाने पर कि भामसंघ तो भाजपा की ही संपोषित अंग है। भामसंघ के राष्ट्रीय मंत्री श्री अयरनाथ डोगरा ने कड़े शब्दों में इसका प्रतिवाद किया और कहा कि भारतीय मजदूर संघ किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। उसके लिए राष्ट्रहित, देशहित एवं मजदूरहित सर्वोपरि है। श्री दवे जी ने कहा कि यदि हम भाजपा से संबंध होते तो १६ अप्रैल को वर्तमान सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं करते। सरकार चाहे कोई भी क्यों न हो यदि वह मजदूर विरोधी, राष्ट्र विरोधी कार्य करेगा तो भारतीय मजदूर संघ इसे कतई बर्दास्त नहीं करेगा एवं १६ अप्रैल को संसद पर करीब एक लाख लोगों के सामने मा० दत्तोपंत ठेंगड़ी जी सरकार की इन नीतियों का पर्दाफास करेंगे। ■

लघु क्षेत्र का तथ्यान्वेशी जन-आयोग

बड़ौदा और अहमदाबाद में संपन्न हुई सुनवाई

भूमंडलीकरण की नीतियों और आर्थिक सुधारों के कारण लघु उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन के लिए अक्टूबर, २००० में स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा प्रोफेसर रुद्रदत्त की अध्यक्षता में एक तथ्यान्वेशी जन-आयोग का गठन किया गया था। इस जन-आयोग ने अभी तक देश के १२ प्रमुख औद्योगिक शहरों में सुनवाई संपन्न कर ली है। इसी संबंध में २४ मार्च, २००१ को बड़ौदा में और २५ मार्च, २००१ को अहमदाबाद में आयोग द्वारा सुनवाई संपन्न की गई। जन-आयोग के प्रतिनिधि डॉ. अश्विनी महाजन ने दोनों स्थानों पर इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता की।

बड़ौदा के कार्यक्रम में वहाँ के कोरोगेटिड डिब्बा उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, प्रताप नगर इंडस्ट्रिज एसोसिएशन, बैंक वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं के उपभोक्ताओं के संगठन, बड़ौदा मेटल मर्चेन्ट एसोसिएशन और अन्य कई औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। वित्त, विपणन, कर, श्रम कानून इत्यादि से संबंधित अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर आयोग को बताया गया।

आयोग को बताया गया कि गुजरात औद्योगिक विकास कार्पोरेशन के औद्योगिक क्षेत्र मकरपुरा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैमिकल इंजीनियरिंग, मशीन मैन्युफैक्चरर, मेडिकल संयंत्र और इलैक्ट्रोनिक उद्योगों में से अधिकतर या तो बंद हो चुके है या बंद होने के कगार पर खड़े है। माँग में कमी आई है, भुगतान की समस्याएँ पहले से भयंकर हो गई है, कोई नई परियोजना नहीं लग रही है और जो लग रही है वहाँ पुरानी कोरियाई मशीनें आयात करके काम चलाया जा रहा है। जहाँ पहले कारों को पार्किंग के लिए स्थान नहीं मिलता था वहाँ दूर-दूर तक अब कोई कार नजर नहीं आती। आयोग द्वारा पूछे जाने पर कि क्या सभी उद्योग बंद है तो प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि नहीं कुछ घुट-घुट कर जी रहे हैं।

अहमदाबाद में संपन्न सुनवाई में गुजरात स्टेट प्लास्टिक एसोसिएशन, अहमदाबाद इंजीनियरिंग एसोसिएशन, अहमदाबाद पॉवरलूम ऑनर्स एसोसिएशन, स्माल स्केल स्पिनर एसोसिएशंन गुजरात पॉवरलूम एसोसिएशन, अहमदाबाद साइजिंग एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती, अहमदाबाद के पदाधिकारियों ने भाग लिया। आयोग को बताया गया कि हाल ही में सरकार द्वारा बियरिंग, कपड़ा, स्पीनर्स, प्रोसेसिंग हाऊस सहित १४ वस्तु उत्पादन करने वाले लघु उद्योगों से उत्पाद शुल्क संबंधित छूट वापिस ले लिए जाने के कारण इन उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि हम किसी विदेशी कंपनी की प्रतियोगिता से नहीं डरते बस हमें लेवल प्लेयिंग फील्ड चाहिए। सबसे अधिक विचलित करने वाला तथ्य जो सामने आया वो यह था कि ५००० टन प्लास्टिक वस्तुएँ शून्य आयात शुल्क पर आयात की जा रही है और अब उद्यमी भारत में उत्पादन करने की बजाए चीन और नेपाल और कुछ हद तक बंगलादेश में स्थानांतरित हो रहे हैं। भारी संख्या में लघु उद्यमी अब चीन में अपने उद्योग की संभावनाएँ तलाश करने के लिए जा रहे हैं। ऊषा, आर्पेट, एसेल पैकेजिंग तो केवल कुछ उदाहरण हैं। आर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसरस ने अभी चीन और नेपाल का दौरा कर इस संबंध में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। ■

Scanned with OKEN Scanner

हलचल

आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के विरोध में संसद पर धरना

आज हमारे देश के बाजार को मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विकसित देश अपने बाजारों में हमारा माल आने से रोकने के लिए विश्व व्यापार संगठन में तरह-तरह के संशोधन करवा रहे हैं। ऐसे में हमें अपने देश के लोगों का हित ध्यान में रखते हुए मात्रात्मक प्रतिबंधों को बरकरार रखना चाहिए।

२२ मार्च २००१ को संसद भवन (जन्तर मन्तर) पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाये जाने के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच की केन्द्रीय संचालन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार स्वदेशी जागरण मंच (दिल्ली प्रान्त) ने एक धरने का आयोजन किया। इस धरने को स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री और स्वदेशी जागरण मंच, केन्द्रीय संचालन समिति के सदस्य श्री मुकुन्द गोरे ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि ''वर्तमान बजट विश्व व्यापार संगठन का समर्थन करते हुए बनाया गया है जिसमें अमीरों के लिए तो सुख-सुविधाएँ बढ़ा दी गयी हैं, लेकिन गरीबों को और गरीब बनाने के प्रावधान कर दिये गये हैं। शहरी विकास को बढ़ावा दिया गया है, गाँवों की उपेक्षा की गयी है।'' उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रामीण विकास विरोधी वित्तमंत्री को हट जाना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रामीण विकास विरोधी वित्तमंत्री को हट जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बजट को मजदूर विरोधी करार देते हुए कहा कि ''इस देश में ९८ लाख मजदूर है, जिसमें केवल १३ लाख मजदूर ऐसे हैं जो १००० के ऊपर एक साथ काम कर रहे हैं। और नये बजट में ऐसे प्रावधान किये गये हैं कि उन ८५ लाख मजदूरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।''

उन्होंने कहा कि ''वर्तमान वित्त वर्ष में २ लाख ३१ हजार करोड़ राजस्व वसूल करने की बात कहीं गयी है, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार द्वारा किए गये कर्जों पर ही २ लाख ३८ हजार करोड़ रुपये अदा होंगे। ऐसे में सरकार फिर नये कर्जे लेगी।'' उन्होंने इस धरने को स्वदेशी का विरोध करनेवाले लोगों के खिलाफ संघर्ष कहा।

धरने को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच उत्तर प्रदेश के सह-संयोजक श्री वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि ''भूमण्डलीकरण के बाद देश के हर क्षेत्र में गिरावट आयी है। शिक्षा, समाज, राजनीति, कृषि, लघु उद्योग, रोजगार सबमें गिरावट दर्ज की गयी है। क्या ऐसे में यह प्रासंगिक नहीं कि अब हमें पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में पंजाब हरियाणा बड़े किसान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार के छोटे किसान तक, केरल के नारियल उत्पादक से लेकर हिमाचल के सेब उत्पादक तक सबकी हालत पस्त है और आखिरी ७१५ वस्तुओं, पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटने के बाद स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी इसका सहज अन्दाज लगाया जा सकता है''

धरने को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के संगठक श्री मुरलीधर राव ने कहा कि आज हमारे देश के बाजार को मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विकसित देश अपने बाजारों में हमारा माल आने से रोकने के लिए विश्व व्यापार संगठन में तरह-तरह के संशोधन करवा रहे हैं। ऐसे में हमें अपने देश के लोगों का हित ध्यान में रखते हुए मात्रात्मक प्रतिबंधों को बरकरार रखना चाहिए। जब तक हमारे देश के लोग उनसे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार नहीं हैं, हमें अपने बाजार उनके लिए नहीं खो[लने] चाहिए। इस धरने को स्वदेशी जागरण [मंच] दिल्ली के संयोजक, श्री ईश्वरदास म[हाजन] अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के श्री [...] पप्पा और स्वदेशी जागरण मंच के के[न्द्रीय] कार्यालय प्रमुख श्री सीताराम भारद्वाज [ने] संबोधित किया।

मंच का संचालन स्वदेशी जागरण [मंच] दिल्ली प्रांत के सह-संयोजक, डा. [...] महाजन ने किया। इस अवसर पर स्व[देशी] जागरण मंच ने सरकार के सामने एक चा[र सूत्री] मांग पत्र भी रखा जो निम्नलिखित है-

स्वदेशी जागरण मंच मांग करता है कि-

१. ३१ मार्च, २००१ को मात्रात्मक [प्रतिबंध] न हटाये जायें। बल्कि हमारी कृ[षि,] लघु उद्योगों के हितों की सुरक्षा और [...] बढ़ा हमारी खाद्य सुरक्षा के लिये [...] और कृषि सम्बन्धी उत्पादों औ[र] उद्योगों के उत्पादों पर मात्रात्मक [प्रतिबंध] तुरन्त लगाये जाये।

२. सरकार यह स्पष्ट घोषणा करे कि [विश्व] व्यापार संगठन में राष्ट्र की खाद्य सुर[क्षा,] आत्मनिर्भरता के साथ कोई समझौ[ता नहीं] किया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन [के जो] प्रावधान गरीबी और भूख के उन्मूल[न,] लघु कुटीर उद्योगों के संरक्षण के [...] आयेंगे, उन्हें किसी भी हालत में स्वीका[र नहीं] किया जाएगा।

३. असंतुष्ट जनता के धैर्य की परीक्षा [...] न ले तथा शीघ्रातिशीघ्र ऐसे कदम उठा[ये] जिसके कारण देश की आर्थिक स्वतंत्र[ता एवं] संप्रभुता अक्षुण्ण बनी रहे।

४. स्वदेशी जागरण मंच अपने पूर्व के [...] को दोहराता है कि यदि सरकार विश्व [व्यापार] संगठन में भारत के हितों के सं[रक्षण में] असफल रहती है तो विश्व व्यापार [संगठन] से बाहर आने हेतु आवश्यक कार्य[वाही] जाये और इस हेतु जनमानस तैया[र करने] के लिये पहल करे।

■ स्वदेशी [...]

भारतीय आई. टी. विशेषज्ञ अमेरिका में सड़कों पर

एक तरफ पूरे भारत में आई टी क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं एवं विशेषज्ञों को अमेरिका में रोजगार मिलने का स्वप्निल चित्र मन में रहता है। हर आई टी प्रशिक्षित व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है कि उसे अमेरिका में नौकरी का अवसर प्राप्त हो। लेकिन अमेरिका में आये इस क्षेत्र में भारी मंदी के कारण न केवल भारत से अमेरिका जाने को उत्सुक लोगों पर तुषारपात हुआ है। अपितु वहाँ पहले से कार्यरत सूचना तकनीक विशेषज्ञ एक-एक कर कंपनी से हटाये जा रहे हैं। इन विशेषज्ञों की एक भारी तादाद सड़कों पर बेकार घूम रही है। ज्ञातव्य हो कि भारतीय विशेषज्ञों का अमेरिका जाना वैश्वीकरण के अच्छे परिणामों में शुमार किया जाता है लेकिन आज अमेरिका में व्याप्त मंदी के कारण स्टाफ में कटौती हो रही है तो सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है जो बेकार हो गये हैं। अब वैश्वीकरण के पक्षधर इस बेईमान एवं पक्षपातपूर्ण रवैये को किस प्रकार देखते हैं यह उनके सोच की कसौटी भी होगी। यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर जिन भारतीयों को नौकरी से निकाला

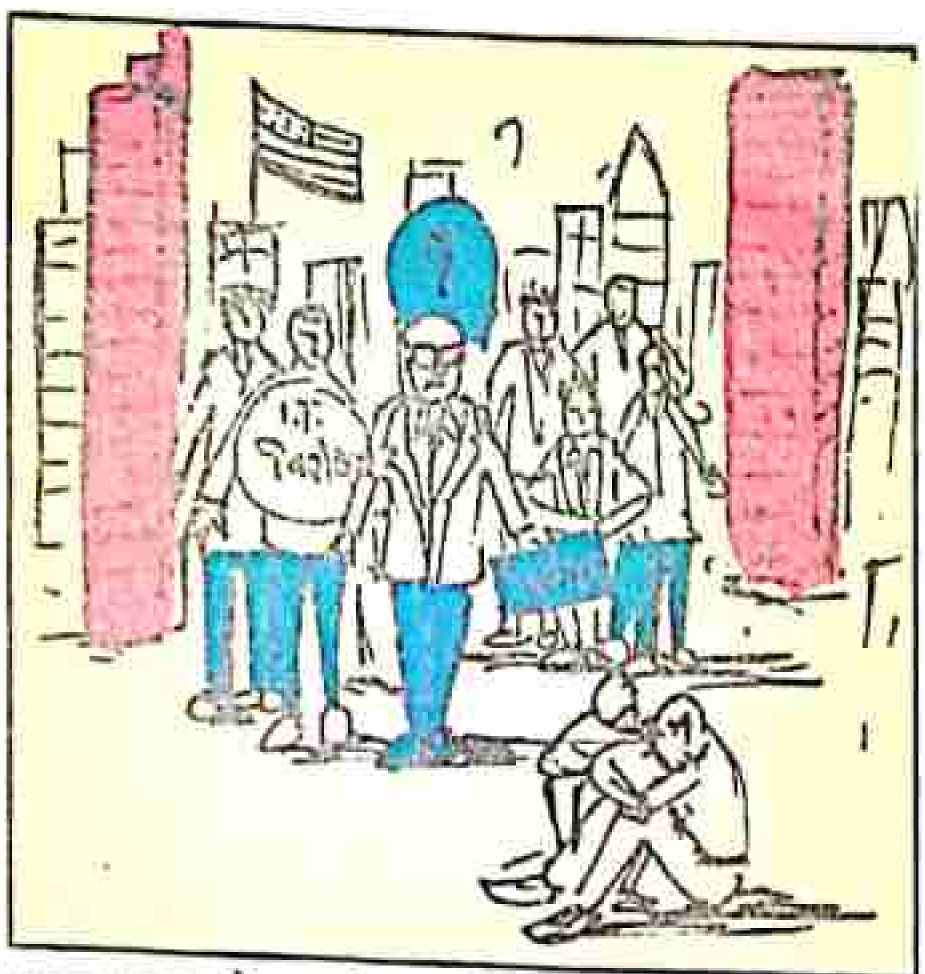

गया क्या वे अयोग्य थे?

अमेरिका के पिट्सबर्ग में एक कंपनी है जिसका नाम है ऑनलाइनच्वाइस डॉट कॉम। इस कंपनी ने पिछले छह महीनों के भीतर तीन बार स्टाफ में कटौती की है। इस बार यह कटौती का पचास प्रतिशत के करीब है। इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसको पूंजी का अभाव बताते हैं। डेल कम्प्यूटर ने जहाँ १७०० लोगों की छँटनी की है वहीं लुसेंट कंपनी ने भारी घाटे की वजह से १०,००० लोगों को बाहर कर दिया है। मोटोरोला ई-कॉमर्स बिजनेस एवं अल्टाविस्टा ने क्रमश: ४०००, ३०० एवं २०० लोगों को निकाल बाहर किया है। विश्व व्यवस्था में सबसे उदारीकृत एवं खुली बाजार नीति अपनाने वाले अमेरिका में हालात यह है कि नौकरी से छुट्टी करने के लिए केवल २४ घंटे की पूर्वसूचना दी जाती है। कोई औपचारिकता नहीं कोई श्रम विधान का झमेला नहीं। इस डावाँडोल वातावरण में अगर कुछ राहत की बात है तो वह है वीसा की अवधि जो ६० दिन तक बेरोजगार हुए लोगों को कम से कम अन्य नौकरी खोजने का समय प्रदान करता है।

अगर आप वहाँ अच्छे से अच्छे फर्म में काम कर रहे हैं एवं गृह-प्रेम, देश प्रेम या अपने लोगों से मिलने भारत आएं तो वापस नहीं जाना क्योंकि वह नौकरी तब तक समाप्त कर दी जाती है। भविष्य भी कुछ ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। वहाँ की अमेजन जैसी दिग्गज कंपनी यह बताने में सक्षम नहीं है कल क्या हालात होंगे। अगर अमेरिका में भारतीय विशेषज्ञों का छँटनी का कार्य इसी तरह जारी रहा हो तो भारतीय सूचना तकनीक व्यापार क्षेत्र में तहलका मच सकता है। अत: अमेरिका जाकर सूचना तकनीक विशेषज्ञ की नौकरी चाहते हैं तो कृपया सावधान।

भारतीय सीमेन्ट उद्योग संकट में

भारत में विदेशी सीमेंट कंपनियों के आने से भारतीय सीमेंट उद्योग संकट के दौर में है। यदि विदेशी कंपनियों को भारतीय सीमेंट कारखानों की खरीद परोक नहीं लगाई गई तो देश का सीमेंट उद्योग बंद हो जायेगा।

विदेशी कंपनियाँ भारत में एक के बाद एक सीमेंट कारखाने खरीद रही हैं। टाटा समूह, रेमण्ड और बिरला समूह के कारखाने बिक चुके हैं। उन्होंने बताया कि विदेशी कंपनियों की योजना है कि वह बाहर से लाकर सस्ते दामों में यहाँ सीमेंट की डंपिंग कर देशी सीमेंट उद्योग नष्ट कर बाद में मनमानी कीमतों में सीमेंट बेचेंगी। इससे भारत जैसे गरीब देश के लोगों के लिये घर का सपना दूर की कौड़ी हो जायेगी।

बिल्डरों की लॉबी इस बात का दुष्प्रचार कर रही है कि भारतीय सीमेंट उत्पादक महंगी कीमत में सीमेंट बेच रहे हैं। १९९४ में सीमेंट की कीमत १५० रुपये बैग थी। बीते ६ सालों में सीमेंट उत्पादन के लिये जरूरी डीजल कोयला और बिजली में २२० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अलावा सीमेंट पर लगने वाले प्रशुल्क २५ से ३० प्रतिशत हैं। इससे भी सीमेंट की कीमतों में बढ़ोत्तरी होती है। जिस अनुपात में कर एवं अन्य चीजें बढ़ी हैं उसी अनुपात में भारत में सीमेंट की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। भारत में अन्तरराष्ट्रीय गुणवत्ता की सीमेंट विदेशों की तुलना में कम कीमत पर मिलती है।

एक अनुमान के अनुसार भारतीय सीमेंट उद्योग एक हजार करोड़ रुपये के सालाना घाटे में चल रहा है। इसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। नतीजा कर्जा, गैर निष्पादक संपत्तियों में तब्दील हो रही है और शेयर धारकों का हिस्सा घट रहा हैं देश का सीमेंट उद्योग गंभीर संकट में है। लगभग ३० से ज्यादा कंपनियाँ घाटे में चल रही है। १० से ज्यादा बी.आई.एफ.आर. में चली गई है। अगर सरकार की वर्तमान नीति जारी रही एवं बाजार का यही हाल रहा तो भारतीय सीमेंट उद्योग बीते जमाने की चीज हो जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

मात्रात्मक प्रतिबंध को पूरी तरह हटाए जाने के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत ने
२२ मार्च, २००१ को संसद भवन पर धरना आयोजित किया।

ईश्वर दास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण फाऊंडेशन के लिए कुमार ब्रदर्स प्रिंटिंग प्रेस, नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२ से मुद्रित एवं ६०, नॉर्थ एवेन्यू से